भारतेन्दु शिखर

हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू व उत्तराखंड में प्रसारित

आरएनआई नं. HPHIN/2000/02437 | शिमला | रविवार, 5 जुलाई 2026 | 21 आषाढ़, विक्रमी संवत 2083 | वर्ष 28, अंक 71, कुल पृष्ठ 12 | मूल्य : 5 रुपए | bhartendunewsmedia@gmail.com | 8894677702

न्यूज शॉर्ट्स

वैभव इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर

एजेंसी, मैनेचेस्टर। वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए सबसे कम उम्र में डेब्यू करने

वाले क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने 15 साल 99 दिन की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ पहला इंटरनेशनल मैच खेला। वैभव को तिलक वर्मा ने डेब्यू कैप दी। वैभव ने शेफाली वर्मा और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। शेफाली ने 15 साल 239 दिन और सचिन ने 16 साल 205 दिन की उम्र में भारत के लिए पहला मैच खेला था। भारत ने दूसरे टी-20 में टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया।

संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक

एजेंसी, नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर दी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों के सत्र को स्वीकृति प्रदान की है। सत्र के दौरान राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा, बहस और विधायी कार्य किए जाएंगे। आगामी सत्र को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि हाल के चुनावों के बाद संसद के समीकरणों में बदलाव देखा गया है और कई अहम विधेयक पेश किए जाने की संभावना है।

भारत-नेपाल सीमा पर बढ़ाई गई निगरानी

एजेंसी, पश्चिम चम्पारण (बगहा)। भारत-नेपाल सीमा की सुरक्षा को लेकर गोबरहिया थाना पुलिस ने सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के साथ संयुक्त गश्ती अभियान चलाया। इस दौरान सीमा क्षेत्र में आने-जाने वाले लोगों और वाहनों की सघन जांच की गई तथा संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी गई। गश्ती के दौरान संवेदनशील इलाकों का भ्रमण कर स्थानीय लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस या एसएसबी को देने की अपील की गई। पुलिस अधीक्षक बगहा ने बताया कि तस्करी व अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए इस प्रकार के अभियान नियमित रूप से चलाए जा रहे हैं।

फायरिंग मामला: विधायक राजू को 4 साल की सजा

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 31 दिसंबर 2018 की नववर्ष पूर्व संध्या पर हर्ष फायरिंग में महिला की मौत के मामले में बिहार के विधायक राजू सिंह को चार साल की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जो मृतक महिला के पति को दिया जाएगा। कोर्ट ने 6 जून को राजू सिंह को दोषी करार दिया था, जबकि उनकी पत्नी सहित अन्य आरोपितों को बरी कर दिया गया था। मामले में 2018 में अंबेडकर कॉलोनी मंडी गांव स्थित एक समारोह के दौरान फायरिंग में महिला अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी। कोर्ट ने उन्हें आईपीसी की धारा 304 (भाग 2) और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी माना।

भारत सबसे बड़े ऊर्जा संकट से उबरा : मोदी

कहा- भारत ने ईंधन कीमतों व आपूर्ति को नियंत्रित कर वैश्विक संकट में दिखाई रणनीतिक क्षमता

एजेंसी, बालोतरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण 21वीं सदी का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट पैदा हुआ, लेकिन नए भारत की इच्छाशक्ति, समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी रणनीति, संसाधनों के संतुलित उपयोग और कूटनीतिक ताकत के दम पर देश इस संकट से सफलतापूर्वक बाहर निकल आया।

उन्होंने कहा कि जब दुनिया के कई देश ईंधन संकट और बढ़ती कीमतों से जूझ रहे थे, तब भारत ने पेट्रोल, डीजल और घरेलू रसोई गैस की उपलब्धता तथा कीमतों को नियंत्रित रखा। राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1.06 लाख करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन, लोकार्पण व शिलान्यास के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सार्वजनिक तौर पर कुछ लोग अफवाहें और आशंकाएं फैला रहे थे, तब सरकार दिन-रात हालात संभाले, नीतिगत और कूटनीतिक स्तर पर फैसले लेते रहे तथा संकट से देश को बाहर निकालने में जुटी थी। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों का इतिहास कभी न कभी जरूर

◆ ऊर्जा संकट में भारत ने बढ़ाया आयात दायरा, 40 से अधिक देशों से हुई आपूर्ति

लिखा जाएगा। मोदी ने कहा कि युद्ध के कारण घरेलू एलपीजी, पेट्रोल और डीजल पर बड़ा संकट खड़ा हो गया था। उन्होंने बताया कि भारत की लगभग 60 प्रतिशत एलपीजी आवश्यकता आयात से पूरी होती थी और उसमें से 90 प्रतिशत आपूर्ति खाड़ी देशों से होर्मुज़ मार्ग के जरिए आती थी, जो युद्ध जैसे हालात के कारण लगभग रुक गई।

इसके बाद सरकार ने रिफाइनरियों की क्षमता का बेहतर उपयोग करने का फैसला किया, जिन रिफाइनरियों में पहले अन्य उत्पाद बनाए जाते थे, उन्हें एलपीजी उत्पादन के निर्देश दिए गए और सात दिनों के भीतर घरेलू एलपीजी उत्पादन 35 हजार मीट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़कर 54 हजार मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गया। जिन रिफाइनरियों ने पहले कभी एलपीजी का उत्पादन नहीं किया था, उन्हें भी इसके लिए तैयार किया गया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि रसोई गैस की पूरी मांग का बोझ केवल एलपीजी पर न पड़े। इसके लिए पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन बढ़ाने का अभियान चलाया गया और बहुत कम समय में 11 लाख से अधिक घरों को पीएनजी से जोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार संकट के दौरान घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत दो हजार रुपए तक पहुंच सकती थी, लेकिन सरकार ने इसे 950 रुपए से कम कीमत पर उपलब्ध कराया। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान कच्चे तेल की कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई व आयात के रास्ते भी बाधित हो गए। दुनिया के अनेक देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 40 से 50 प्रतिशत तक वृद्धि हुई तथा कई देशों में ईंधन की राशनिंग करनी पड़ी लेकिन भारत में एक दिन के लिए भी ऐसी स्थिति नहीं आई।

राजस्थान में 1000 मेगावाट बीकानेर सौर परियोजना का किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के पचपदरा में एसजेवीएन की 1000 मेगावाट बीकानेर सौर विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया। यह परियोजना भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है और स्वच्छ ऊर्जा तथा सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में देश की प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है। इस अवसर पर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, तथा राज्य के उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी और डॉ. प्रेम चंद बैरवा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। एसजेवीएन के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक भूपेंद्र गुप्ता सहित कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में भाग लिया।

सरकार ने प्याज की खरीद कीमत 13 फीसदी बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल की

एजेंसी, नई दिल्ली। सरकार ने प्याज की खरीद कीमत 13 फीसदी बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल कर दी है। इससे प्याज किसानों को बेहतर रिटर्न मिलेगा और बफर खरीद मजबूत होगी। नई दरें 4 जुलाई से प्रभावी हो गई है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने शनिवार को जारी बयान में बताया कि केंद्र सरकार ने 'प्राइस स्टेबलाइजेशन बफर' (कीमतों को स्थिर रखने के लिए बनाए गए स्टॉक) के लिए प्याज की खरीद कीमत 13 फीसदी बढ़ा दी है, जो 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। ये नई खरीद कीमत 4 जुलाई से प्रभावी हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार के 'प्राइस स्टेबलाइजेशन बफर' के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नाफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) के जरिए प्याज की खरीद का काम चल रहा है। प्याज खरीद की ये नई कीमत प्याज किसानों को बेहतर आमदनी दिलाएगी और बफर स्टॉक बनाने की कोशिशों में भी मदद करेगी।

केंद्र सरकार ने 17 पाकिस्तानियों समेत 23 और दहशतगर्दों को घोषित किया आतंकवादी

भारतेन्दु संवाददाता, नई दिल्ली। आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत गृह मंत्रालय ने 23 और दहशतगर्दों को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम-1967 (यूएपीए) के तहत आतंकवादी घोषित किया है।

इस कार्रवाई के बाद यूएपीए की चौथी अनुसूची में नामित आतंकवादियों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है। घोषित 23 आतंकवादियों में 17 पाकिस्तानी और छह भारतीय नागरिक हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि इन आतंकवादियों को औपचारिक रूप से नामित किए जाने से उनके वित्तीय नेटवर्क, आवाजाही, भर्ती क्षमता और आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को और मजबूती मिलेगी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आतंकवाद के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' के दृष्टिकोण को

◆ यूएपीए के तहत सूची में शामिल हुए 17 पाकिस्तानी और 6 भारतीय नागरिक

आगे बढ़ाते हुए प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े 23 खूंखार आतंकवादियों को यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, आतंकी हमलों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकवादियों की भर्ती में शामिल रहे हैं। शाह ने कहा कि मोदी सरकार भारत और उसके नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर आतंकी मॉड्यूल को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय के अनुसार घोषित 23 आतंकवादियों में 17 पाकिस्तानी और छह भारतीय नागरिक हैं। सभी वर्तमान में पाकिस्तान अथवा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओके) से भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं।

आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सूचीबद्ध किए गए आतंकवादी

मंत्रालय ने कहा कि इन आतंकवादियों को सूचीबद्ध करने का उद्देश्य उनके आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करना, वित्तीय स्रोतों पर रोक लगाना, भर्ती और आवाजाही की क्षमता को समाप्त करना तथा आतंकवाद के विरुद्ध भारत की कानूनी और सुरक्षा कार्रवाई को और प्रभावी बनाना है।

योगी सरकार का बड़ा फैसला, तीन सदस्यीय विशेष पीठ करेगी अब शासकीय भूमि से जुड़े वादों की सुनवाई

एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में राजस्व प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने की दिशा में लगातार महत्वपूर्ण सुधार कर रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजस्व परिषद ने सार्वजनिक महत्व की भूमि से जुड़े मामलों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए बड़ा निर्णय लिया है। अब आरक्षित श्रेणी की भूमि, शासकीय भूमि, ग्राम सभा, नजूल, निष्क्रांत संपत्ति तथा शत्रु संपत्ति (यदि कोई हो) से संबंधित सभी वादों की सुनवाई तीन सदस्यीय विशेष पीठ (थ्री मेंबर बेंच) द्वारा की जाएगी। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। राजस्व परिषद की अध्यक्ष

अर्चना अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सरकारी एवं सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने, भूमि विवादों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने तथा राजस्व न्याय प्रणाली को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने पर विशेष बल देते रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नई व्यवस्था लागू की गयी है। इसका उद्देश्य इन संवेदनशील मामलों के निस्तारण में पारदर्शिता, न्यायिक गुणवत्ता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। यह व्यवस्था तत्काल लागू कर दी गई है।

इसके तहत लखनऊ एवं प्रयागराज स्थित राजस्व परिषद न्यायालयों में इन श्रेणी के सभी लंबित और नए वाद अब विशेष रूप से गठित तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। नई व्यवस्था के अनुसार आरक्षित श्रेणी की भूमि, शासकीय भूमि, ग्राम सभा, नजूल, निष्क्रांत संपत्ति तथा शत्रु संपत्ति से जुड़े मामलों की सुनवाई अब परिषद की एकल पीठ अथवा सर्किट कोर्ट द्वारा नहीं की जाएगी। इन मामलों पर विशेष रूप से गठित तीन सदस्यीय पीठ सामूहिक रूप से विचार करेगी।

बैंक धोखाधड़ी मामले में रिलायंस कैपिटल के पूर्व सीएफओ अमित गिरफ्तार

एजेंसी, नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) अमित बापना को रिलायंस एडीए ग्रुप से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामलों की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने बताया कि एजेंसी की जांच में सामने आया कि अगस्त 2014 से दिसंबर 2019 तक कंपनी के सीएफओ रहे बापना ने कंपनी की वित्तीय गतिविधियों में अहम भूमिका निभाई और ऐसे ऋणों को मंजूरी दी जो भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से लिए गए उधार की शर्तों के विपरीत थे।

यादविंद्रा गार्डन और टिक्करताल का होगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकास : सीएम सैनी

एजेंसी, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने हरियाणा को राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाने का एक्शन प्लान तैयार किया है। वेड इन इंडिया को गति देते हुए हरियाणा ने पिंजौर में हाईटेक वेडिंग डेस्टिटेशन बनाने का फैसला लिया है।

90 करोड़ रुपए की परियोजना से पिंजौर के ऐतिहासिक यादविन्द्रा गार्डन और मोरनी के टिक्करताल का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकास किया जाएगा। यहां लग्जरी होटल, हेलिपैड और एडवेंचर सुविधाएं विकसित कर पर्यटन, रोजगार और राजस्व को नई उड़ान देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को पर्यटन विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में पिंजौर के

ऐतिहासिक यादविन्द्रा गार्डन और मोरनी हिल्स के खूबसूरत टिक्करताल को आधुनिक एवं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने के निर्देश दिए हैं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत दोनों प्रमुख पर्यटन स्थलों के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण पर करीब 90 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। सरकार की इस पहल से न केवल हरियाणा में पर्यटन को नए पंख मिलेंगे, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और राज्य के राजस्व में भी भारी बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'वेड इन इंडिया' विजन के अनुरूप यादविन्द्रा गार्डन के समीप आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक भव्य 'वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर वेडिंग' विकसित करने को कहा है, जिससे पर्यटन विभाग को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति हो सके।

राम मंदिर में दान गिनती के नियम बदले कर्मियों के लिए जेब रहित ड्रेस अनिवार्य

एजेंसी, लखनऊ। राम मंदिर के दान काउंटिंग सिस्टम में सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। काउंटिंग हॉल में अब कर्मचारियों को सख्त सुरक्षा व्यवस्था और दोहरी जांच (डबल चेकिंग) के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, काउंटिंग कर्मचारियों के लिए अब नया ड्रेस कोड लागू किया गया है। कर्मचारियों को बिना किसी जेब (पॉकेट) वाली डार्क ब्लू रंग की ड्रेस पहनना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही काउंटिंग हॉल में प्रवेश से पहले प्रत्येक कर्मचारी को दो चरणों की सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। वहीं, काउंटिंग का कार्य अब कुर्सी-मेज पर नहीं, बल्कि जमीन पर बैठकर कराया जाएगा। मोबाइल फोन, कैमरा, बैग और अन्य निजी सामान काउंटिंग हॉल के अंदर ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। कर्मचारियों को काउंटिंग हॉल में प्रवेश से पहले जूते-

◆ मोबाइल फोन, कैमरा, बैग व अन्य निजी सामान काउंटिंग हॉल के अंदर ले जाने पर प्रतिबंध

चप्पल भी बाहर ही उतारने होंगे। इस बीच, राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला लगातार नए खुलासों के साथ सुर्खियों में बना हुआ है।

इस मामले में आरोपी अनुकल्प मिश्रा को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक, अनुकल्प मिश्रा के नाम पर मंदिर में 'व्यवस्था कार्यकर्ता' के तौर पर एंट्री पास जारी किया जाता था। आरोप है कि मंदिर में होने वाले हर विशेष कार्यक्रम के दौरान अनुकल्प मिश्रा के नाम से एंट्री पास बनाया जाता था। दावा किया जा रहा है कि इसी व्यवस्था कार्यकर्ता वाले पास के जरिए उसे मंदिर परिसर में प्रवेश मिलता था। आरोप यह भी हैं कि इसी पास के आधार पर वह चढ़ावे की राशि की गिनती की प्रक्रिया में शामिल होता था।

2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की सीटें घटेंगी : सीएम सुक्खू

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वर्ष 2027 के हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक दावा किया है।

उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव में

भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा समय से कम विधायक चुनकर आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र में 'मिशन रिपीट' जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती और यह जनता तय करती है कि सरकार किसकी बनेगी। दिल्ली से लौटने के बाद शनिवार को शिमला में कांग्रेस कमेटी की बैठक में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पार्टी की बैठक काफी महत्वपूर्ण रही। उन्होंने कहा कि बैठक में भाजपा के आरोपों का जनता के बीच किस तरह जवाब देना है और राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे को लोगों

◆ कांग्रेस बैठक में रणनीति तय, भाजपा के आरोपों का जवाब देने पर मंथन

तक किस प्रकार पहुंचाना है, इस पर चर्चा हुई और आगे की रणनीति तैयार की गई। किन्नौर में मंत्री जगत सिंह नेगी और जिला कांग्रेस अध्यक्ष निगम भंडारी के बीच कथित मतभेद के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच कोई मनमुटाव नहीं है। उनके अनुसार, जगत सिंह नेगी ने केवल अपने विचार रखे हैं। विचार अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब आपसी विवाद नहीं होता। उन्होंने कहा कि जगत सिंह नेगी प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और निगम भंडारी यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं। दोनों नेताओं के साथ बैठकर बातचीत की जाएगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी। जगत सिंह नेगी ने पार्टी आलाकमान पर कोई सवाल नहीं उठाया है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल में एक पद खाली है और उसे भरना जरूरी है। उन्होंने कहा कि विस्तार कब होगा, इसका फैसला कांग्रेस आलाकमान करेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि यदि मौसम अनुकूल रहा तो 16 और 17 जुलाई को धर्मशाला में कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक होगी। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि मौसम की स्थिति को देखते हुए बैठक के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम सभी के आराध्य हैं। उन्होंने याद दिलाया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। उन्होंने कहा कि भगवान के नाम पर चंदे में गड़बड़ी करने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाना चाहिए और इस मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

एथेनॉल के विरोध पर सरकार बोली यह जांची-परखी साइंटिफिक प्रोसेस

एजेंसी, नई दिल्ली। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने को लेकर हो रहे विरोध के बीच शनिवार को सरकार ने कहा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग का काम रातों-रात नहीं हुआ। यह एक जांची-परखी, साइंटिफिक और स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस है। इसे पेट्रोल में मिलाने की ग्लोबल प्रैक्टिस अपनाई है और टॉप एजेंसियां भी इसका टेस्ट कर चुकीं हैं।

एथेनॉल ब्लेंडिंग पर दिल्ली में हुई इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की ओर से शामिल एक्सपर्ट वर्तिका शुक्ला ने यह बात कही। वर्तिका शुक्ला ने बताया कि देश में साल 2013 और 2014 के दौरान पेट्रोल में सिर्फ 1.5% एथेनॉल मिलाया जा रहा था, अब इस प्रोग्राम के तहत पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की जा रही है। 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को तय समय से पांच साल पहले यानी दिसंबर 2025 तक ही पूरा

◆ इसे पेट्रोल में मिलाने की ग्लोबल प्रैक्टिस अपनाई, टॉप एजेंसियां भी टेस्ट कर चुकीं

कर लिया गया है। भारत में 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल के इस मिश्रण यानी E20-पेट्रोल का विरोध हो रहा है। खासकर 2023 से पहले बनी पेट्रोल गाड़ियों के मालिक परेशान हैं। उनका दावा है कि इस फ्यूल से गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा, मेंटेनेंस का खर्च बढ़ गया और इंजन के पार्ट्स जल्दी खराब हो रहे हैं। हालांकि, भारत सरकार का कहना है कि एथेनॉल से माइलेज में मामूली कमी जरूर आती है, लेकिन इससे गाड़ी का पिकअप और इंजन परफॉर्मेंस बेहतर होता है। एक्सपर्ट शुक्ला ने बताया कि विशेष रूप से साल 2018 में एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को एक स्ट्रक्चर्ड यानी व्यवस्थित तरीके से सभी स्टेकहोल्डर्स के सामने चर्चा और विचार-विमर्श के लिए रखा गया था।

आयोजन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश से 'सेवा पखवाड़ा' के दूसरे चरण का किया शुभारंभ, बोले-

सरकार जन-जन के द्वार, हर पात्र तक पहुंचेगा योजनाओं का लाभ

एजेंसी, ऋषिकेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को ऋषिकेश से 'सेवा, सुशासन एवं समर्पण-जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' सेवा पखवाड़ा अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री के रूप में पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस अभियान का उद्देश्य सरकार और आमजन के बीच समन्वय को और अधिक सुदृढ़ बनाना तथा जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार सेवा, सुशासन और समर्पण की भावना के साथ कार्य कर रही है। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक नागरिक को

सरकारी योजनाओं का लाभ सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध हो।

उन्होंने कहा कि सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के लिए स्वयं लोगों के बीच पहुंच रही है, जिससे आमजन को अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। मुख्यमंत्री ने बताया कि सेवा पखवाड़ा के तहत प्रदेशभर में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में विभिन्न विभागों की सेवाएं और योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा। स्वास्थ्य, आयुष्मान भारत योजना, पेंशन, राजस्व, समाज कल्याण, कृषि, स्वरोजगार सहित कई विभागों की सेवाएं शिविरों के माध्यम से आमजन तक पहुंचेंगी। साथ ही जनसमस्याओं का मौके पर पंजीकरण किया जाएगा तथा उनके त्वरित और समयबद्ध निस्तारण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारी शिविरों में मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, किसानों, युवाओं तथा जरूरतमंद परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष अभियान भी संचालित किए जाएंगे। पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विभागीय स्तर पर विशेष प्रयास किए जाएंगे, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी सुविधाओं से वंचित न रहे।

योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा पखवाड़ा के दौरान स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर, पौधरोपण, स्वच्छता अभियान और जनजागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य जनभागीदारी को बढ़ावा देने के साथ-साथ सामाजिक उत्तरदायित्व और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान प्रदेश के सभी जनपदों में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। सरकार और जनता के बीच सीधे संवाद के माध्यम से लोगों की समस्याओं का प्रभावी समाधान किया जाएगा तथा शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लक्ष्य को साकार किया जाएगा।

सीएम ने विकास कार्यों का लोकार्पण व मुनक नहर का किया निरीक्षण

सरकार जलभराव व सीवरेज समस्या के स्थायी समाधान के लिए विकसित कर रही आधुनिक अवसंरचना : रेखा गुप्ता

एजेंसी, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र एवं पीतमपुरा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के साथ-साथ अनेक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुविधाओं का निरीक्षण किया।

इस दौरान उन्होंने पार्कों के सौंदर्यीकरण, आधुनिक जल निकासी व्यवस्था, सीवरेज प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं, सिंचाई इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी शिक्षा संस्थानों में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अपने दौरे की शुरुआत पीतमपुरा स्थित बीडी-एफडी

पार्क में विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्यों के लोकार्पण से की। इस अवसर पर पार्क में लगाए गए 93 नए इलेक्ट्रिक पोल एवं आधुनिक लाइट व्यवस्था का भी शुभारंभ किया गया।

इसके बाद मुख्यमंत्री ने शालीमार बाग क्षेत्र में वर्षा जल निकासी व सीवरेज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) द्वारा तैयार की गई विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इनमें डीटी मॉल से सीए ब्लॉक तक दोनों ओर प्रीकास्ट ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण, सीए ब्लॉक से शालीमार विलेज चौक अंडरपास, आरयूबी से जीटी करनाल रोड (आजादपुर मंडी गेट) और शालीमार चौक से डीए ब्लॉक तक आधुनिक जल निकासी प्रणाली का निर्माण शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार नागरिकों को जलभराव एवं सीवरेज संबंधी समस्याओं से स्थायी राहत दिलाने के लिए आधुनिक और दीर्घकालिक अवसंरचना विकसित कर रही है।

तय समय में पूरा होगा कांग्रेस संगठन विस्तार अभियान : रजनी पाटिल

राजीव भवन में हुई आम सभा, बूथ से पंचायत तक मजबूत ढांचा बनाने पर जोर, मासिक बैठकों को अनिवार्य करने के निर्देश

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल ने पार्टी नेताओं से प्रदेश में संगठन विस्तार और मजबूती के लिए एकजुटता के साथ कार्य करने का आह्वान किया है।

उन्होंने कहा कि संगठन विस्तार अभियान तय सीमा में पूरा किया जाना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की आम सभा, जर्नल हाउस की बैठक में मुख्यातिथि शिरकत करते हुए रजनी पाटिल ने कहा कि सभी ब्लॉकों में ब्लॉक ,जोन व पंचायत कमेटियों का भी जल्द गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस व जोन की मासिक बैठक आवश्यक की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन बैठकों की रिपोर्ट पीसीसी के माध्यम से एआइसीसी को भी भेजी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस भी पदाधिकारी को जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई हैं, उस पर उन्हें खरा उतरना होगा। रजनी पाटिल ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस के अपने कार्यलय भवन हो इसके प्रयास भी किए जाने चाहिए। रजनी पाटिल ने कहा कि देश में हो रहें युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़, नीट पेपर लीक जैसे मामले बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि श्रीराम के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा अयोध्या के दान पात्र,चंदा हजारों करोड़ रुपए की लूट पर पूरी तरह खामोश है। उन्होंने कहा कि यह देश ही नही अपितु विश्व के सब लोगों की आस्था पर डाका डाला गया है। लोगों को इस आस्था की लूट,युवाओं के साथ हो रहें अन्याय के खिलाफ जागरूक करना होगा। आम सभा की इस बैठक को लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री विनोद जिंटा,अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव,प्रदेश मामलों के सह प्रभारी चेतन चौहान, विदित चौधरी ने संबोधित किया। सभा मे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी ब्लॉक व जिला अध्यक्षों ने भी अपनी अपनी बात रखी व उनके क्षेत्रों में संगठन की गतिविधियों की जानकारी दी।

भाजपा के भ्रष्टाचार को वह पूरे तथ्यों के साथ उजागर करेंगे : सुक्खू

मुख्यमंत्री सुक्खू ने सभा को संबोधित करते हुए मीडिया या सोशलमीडिया में विपक्ष व विरोधियों द्वारा प्रदेश सरकार के खिलाफ किसी भी झूठ या दुष्प्रचार का मुंहतोड़ जवाब देने का पार्टी पदाधिकारियों का आह्वान करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियों व जन कल्याणकारी निर्णयों को जन जन तक पहुंचाएं। सुक्खू ने साफ किया कि पूर्व में भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार को वह पूरे तथ्यों के साथ उजागर करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने की दिशा में उनकी सरकार ने महत्वपूर्ण कार्य किए है। सुक्खू ने कहा कि अब प्रदेश चुनावी मोड़ पर आ रहा है। सरकार अपनी सभी गारंटियों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में चुनावी रणनीति बनाई जाएगी।प्रदेश में जल्द ही कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित होंगे। सभी कार्यकर्ताओं के साथ वह सीधा संवाद करेंगे। उन्होंने पार्टी के सभी पदाधिकारियों से सच्चे मन से एकजुट होकर संगठन का कार्य करने का आह्वान भी किया।

कांग्रेस के पास भाजपा के खिलाफ बहुत मुद्दे : मुकेश अग्निहोत्री

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सभा में कहा कि प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अभी से तैयार होना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास भाजपा के खिलाफ बहुत मुद्दे है। भाजपा प्रदेश की हितेषी नही है। कांग्रेस ने अपने कर्मचारियों को ओपीएस देकर एक इतिहास रचा है,जबकि भाजपा ने केंद्र से मिलने वाले फंड जो प्रदेश का हक्क है उसे रुकवा दिया है। उन्होंने कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों का आह्वान किया कि सभी एकजुट होकर कार्य करें।

प्रदेश में संगठन विस्तार अभियान को तेज किया जाएगा : विनय कुमार

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि प्रदेश में संगठन विस्तार अभियान को तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले ही दिन शिमला में भाजपा के 300 से अधिक सक्रिय कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का हाथ थामा है। उन्होंने दावा किया कि इस एक महीने में 8 से 10 हजार लोग कांग्रेस से जुड़ेंगे। विनय कुमार ने जिला व ब्लॉक अध्यक्षों से अपने अपने जिलों व ब्लॉकों में 1 तारीख से 10 तारीख के मध्य नियमित तौर पर बैठके करने व इन बैठकों की पूरी कार्यवाही पीसीसी के कनेक्ट रूम को देने को कहा। विनय कुमार ने कहा कि एक मंत्री को एक जिले का प्रभारी बनाया जाएगा,जिससे वह इन बैठकों में पार्टी कार्यकर्ताओं को सुन सकें।

मेरिट आधारित नियुक्ति के सकारात्मक निर्णय का शिक्षक संघ ने किया स्वागत

◆ सीएम से जल्द अंतिम स्वीकृति देने की शिक्षकों ने की मांग

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई विद्यालयों में मेरिट आधारित नियुक्ति को लेकर कैबिनेट सब-कमेटी द्वारा लिए गए सकारात्मक निर्णय का 'सीबीएसई सब-कैडर इन-सर्विस टीचर्स एसोसिएशन, हिमाचल प्रदेश' ने स्वागत किया है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से आग्रह किया है कि वह इस संबंध में जल्द अंतिम स्वीकृति प्रदान कर नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण करवाएं।

एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष खजान सिंह ठाकुर ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया पर बनी सहमति प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी कदम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री शीघ्र अंतिम निर्णय लेकर लंबे समय से लंबित इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। उनका कहना था कि मेरिट आधारित चयन से योग्य एवं प्रतिभाशाली शिक्षकों को सरकारी सीबीएसई विद्यालयों में कार्य करने का अवसर मिलेगा, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा। उन्होंने 'उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री', शिक्षा मंत्री तथा कैबिनेट सब-कमेटी के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस सकारात्मक पहल से हजारों योग्य शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों की न्यायोचित अपेक्षाओं के पूर्ण होने की आशा जगी है। खजान सिंह ने कहा कि एसोसिएशन उन सभी शिक्षकों की भावनाओं का भी सम्मान करता है, जिन्हें मेरिट आधारित नियुक्ति के कारण अपना वर्तमान कार्यस्थल बदलना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ शिक्षकों को इससे व्यक्तिगत असुविधा हो सकती है । एक शिक्षक का सर्वोच्च दायित्व विद्यार्थियों के हित में कार्य करना है, इसलिए 'व्यापक जनहित में होने वाले ऐसे परिवर्तन को सकारात्मक दृष्टि से स्वीकार किया जाना चाहिए।'

संघ के महासचिव वीरेंद्र कुमार ने मुख्यमंत्री से पुन: आग्रह किया कि वह अपने मेरिट आधारित भर्ती के ड्रीम प्रोजेक्ट को शीघ्र अंतिम स्वीकृति देकर धरातल पर उतारें। उन्होंने कहा कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को सफल बनाने के उद्देश्य से मेरिट सूची में चयनित अध्यापकों ने कठिन परिश्रम, समर्पण और प्रतिस्पर्धा के आधार पर अपना स्थान बनाया है। अगले ही शैक्षणिक सत्र से मेरिट के आधार पर नियुक्त शिक्षक अपने उत्कृष्ट शैक्षणिक परिणामों के माध्यम से सरकार के इस निर्णय को सही सिद्ध करेंगे तथा सीबीएसई बोर्ड में प्रदेश का नाम पूरे देश में गौरवान्वित करेंगे।

वन विभाग ने 8 हजार हेक्टेयर भूमि पर पौधरोपण का रखा लक्ष्य

पहली बार चिनार के पौधे रोपे जाने पर भी दिया जा रहा जोर

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। इस बार के मानसून सीजन में हिमाचल प्रदेश वन विभाग ने राज्य में 7 से 8 हजार हेक्टेयर भूमि पर 50 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से करीब 4 हजार हैक्टेयर भूमि पर राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत पौधे रोपे जाएंगे।

इसके लिए विभाग ने सभी वन मंडल स्तर पर तैयारियां भी शुरू कर दी है। बताया गया कि राज्य के विभिन्न जिलों की भौगोलिक परिस्थितियों एवं संतुलित जलवायु के मुताबिक चिनार और अन्य प्रजातियों के पौधे रोपे जाएंगे। विभाग ने वर्ष 2030 तक मिशन-32 यानी राज्य के हरित आवरण को 32 प्रतिशत तक बढ़ाने के लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प लिया है। इसके मद्देनजर इस बार के वन महोत्सव में प्रदेश के सभी जिलों में पौधरोपण अभियान को सफल बनाने के लिए विभाग ने टारगेट फिक्स किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जाइका वानिकी परियोजना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वन बल प्रमुख डॉ. संजय सूद ने प्रदेश की जनता से पौधरोपण अभियान में सहयोग करने तथा उनके संरक्षण की अपील भी की।

उन्होंने राज्य के सभी वन मंडलाधिकारियों को प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना और राजीव गांधी ग्रीन एडॉप्शन योजना पर बेहतरीन कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सुक्खू ने गत पांच जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शिमला में चिनार का पौधा रोपकर पौधरोपण अभियान का आगाज किया था। उसके बाद 25 जून को भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह सिंधवालिया ने पौधरोपण अभियान का शुभारंभ किया। वन बल प्रमुख डा. संजय सूद ने बताया कि प्रदेश के भिन्न-भिन्न स्थानों पर विशेष पौधरोपण अभियान को सफल बनाने के लिए इस तरह के प्रयास जारी रहेंगे। जाइका वानिकी परियोजना ने 2018 से लेकर 2025 तक 8343 हेक्टेयर भूमि पर भिन्न-भिन्न प्रजातियों के पौधे रोपकर राज्य के 22 वन मंडलों में हरित क्रांति लोने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हर वर्ष की भांति इस बार भी वानिकी परियोजना मिशन-32 के लक्ष्य को सफल बनाने के लिए जन सहभागिता और विभागीय स्तर पर पौधे रोपने के लिए कार्य करेगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना के तहत भी परियोजना ने पिछले साल 124 हेक्टेयर भूमि पर विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपने में सफलता हासिल की। इस वर्ष वन महोत्सव के दौरान प्रदेश में 7 से 8 हजार हेक्टेयर पर चिनार सहित अन्य प्रजातियों के 50 लाख से अधिक पौधे रोपने का लक्ष्य रखा है।

पठानकोट में नहर गेट तोड़ने की साजिश नाकाम, आरोपी पर मामला किया दर्ज

भारतेन्दु संवाददाता, पठानकोट। पठानकोट के गांव डिबकू में नहर के पानी को रोकने के लिए लगाए गए लोहे के गेट को तोड़ने की बड़ी साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया गया। हालांकि, शरारती तत्वों ने गेट के नट-बोल्ट तोड़ दिए थे, लेकिन विभागीय सतर्कता के चलते गेट पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने से बच गया। कार्यकारी अभियंता, नहर एवं भूमिगत जल विभाग, गुरदासपुर द्वारा भेजी गई शिकायत के आधार पर थाना सदर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस ने यह कार्रवाई पंजाब कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट की धारा 52 तथा बीएनएस की धारा 326(ए) और 324(3) के तहत की है। आरोपी की पहचान गांव माहीचक्क निवासी आरिफ हुसैन उर्फ कालू गुज्जर के रूप में हुई है। जांच अधिकारी एएसआई परमजीत शर्मा ने बताया कि गांव डिबकू से शुरू होने वाली गुलपुर एस्केप चैनल के माध्यम से कलानौर, डेरा बाबा नानक और रामदास क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए नहरी पानी उपलब्ध कराया जाता है। यह नहर इन क्षेत्रों की जीवनरेखा मानी जाती है। नहर विभाग के फील्ड स्टाफ की रिपोर्ट में सामने आया कि बुरजी संख्या 9000 के पास लगे भारी लोहे के गेट के नट-बोल्ट किसी व्यक्ति द्वारा तोड़ दिए गए थे। रिपोर्ट के अनुसार यह हरकत गेट को क्षतिग्रस्त करने या चोरी के इरादे से की गई थी। समय रहते विभाग को इसकी जानकारी मिल गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। विभाग ने आशंका जताई है कि यदि गेट टूट जाता तो नहर का पानी अनियंत्रित होकर आसपास के रिहायशी इलाकों और खेतों में फैल जाता, जिससे कलानौर, डेरा बाबा नानक और रामदास क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते थे और जन-धन की भारी क्षति हो सकती थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और जनजीवन को खतरे में डालने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

शिव कथा में शिव-पार्वती विवाहोत्सव की रही धूम

'वसुधैव कुटुंबकम' दुनिया के लिए भारत का शाश्वत संदेश : राज्यपाल

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि 'वसुधैव कुटुंबकम' दुनिया के लिए भारत का शाश्वत संदेश है और सनातन धर्म करुणा, सद्भाव, शांति तथा विश्व बंधुत्व का मार्ग दिखाता है। उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत ही देश की प्रगति की सबसे मजबूत नींव है। राज्यपाल शनिवार को शिमला में दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान की ओर से आयोजित शिव-शक्ति महाकथा और शिव विवाह महोत्सव में शामिल हुए।

इस दौरान उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा-अर्चना कर हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए शांति, समृद्धि, सुख और खुशहाली की कामना की। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि ऐसे आध्यात्मिक आयोजन भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं को सहेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उन्होंने कहा कि सनातन धर्म केवल एक धर्म नहीं, बल्कि जीवन जीने की ऐसी पद्धति है, जो मानवीय मूल्यों पर आधारित है। इसके आदर्श आज भी पूरी दुनिया को शांति और साथ मिलकर रहने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त परिवारों से एकल परिवारों की ओर बढ़ना समाज में स्वाभाविक बदलाव है। फिर भी इस बदलाव के बीच परिवारों में प्रेम, आपसी सम्मान, भावनात्मक जुड़ाव और संवाद कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। उनके अनुसार परिवार की मजबूती का आधार यही मूल्य हैं। राज्यपाल ने युवाओं में बढ़ती नशे की समस्या पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए कानून का सख्ती से पालन जरूरी है, लेकिन बच्चों को अच्छे संस्कार देना सबसे प्रभावी उपाय है। उन्होंने अभिभावकों से अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताने, उनसे खुलकर बात करने, उनका विश्वास जीतने और उन्हें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक परंपराओं से जोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समाज के सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि भारत की सांस्कृतिक परंपराएं, पारिवारिक मूल्य और आध्यात्मिक विरासत आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचती रहें।

कांग्रेस की गारंटियां निकलीं खोखली, महिलाएं आज भी 1500 का इंतजार कर रही : बलदेव

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता बलदेव तोमर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी शिमला दौरे पर हैं, लेकिन प्रदेश की जनता विशेषकर 28 लाख महिलाएं कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान दी गई 1500 प्रतिमाह की गारंटी का जवाब मांग रही हैं।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बड़े-बड़े वादे किए, लेकिन आज तक उन्हें पूरा नहीं किया। प्रदेश में केवल झूठे वादों और प्रचार की राजनीति हो रही है उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री भी कांग्रेस की इस बैठक में उपस्थित हैं। तोमर ने कहा कि उपमुख्यमंत्री ने चुनावों के दौरान प्रदेश के युवाओं को 5 लाख स्थायी नौकरियां देने का वादा किया था और कहा था कि आउटसोर्स नहीं, बल्कि नियमित रोजगार दिया जाएगा, लेकिन आज प्रदेश का युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में रोजगार देने के दावे पूरी तरह विफल रहे हैं और कांग्रेस सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतरी। बलदेव तोमर ने कहा कि दूसरी ओर पंचायतीराज संस्थाओं में भारतीय जनता पार्टी को लगातार जनता का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जिला परिषद और बीडीसी चुनावों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों का लगभग 80 प्रतिशत स्थानों पर कब्जा है। इसके साथ ही प्रदेश के अधिकांश पंचायतों में भी प्रधान और उपप्रधान के रूप में भाजपा समर्थित उम्मीदवार विजयी होकर सामने आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने और चुनाव टालने के अनेक प्रयास किए, लेकिन जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा के पक्ष में अपना स्पष्ट जनादेश दिया। उन्होंने कहा कि यह परिणाम प्रदेश की जनता के कांग्रेस सरकार से मोहभंग और भाजपा की नीतियों एवं संगठन पर बढ़ते विश्वास का प्रमाण हैं।

मजबूत सामाजिक ताने-बाने से भारत बनेगा विश्वगुरु : डॉ. सिकंदर कुमार

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने कहा है कि भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए केवल तकनीकी और आर्थिक प्रगति पर्याप्त नहीं है।

इसके साथ राजनीतिक व्यवस्था में पारदर्शिता, मजबूत सामाजिक ताना-बाना और समाज की एकजुटता भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश के सामने मौजूद राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों का समाधान सरकार अकेले नहीं कर सकती। इसके लिए पूरे समाज की भागीदारी जरूरी है। प्रोफेसर सिकंदर कुमार शनिवार को मंडी में भाजपा जिला मंडी की ओर से आयोजित 'पंडित दीन दयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान' के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण संगठन की कार्यप्रणाली की आत्मा है। किसी भी मजबूत संगठन के निर्माण में प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रशिक्षण से कार्यकर्ता वैचारिक रूप से परिपक्व, अनुशासित और संगठन के प्रति अधिक जिम्मेदार बनते हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत तकनीकी और आर्थिक क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके साथ देश के सामने कुछ गंभीर आंतरिक चुनौतियां भी हैं, जिन पर समान

▶ कहा-राजनीतिक व सामाजिक चुनौतियों के समाधान में समाज की भागीदारी आवश्यक

रूप से ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने राजनीति के अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, क्षेत्रीय और संकीर्ण राजनीति तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता से जुड़े सवालों को देश के सामने बड़ी चुनौतियां बताया। प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने कहा कि समाज में जातिवाद, सांप्रदायिकता, बढ़ती आर्थिक असमानता, महिलाओं की सुरक्षा, लैंगिक असमानता और शिक्षा व स्वास्थ्य के बढ़ते बाजारीकरण जैसे मुद्दे भी चिंता का विषय हैं। उनका कहना था कि इन चुनौतियों का समाधान समाज के सामूहिक प्रयास से ही संभव है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे 'मैं' की भावना छोड़कर 'हम' की सोच के साथ काम करें। उनके अनुसार, जब समाज जाति, धर्म और संकीर्ण सोच से ऊपर उठकर एक भारतीय के रूप में एकजुट होगा, तभी देश अंदर से मजबूत बनेगा और दुनिया में अग्रणी भूमिका निभा सकेगा। समारोह में उन्होंने कार्यकर्ताओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

शिमला वन वृत्त में सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों के अस्थायी पुनर्नियोजन के लिए आवेदन आमंत्रित

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। मुख्य अरण्यपाल, शिमला वन वृत्त द्वारा सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों (नायब तहसीलदार, कानूनगो व पटवारी) से एक वर्ष की अवधि के लिए अस्थायी पुनर्नियोजन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं जिसकी अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित की गई है। वन विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि 8 रिक्त पदों के तहत शिमला वन वृत्त में सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार का एक पद, शिमला वन मंडल (ग्रामीण) में सेवानिवृत्त पटवारी का एक पद, ठियोग वन मंडल में सेवानिवृत्त कानूनगो व पटवारी के एक-एक पद, रोहड़ू वन मंडल में सेवानिवृत्त कानूनगो का एक पद व सेवानिवृत्त पटवारी के दो पद तथा चौपाल वन मंडल में सेवानिवृत्त पटवारी के एक रिक्त पद को भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों की सेवाएं शिमला वन वृत्त के अंतर्गत वन भूमि की पैमाइश, अतिक्रमण प्रकरणों से संबंधित राजस्व एवं विधिक कार्यों के निष्पादन के लिए ली जाएंगी। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र, विस्तृत नियम व शर्तें मुख्य अरण्यपाल, शिमला के कार्यालय से 15 जुलाई, 2026 तक प्रत्येक कार्य दिवस में प्रात: 10 से सायं 05 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं और निर्धारित तिथि (15 जुलाई) तक आवेदन को पूर्ण रूप से भरकर मुख्य अरण्यपाल, शिमला के कार्यालय जमा करवा सकते हैं। 15 जुलाई के उपरांत प्राप्त और अपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

हिमकेयर योजना को खोखला बनाकर सरकार ने गरीबों के इलाज पर लगाया ताला : बिक्रम

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। पूर्व उद्योग मंत्री एवं भाजपा नेता बिक्रम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने हिमाचल की सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा योजना हिमकेयर को पूरी तरह खोखला कर दिया है।

टांडा मेडिकल कॉलेज में लागू की गई नई अधिसूचना इस बात का प्रमाण है कि सरकार अब गरीब, मध्यम वर्ग और जरूरतमंद मरीजों से स्वास्थ्य का अधिकार भी छीन रही है। बिक्रम ने कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन आज स्थिति यह है कि हिमकेयर कार्ड हाथ में होने के बावजूद मरीजों को अपनी जेब से हजारों रुपये खर्च करने पड़ेंगे। सरकार ने दवाइयों की रिइम्बर्समेंट बंद कर दी, एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्स-रे, लैब जांच जैसी आवश्यक सुविधाओं को भुगतान योग्य बना दिया और भर्ती के बाद मिलने वाली मुफ्त दवाइयों की सुविधा भी समाप्त कर दी। इससे साफ है कि कांग्रेस सरकार गरीबों की नहीं बल्कि उनकी जेब पर डाका डालने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बार-बार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के दावे करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को इलाज के बजाय बिल थमाया जा रहा है। जिन लोगों ने इस उम्मीद में हिमकेयर कार्ड बनवाए थे कि गंभीर बीमारी की स्थिति में आर्थिक सहायता मिलेगी, आज वही लोग सबसे अधिक ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।

बिक्रम ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पहले प्रदेशवासियों पर टैक्सों का बोझ बढ़ाया, बिजली-पानी महंगा किया और अब इलाज भी महंगा कर दिया। प्रदेश का आम नागरिक आखिर जाए तो जाए कहां? सरकार की हर नीति जनता की जेब काटने वाली साबित हो रही है। स्वास्थ्य जैसी संवेदनशील व्यवस्था में भी सरकार ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई, बल्कि गरीबों के अधिकारों पर कैंची चला दी।

एचपीयू में बीएड परीक्षा की तारीख बदलने की मांग

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) में बीएड के विद्यार्थियों ने परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव की मांग उठाई है।

स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) की हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई ने विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक (सीओई) से मुलाकात कर इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। एसएफआई का कहना है कि विश्वविद्यालय की ओर से जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार बीएड द्वितीय सेमेस्टर का 'असेसमेंट एंड लर्निंग' विषय का पेपर 17 जुलाई 2026 को होना है। वहीं बीएड चौथे सेमेस्टर का 'इन्क्लूसिव स्कूल' विषय का पेपर 18 जुलाई 2026 को निर्धारित किया गया है। एसएफआई के अनुसार इन्हीं दो दिनों यानी 17 और 18 जुलाई को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की ओर से सीएसआईआर राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (सीएसआईआर-नेट) भी

आयोजित की जा रही है। एसएफआई ने कहा कि बीएड के कई विद्यार्थियों ने जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) और असिस्टेंट फेलोशिप के लिए सीएसआईआर-नेट परीक्षा में आवेदन किया है। ऐसे में दोनों परीक्षाएं एक ही तारीख पर होने से विद्यार्थियों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है।

ज्ञापन में कहा गया है कि यदि परीक्षा कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया तो विद्यार्थियों को अपनी विश्वविद्यालय की परीक्षा या राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षा में से किसी एक को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। संगठन का कहना है कि कई विद्यार्थियों के सीएसआईआर-नेट परीक्षा केंद्र शिमला से बाहर बनाए गए हैं। इस वजह से एक ही दिन दोनों परीक्षाओं में शामिल होना संभव नहीं है।

एसएफआई ने विश्वविद्यालय प्रशासन से बीएड परीक्षाओं की शुरुआत की तारीख आगे बढ़ाने या जिन विषयों की परीक्षा सीएसआईआर-नेट से टकरा रही है, उन्हें किसी दूसरी तारीख पर आयोजित करने की मांग की है। संगठन ने कहा कि समय रहते निर्णय होने से विद्यार्थी बिना किसी अतिरिक्त तनाव के दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे।

आयोजन कोलकाता में नव निर्वाचित विधायकों का प्रबोधन कार्यक्रम, कुलदीप सिंह पठानिया ने साझा किए विचार

प्राइवेट मेंबर बिल विधायी बहस व नीति निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम : पठानिया

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददता, शिमला। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर व असेंबली हाउस में 3 व 4 जुलाई, 2026 को आयोजित दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल विधान सभा के नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय लोकतंत्र शोध व प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड) द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने विधायी कार्यों और प्राइवेट मेंबर बिल की भूमिका पर विस्तार से अपने विचार साझा किए। अपने संबोधन में पठानिया ने कहा कि आंकड़े स्वयं यह दर्शाते हैं कि आजादी के बाद से संसद में पेश प्राइवेट मेंबर बिलों में से केवल 14 को ही राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है, जबकि वर्ष 1970 के बाद दोनों सदनों से कोई प्राइवेट बिल पारित नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि 17वीं

लोकसभा में कुल 729 प्राइवेट बिल पेश किए गए, जिनमें से केवल दो पर ही चर्चा हो सकी। उन्होंने कहा कि यह स्थिति विधायी प्रक्रिया में गहन मंथन और गंभीर चर्चा की आवश्यकता को दर्शाती है। पठानिया ने स्पष्ट किया कि प्राइवेट मेंबर (निजी सदस्य) वह सदस्य होता है, जो मंत्री पद पर नहीं होता और ऐसे सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयक को प्राइवेट बिल कहा जाता है। उन्होंने कहा कि भले ही बहुत कम प्राइवेट बिल कानून का रूप ले पाते हैं, लेकिन उनका महत्व केवल कानून बनने तक सीमित नहीं है। ये बिल महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने, बहस शुरू करने, जनमत निर्माण और सरकार को नीतियों पर पुनर्विचार के लिए प्रेरित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। कई बार महत्वपूर्ण सुधारों की शुरुआत भी इन्हीं प्राइवेट बिलों से होती है, जिन्हें बाद में सरकारी कानूनों में शामिल कर लिया जाता है। उन्होंने कहा कि विधायी प्रक्रिया केवल औपचारिक कदमों की श्रृंखला नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक माध्यम है जिसके जरिए लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को अधिकारों और दायित्वों में बदला जाता है।

उन्होंने बताया कि नीति निर्माण, विधेयक प्रारूपण, बहस, समिति जांच, संशोधन और अंतिम मंजूरी जैसे हर चरण का उद्देश्य कानून की गुणवत्ता को बेहतर बनाना होता है, जो वर्षों के संसदीय अनुभव से विकसित हुआ है। नव निर्वाचित सदस्यों को संबोधित करते हुए पठानिया ने कहा कि उन्हें इस महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा बनने का अवसर मिला है।

उन्होंने कहा कि सदन में प्रस्तुत हर विधेयक शासन व्यवस्था को सुधारने का अवसर होता है, जबकि हर प्राइवेट मेंबर बिल सार्वजनिक नीति में नए विचार जोड़ने का माध्यम बन सकता है। उन्होंने सभी विधायकों से आग्रह किया कि वे जिज्ञासा, संवैधानिक निष्ठा और जनहित के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि एक विधायक की वास्तविक विरासत उनके कार्यकाल या भाषणों की संख्या से नहीं, बल्कि उन कानूनों की गुणवत्ता, बहस की गंभीरता और लोकतांत्रिक संस्थाओं में उनके योगदान से तय होती है। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने सभी नव निर्वाचित सदस्यों के सफल विधायी करियर की शुभकामनाएं दीं और विश्वास जताया कि उनका कार्य पश्चिम बंगाल विधानसभा की संसदीय परंपराओं को और सुदृढ़ करेगा।

समिति प्रणाली सुधार रिपोर्ट को मिली मंजूरी

कार्यक्रम के बाद पीठासीन अधिकारियों की समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें समिति प्रणाली की समीक्षा से संबंधित प्रारूप प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिया गया। सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर कर इसे अनुमोदित किया। बाद में आयोजित सांस्कृतिक संध्या के दौरान समिति सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को प्रारूप प्रतिवेदन की हस्ताक्षरित प्रति भेंट की। लोकसभा अध्यक्ष ने रिपोर्ट स्वीकार करते हुए समिति के सभापति और सदस्यों को समयबद्ध और चरणबद्ध कार्य पूरा करने के लिए धन्यवाद दिया।

न्यूज ब्रीफ

जसपुर में सरकारी भूमि पर बना अवैध मजार ध्वस्त, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

भारतेंदु संवाददाता, जसपुर। उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जिले की जसपुर तहसील के अहमदनगर क्षेत्र में सरकारी भूमि पर निर्मित एक अवैध मजार को प्रशासन ने शनिवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के तहत ध्वस्त कर दिया। प्रशासन का कहना है कि संबंधित पक्ष को पूर्व में नोटिस जारी कर भूमि और निर्माण से जुड़े वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके बाद राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम की मौजूदगी में कार्रवाई की गई।

अगस्त्यमुनि में मिनी मैराथन संपन्न, युवाओं ने दिखाया उत्साह

भारतेंदु संवाददाता, रुद्रप्रयाग। सेवा, सुशासन एवं समर्पण के तहत मनाए जा रहे सेवा सप्ताह के अवसर पर शनिवार को अगस्त्यमुनि क्रीड़ा मैदान में बालक एवं बालिका वर्ग की मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बालक वर्ग में सचिन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि बालिका वर्ग में दिव्या विजेता रहीं। प्रतियोगिता के समापन पर विजेताओं को सम्मानित किया गया तथा सभी प्रतिभागियों को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत शपथ भी दिलाई गई।

हरिद्वार में किसान सम्मेलन के दौरान डांस शो पर उठे सवाल

भारतेंदु संवाददाता, हरिद्वार। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन (अनाज क्रांति) द्वारा आयोजित किसान महाकुंभ में महिला डांसरों का डांस करते हुए वीडियो सामने आया है। जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। वीडियो हर की पौड़ी के सामने स्थित वीआईपी घाट का बताया जा रहा है। जिसमें भारतीय किसान यूनियन (अनाज क्रांति) द्वारा आयोजित किसान महाकुंभ में महिला डांसरों के फिल्मी गीतों पर प्रस्तुति दे रही हैं। कार्यक्रम में मौजूद लोगों द्वारा नोट भी उड़ाए गए। वीडियो सामने आने के बाद बवाल मचा हुआ। धार्मिक संगठनों ने इसे हरिद्वार की मर्यादा के खिलाफ बताते हुए कार्रवाई की मांग की है।

रुड़की में नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास का आरोपी गिरफ्तार

भारतेंदु संवाददाता, हरिद्वार। हरिद्वार पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रयास के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार, 3 जुलाई को कोतवाली रुड़की में एक व्यक्ति ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि ग्राम जबरदस्तपुर निवासी हसन पुत्र मकसूद ने उसके नाबालिग पुत्र का अपहरण कर उसे डरा-धमकाया तथा उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। तहरीर के आधार पर कोतवाली रुड़की में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक अंशु चौधरी को सौंपी गई।

कश्यप घाट पर चला विशेष स्वच्छता अभियान, 38 कट्टे सूखा कचरा एकत्रित

भारतेंदु संवाददाता, हरिद्वार। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशानुसार शनिवार को ऋषिकुल चौक स्थित कश्यप घाट पर विशेष स्वच्छता एवं गाजर घास उन्मूलन अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य घाट क्षेत्र को स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाना तथा आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना रहा। अभियान में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की प्रेरणा से नगर निगम हरिद्वार, आईटीसी मिशन सुनहरा कल तथा श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम ने संयुक्त रूप से श्रमदान किया। इस दौरान घाट परिसर और आसपास फैले कचरे की व्यापक सफाई की गई तथा गाजर घास का उन्मूलन कर क्षेत्र को स्वच्छ बनाया गया। स्वच्छता अभियान के दौरान 38 कट्टे सूखा कचरा एकत्रित कर वैज्ञानिक निस्तारण के लिए नगर निगम हरिद्वार को सौंपा गया। साथ ही गाजर घास हटाकर पर्यावरण संरक्षण और जनस्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक किया गया।

राज्यपाल-सीएम ने ऋषिकेश में 'सेवा पखवाड़ा' का किया शुभारंभ

देहरादून की 219 करोड़ रुपए की 51 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास

◆ सेवा और समर्पण के साथ जन जन तक पहुंच रही सरकार

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) एवं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को आईडीपीएल ग्राउंड, ऋषिकेश में आयोजित 'सेवा, सुशासन एवं समर्पण: जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए प्रदेशवासियों को संबोधित किया। इस अवसर पर राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने देहरादून जनपद की 219 करोड़ से अधिक लागत की 51 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने कहा कि यह अभियान लोकसेवा, सुशासन और जनकल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतीक है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की वास्तविक सफलता तभी है, जब शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े प्रत्येक नागरिक तक सम्मान, संवेदनशीलता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पहुंचे। राज्यपाल ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री के रूप में पांच वर्ष से अधिक समय तक दायित्व निभाने की उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि जनता के विश्वास, लोकतांत्रिक स्थिरता और विकास की निरंतरता का प्रतीक है राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखण्ड ने पिछले वर्षों में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अनेक ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी निर्णय लिए हैं। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य बना, जिसने समानता, न्याय और सामाजिक समरसता की भावना को सुदृढ़ किया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के हितों की रक्षा के लिए सशक्त नकल विरोधी कानून, जबरन धर्मांतरण और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी प्रावधान तथा प्रभावी भू-कानून जैसे निर्णय जनहित और सुशासन के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

राज्यपाल ने कहा कि राज्य की विकास यात्रा में महिलाओं, युवाओं, किसानों और सीमांत क्षेत्रों के नागरिकों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, स्वयं सहायता समूहों के सशक्तीकरण तथा 'लखपति दीदी' जैसी योजनाओं को महिला सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

राज्यपाल ने कहा कि केदारनाथ एवं बदरीनाथ धाम के पुनर्विकास कार्य, पर्यटन और होमस्टे योजना के विस्तार, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, जी-20 बैठकों, राष्ट्रीय खेलों तथा आधारभूत संरचना परियोजनाओं ने उत्तराखण्ड को विकास और निवेश के नए केंद्र के रूप में स्थापित किया है।

युवाओं के सशक्तिकरण पर सरकार का विशेष जोर

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज से पांच वर्ष पूर्व उन्हें देवभूमि उत्तराखण्ड की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ था और यह यात्रा जनसेवा, सुशासन एवं समर्पण की भावना के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। उन्होंने इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए प्रदेश की जनता का विश्वास, स्नेह एवं आशीर्वाद ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के लिए यह अवसर उत्सव का नहीं, बल्कि आत्ममंथन एवं जनसेवा के संकल्प को और अधिक मजबूत करने का है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य वर्ष 2035 तक उत्तराखण्ड को विकसित एवं श्रेष्ठ राज्य बनाना है। इसी उद्देश्य से प्रदेश में आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, कृषि, पर्यटन, उद्योग, निवेश, स्वरोजगार एवं सीमांत क्षेत्रों के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित कर रही है। नई स्टार्टअप नीति, एक जनपद-दो उत्पाद, होमस्टे योजना, सौर स्वरोजगार योजना सहित अनेक योजनाओं के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।

'लखपति दीदी' अभियान को मिलेगी गति

हरिद्वार में खुला प्रदेश का पहला 'हिलांस' आउटलेट

◆ स्थानीय उत्पादों को मिला नया बाजार मंच

भारतेंदु संवाददाता, हरिद्वार। उत्तराखंड में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की ओर से तैयार स्थानीय उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने की दिशा में हरिद्वार में प्रदेश का पहला 'हिलांस' रिटेल आउटलेट उपभोक्ताओं के लिए शनिवार को खोल दिया गया।

ग्रामोत्थान (रीप) परियोजना और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के सहयोग से स्थापित इस आउटलेट का शुभारंभ शाम उद्घाटन रीप की राज्य परियोजना निदेशक झरना कामठान ने किया। रिटेल आउटलेट में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की ओर से तैयार स्थानीय खाद्य उत्पाद, पारंपरिक हस्तशिल्प, जैविक उत्पाद, मसाले, मिलेट आधारित खाद्य सामग्री, हस्तनिर्मित वस्तुएं और उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान से जुड़े विभिन्न उत्पाद उपलब्ध कराए गए हैं। इससे महिला समूहों को अपने उत्पादों के विपणन के लिए स्थायी मंच मिलेगा, वहीं उपभोक्ताओं को स्थानीय उत्पाद एक ही स्थान पर आसानी से मिल सकेंगे।

इस मौके पर झरना कामठान ने कहा कि 'हिलांस' रिटेल आउटलेट महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार स्वयं सहायता समूहों को बाजार उपलब्ध कराने, उनकी आय बढ़ाने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन कर रही है। उन्होंने कहा कि 'लखपति दीदी' अभियान के तहत हजारों महिलाओं को सफल उद्यमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और यह आउटलेट उस लक्ष्य को गति देगा।

झरना कामठान ने दिखाई हरी झंडी

उन्होंने कहा कि हरिद्वार देश-विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों का प्रमुख केंद्र है। ऐसे में यहां स्थापित यह आउटलेट उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रीप के जिला परियोजना प्रबंधक संजय सक्सेना ने बताया कि प्रदेश के पहले 'हिलांस' रिटेल आउटलेट का संचालन श्रद्धा महिला स्वायत्त सहकारिता की ओर से किया जाएगा। कार्यक्रम में हरिद्वार के मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री धामी को 5 वर्ष पूरे होने पर दी बधाई

◆ ऋषिकेश क्षेत्र के विकास को लेकर प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष रखे

भारतेंदु संवाददाता, ऋषिकेश। ऋषिकेश विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकेश में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के सफल 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। इसी क्रम में ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर डॉ. अग्रवाल ने मुख्यमंत्री का ध्यान क्षेत्र की महत्वपूर्ण समस्याओं एवं आवश्यकताओं की ओर आकृष्ट किया है।

उन्होंने क्षेत्र के समग्र विकास हेतु कई प्रमुख मांगें एवं प्रस्ताव रखे हैं, जिनमें मुख्य रूप से— बापूग्राम को पूर्ण राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग, विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा एवं तटबंध निर्माण हेतु बजट स्वीकृति, ऋषिकेश क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, अस्पतालों के उन्नयन एवं आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की स्थापना, क्षतिग्रस्त एवं जर्जर सड़कों के पुनर्निर्माण व सुदृढ़ीकरण के लिए विशेष धनराशिनगर निगम से जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेंट कंक्रीट सड़कों का निर्माणजलभराव की समस्या के स्थायी समाधान हेतु नालों का भू-गर्भीकरणपर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झीलों एवं प्राकृतिक स्थलों का सौंदर्यीकरण.ऋषिकेश को अंतरराष्ट्रीय योग राजधानी के रूप में और विकसित करने हेतु बड़े योग संस्थान की स्थापना। कार्यक्रम के दौरान मंच पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बापू ग्राम वन भूमि प्रकरण पर सरकार द्वारा सकारात्मक फैसला लेने का आश्वासन दिया।

2035 तक विकसित उत्तराखंड हमारा लक्ष्य: महाराज

कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने विकास योजनाओं का किया शिलान्यास

चौबट्टाखाल में सतपाल महाराज का दौरा, सुनीं जनता की समस्याएं

भारतेंदु संवाददाता, पौड़ी। उत्तराखंड सरकार द्वारा 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' थीम पर 15 दिवसीय 'सेवा पखवाड़ा' के तहत प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और चौबट्टाखाल विधायक सतपाल महाराज ने अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मंडल कार्यकर्ता सम्मेलन, सशक्त मंडल सशक्त संगठन के अंतर्गत बैठक और जनसंपर्क कर उनकी समस्याएं सुनने के साथ साथ सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से भी अवगत कराया।

सेवा पखवाड़ा' के तहत प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और चौबट्टाखाल विधायक सतपाल महाराज ने शनिवार को पिनानी, घुड़दौड़स्यू, कोटा, पंचूर, मनकोट और पाटीसैण शक्ति केंद्र के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और जनसंपर्क कर उनकी समस्याएं सुनने के साथ साथ सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से भी जनता अवगत कराया।

इस मौके पर उन्होंने विकास खण्ड पाबौ के अन्तर्गत ग्राम रिंगि में 148.36 लाख की धनराशि से पाबौ-पिनानी-दमदेवल मोटर मार्ग कि.मी.16, 17 व 18 में डामरीकरण, 123.30 लाख की लागत से पाबौ दमदेवल मोटर मार्ग के कि.मी. 32 एवं 33 में सुधारीकरण एवं डामरीकरण और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1583.780 लाख की धनराशि से बनने वाले झगरबौ-सिवाल-पल्ली गांव मोटर मार्ग का शिलान्यास एवं भूमि पूजन करने के साथ-साथ 10 लाख की लागत से ग्राम झंगरबौ में बने पंचायत भवन का भी लोकार्पण किया।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी को मिला नया निदेशक, डॉ. खजूरिया ने संभाला पद

डॉ. आरपी खजूरिया बने आईजीएनएफए के नए निदेशक

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। आंध्र प्रदेश कैडर के 1991 बैच के भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारी, डॉ. राजेंद्र प्रसाद खजूरिया ने गुरुवार को इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी (आईजीएनएफए), देहरादून के निदेशक का पद सँभाला। उन्होंने श्रीमती भारती की जगह ली है, जो 30 जून को सेवानिवृत्त हुईं। इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी के निदेशक के रूप में कार्यभार सँभालने से पहले, वे आंध्र प्रदेश पर्यावरण प्रबंधन निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे।

भारतीय वन सेवा के आंध्र प्रदेश कैडर के 1991 बैच के अधिकारी डॉ. राजेंद्र प्रसाद खजूरिया एक जाने-माने वन विशेषज्ञ और शिक्षाविद् हैं और उनके पास 35 वर्षों से अधिक का कार्य अनुभव है।

वे मूल रूप से जम्मू-कश्मीर के रहने वाले हैं। उन्होंने कनाडा की टोरंटो यूनिवर्सिटी से पीएच.डी. की है और वन प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण तथा नीति निर्माण में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभा चुके हैं। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में कई शोध पत्र भी प्रकाशित किए हैं।

वे एक कुशल एवं योग्य अधिकारी हैं और 'अमृत काल' के उद्देश्यों के अनुरूप भारतीय वन सेवा प्रशिक्षण को उचित आकार देने के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण रखते हैं। निदेशक का पद सँभालने के बाद, उन्होंने आईजीएनएफए के संकाय सदस्यों तथा कर्मचारियों से वार्ता की और अकादमी में चल रहीं विभिन्न गतिविधियों का जायजा लिया।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी का मुख्य उद्देश्य ऐसे सक्षम अधिकारी तैयार करना है जो पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर सकें और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ विकास की प्रक्रिया को संतुलित रख सकें।

पूरी पृथ्वी अमृत है, भारत माता परम अमृत है: बापू

भारतेंदु संवाददाता, हरिद्वार। हरिद्वार में आयोजित रामकथा के पांचवें दिन मुरारी बापू ने कहा कि पूरी पृथ्वी अमृतमयी है और भारत माता परम अमृत का स्रोत है। उन्होंने बताया कि गीता पृथ्वी का अमृत है, जबकि संतों और भद्रपुरुषों के मुख से निकले लोककल्याणकारी वचन ही वास्तविक अधरामृत हैं, जिन्हें कभी बेचा नहीं जाता। बापू ने कहा कि रामचरितमानस प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग रूप में प्रेरणा देता है। किसी के लिए यह महाकाव्य, किसी के लिए महामंत्र, तो किसी के लिए गुरु और ज्ञान का स्रोत है। उन्होंने योग, वियोग, समता, एकाग्रता और पवित्र वातावरण को जीवन का अमृत बताते हुए कहा कि योग से शरीर, मन और आत्मा में दिव्यता का संचार होता है।

रुद्रप्रयाग में 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' कार्यक्रम से ग्रामीणों को मिला योजनाओं का लाभ

◆ जनता तक पहुंची सरकारी योजनाएं

भारतेंदु संवाददाता, रुद्रप्रयाग। जनपद रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि क्रीड़ा भवन में सेवा, सुशासन एवं समर्पण अभियान के अंतर्गत सेवा सप्ताह के तहत 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाना तथा जनता की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित समाधान की दिशा में कार्य करना रहा। कार्यक्रम में जनपद के दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और उन्होंने अपनी समस्याओं, सुझावों एवं मांगों को जनप्रतिनिधियों तथा संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखा इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा क्रीड़ा परिसर में अपने-अपने विभागों से संबंधित स्टॉल लगाए गए थे।

इन स्टॉलों के माध्यम से ग्रामीणों एवं आमजन को राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई।

स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्यान, मत्स्य, पर्यटन, डेयरी, सहकारिता, रीप, बाल विकास, उद्योग, पशुपालन, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, आजीविका, स्वरोजगार सहित कई विभागों ने अपने स्टॉल के माध्यम से योजनाओं, पात्रता और लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

दूर-दराज के क्षेत्रों से आए लोगों ने इन स्टॉलों पर पहुंचकर योजनाओं की जानकारी प्राप्त करते हुए विभिन्न योजनाओं का लाभ भी लिया कार्यक्रम के दौरान सूचना विभाग में पंजीकृत सांस्कृतिक दलों ने आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं।

पिपलिया फार्म विवाद में हाईकोर्ट सख्त एसएचओ को पेश होने के आदेश

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ऊधमसिंह नगर जिले के किच्छा क्षेत्र के पिपलिया मोड़ स्थित कुलसुम खान फार्म पर कथित जबरन कब्जे और वहां रह रहे लोगों की सुरक्षा से जुड़े मामले में सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने इस प्रकरण पर सुनवाई करते हुए संबंधित एसडीएम और एसएचओ को 6 जुलाई 2026 को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होकर जवाब देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही न्यायालय ने पहले से दिए गए सिविल कोर्ट के 11 जून 2026 के आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने को भी कहा है।

यह मामला उस समय सामने आया जब सिकंदर आलम खान ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि पिपलिया मोड़ स्थित कुलसुम खान फार्म पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। याचिका में कहा गया है कि यह संपत्ति उनकी बुआ कुलसुम खान की थी, जिन्होंने 2024 में इसकी वसीयत सायरा और उनके चचेरे भाई सिकंदर आलम खान के नाम कर दी थी। बुआ कुलसुम खान का निधन 18 दिसंबर 2025 को हो गया था, जिसके बाद संपत्ति को लेकर विवाद और अधिक बढ़ गया।

याचिकाकर्ता के अनुसार, जैसे ही दूसरे पक्ष को वसीयत की जानकारी मिली, वे कुछ लोगों के साथ मौके पर पहुंचे और कथित रूप से प्रशासन को मिलीभगत से फार्म हाउस पर कब्जा कर लिया। आरोप है कि इस दौरान वहां मौजूद पुरुष सदस्यों को बाहर कर दिया गया, जबकि महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को परिसर के अंदर ही रोके रखा गया और उन्हें बाहर जाने से भी रोक दिया गया। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि वहां रह रहे लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और वे पिछले कई दिनों से असहज स्थिति में अंदर ही फंसे हुए हैं।

डिजिटलीकरण

अब नहीं होगी परीक्षा केंद्र खोजने की परेशानी, एडमिट कार्ड पर मिलेगा क्यूआर समाधान

यूकेपीएससी ने लॉन्च किया परीक्षा केंद्र प्रबंधन सिस्टम

◆ उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाएं डिजिटल, 200 परीक्षा केंद्र पोर्टल से जुड़े

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब उन्हें परीक्षा केंद्र खोजने के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (यूकेपीएससी) ने भर्ती परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी, आधुनिक और अभ्यर्थी-अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए परीक्षा केंद्र प्रबंधन सिस्टम तैयार किया है। इस नई व्यवस्था के तहत अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड पर एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, जिसे मोबाइल फोन से स्कैन करते ही वे सीधे अपने परीक्षा केंद्र की सटीक लोकेशन तक पहुंच सकेंगे। इससे समय की बचत होगी और परीक्षा वाले दिन केंद्र खोजने में होने वाली परेशानियां भी काफी हद तक समाप्त हो जाएंगी।

यह नई सुविधा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (यूकेपीएससी) और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) दोनों की भर्ती परीक्षाओं में लागू की जाएगी। आयोग का उद्देश्य परीक्षा केंद्रों के चयन, प्रबंधन और संचालन को पूरी तरह डिजिटल बनाना है, ताकि परीक्षा प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी हो सके। इसके लिए अब तक राज्यभर के करीब 200 परीक्षा केंद्रों का पोर्टल पर पंजीकरण किया जा चुका है। भविष्य में आवश्यकता के अनुसार अन्य परीक्षा केंद्रों को भी इस प्रणाली से जोड़ा जाएगा।

आयोग द्वारा तैयार किए गए इस परीक्षा केंद्र प्रबंधन सिस्टम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि किसी परीक्षा केंद्र का पंजीकरण केवल एक बार करना होगा। पहले प्रत्येक नई परीक्षा के लिए केंद्रों का अलग-अलग पंजीकरण करना पड़ता था, जिससे समय और संसाधनों की अधिक आवश्यकता होती थी। अब एक बार पंजीकरण होने के बाद वही केंद्र भविष्य की परीक्षाओं के लिए भी उपलब्ध रहेंगे। इससे आयोग के प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और परीक्षा आयोजन की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सरल और प्रभावी बनेगी।

नई प्रणाली के तहत प्रत्येक परीक्षा केंद्र का वर्गीकरण उसकी बैठक क्षमता, उपलब्ध तकनीकी सुविधाओं, इंटरनेट कनेक्टिविटी, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य आवश्यक संसाधनों के आधार पर किया जाएगा। इससे आयोग परीक्षा की संवेदनशीलता, अभ्यर्थियों की संख्या और परीक्षा की प्रकृति के अनुसार उपयुक्त परीक्षा केंद्रों का चयन आसानी से कर सकेगा। यह व्यवस्था न केवल परीक्षा संचालन को बेहतर बनाएगी बल्कि निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा आयोजित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

इस डिजिटल पोर्टल की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि परीक्षा केंद्रों को सभी जरूरी सूचनाएं स्वतः उपलब्ध कराई जाएंगी। पंजीकरण से लेकर परीक्षा की तैयारियों, उपस्थिति, दिशा-निर्देश और अन्य आवश्यक जानकारी एसएमएस तथा ई-मेल के माध्यम से संबंधित परीक्षा केंद्रों तक स्वतः पहुंच जाएगी। इससे बार-बार अलग से पत्राचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सभी सूचनाएं समय पर संबंधित अधिकारियों तक पहुंच सकेंगी।

चंडीगढ़ में लागू राइट टू बिजनेस एक्ट, निवेशकों को मिली राहत

सिंगल विंडो सिस्टम, डीम्ड अप्रूवल और ऑनलाइन मंजूरियों से निवेशकों को राहत, चंडीगढ़ में उद्योग स्थापना होगी अधिक आसान

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में उद्योग और कारोबार को नई गति देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट, 2020 को आवश्यक संशोधनों के साथ लागू कर दिया है। गृह मंत्रालय (एमएचए) की ओर से 2 जुलाई की देर शाम जारी अधिसूचना के बाद यह कानून तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। प्रशासन का मानना है कि इससे निवेशकों को मंजूरियां लेने की प्रक्रिया पहले से अधिक आसान और समयबद्ध होगी, नियामकीय बाधाएं कम होंगी तथा चंडीगढ़ निवेश और उद्योग के लिए अधिक आकर्षक केंद्र बनकर उभरेगा।

यह निर्णय गृह मंत्रालय और चंडीगढ़ प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया। अधिसूचना पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा-87 के तहत जारी की गई है। इसके तहत पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट के सभी प्रावधानों को चंडीगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप संशोधित किया गया है।

नए कानून के लागू होने से आईटी पार्क, बायोटेक पार्क, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड), औद्योगिक टाउनशिप, ग्रोथ सेंटर, फूड प्रोसेसिंग पार्क तथा चंडीगढ़ प्रशासन या केंद्र सरकार से स्वीकृत अन्य औद्योगिक एवं व्यावसायिक परियोजनाओं को विशेष लाभ मिलेगा। इन परियोजनाओं को विभिन्न विभागों से मंजूरियां प्राप्त करने की प्रक्रिया तेज होगी और उद्योग स्थापित करने में आने वाली प्रशासनिक जटिलताएं काफी हद तक कम होंगी।

इस कानून का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान चंडीगढ़ ब्यूरो ऑफ एंटरप्राइज एंड इन्वेस्टमेंट (सीबीईआई) की स्थापना है। यह ब्यूरो निवेशकों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा और विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करेगा। इसके अलावा निवेश प्रस्तावों पर कार्रवाई, इन-प्रिंसिपल अप्रूवल की प्रक्रिया, शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण तथा नए उद्योगों को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी भी इसी ब्यूरो के पास होगी। ब्यूरो का नेतृत्व चंडीगढ़ प्रशासन के उद्योग सचिव करेंगे, जबकि उद्योग निदेशक अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एडिशनल सीईओ) की भूमिका निभाएंगे।

अधिसूचना के तहत कानून में कई आवश्यक संशोधन भी किए गए हैं। अब जहां-जहां पंजाब सरकार, राज्य सरकार या पंजाब की एजेंसियों का उल्लेख था, वहां उन्हें चंडीगढ़ प्रशासन के अनुरूप परिवर्तित कर दिया गया है। राज्य सरकार का अर्थ अब चंडीगढ़ के प्रशासक से होगा। इसी प्रकार जिला नोडल एजेंसी के स्थान पर चंडीगढ़ ब्यूरो ऑफ एंटरप्राइज एंड इन्वेस्टमेंट तथा पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्थान पर चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति कार्य करेगी। सक्षम प्राधिकारी की परिभाषा का भी विस्तार किया गया है, जिसमें चंडीगढ़ प्रशासन के विभाग, स्थानीय निकाय, वैधानिक बोर्ड, यूटी के स्वामित्व वाले निगम, शहरी विकास प्राधिकरण और अन्य स्वीकृति देने वाली एजेंसियां शामिल होंगी।

कानून की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पात्र उद्योगों और उद्यमों को कारोबार शुरू करने के लिए सभी विभागों से अंतिम मंजूरी मिलने का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

मोहाली एकम सिंह ढिल्लों हत्याकांड में पत्नी सीरत कौर को उम्रकैद की सजा

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली

मोहाली में बहुचर्चित एकम सिंह ढिल्लों हत्याकांड में करीब नौ साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पत्नी सीरत कौर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला 19 मार्च 2017 का है, जिसने उस समय पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी।

जानकारी के अनुसार, 40 वर्षीय ऑटो चालक एकम सिंह ढिल्लों की हत्या बेहद बेरहमी से की गई थी। हत्या के बाद उनके शव को एक छोटे सूटकेस में रखकर फेज-3बी1 इलाके में खड़ी उनकी बीएमडब्ल्यू कार की पिछली सीट पर छिपा दिया गया था। पुलिस जांच में सामने आया कि शव को इस तरह मोड़ा गया था कि वह सूटकेस में फिट हो सके, जिससे घटना की क्रूरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। मौके पर पहुंची पुलिस भी यह दृश्य देखकर हैरान रह गई थी।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि एकम सिंह की मौत गोली लगने से हुई थी। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि हत्या के बाद घर में मौजूद खून के निशान और अन्य सबूतों को मिटाने का प्रयास किया गया था, ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। हालांकि, फॉरेंसिक और तकनीकी जांच ने मामले की परतें खोल दीं।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदीप सिंह की अदालत ने सुनवाई के बाद सीरत कौर को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत आजीवन कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा अदालत ने उसे साक्ष्य मिटाने (धारा 201) और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत भी दोषी ठहराया। इन धाराओं के तहत तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई गई, जो साथ-साथ चलेगी।

न्यूज ब्रीफ

सीबीआई ने हत्याकांड में स्केच किया जारी

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़ । नामधारी संप्रदाय में उत्तराधिकार को लेकर चल रहे विवाद से जुड़े 2011 के बहुचर्चित अवतार सिंह तारी हत्याकांड में सीबीआई ने अब नई कार्रवाई की है। एजेंसी ने इस मामले में एक मुख्य संदिग्ध का स्केच जारी किया है और सूचना देने वाले के लिए 2 लाख रुपये इनाम की घोषणा की है। करीब 15 साल पुराने इस मामले में अब जांच दोबारा तेज कर दी गई है। अवतार सिंह तारी की 12 अप्रैल 2011 को लुधियाना के कटानी कलां इलाके में दिनदहाड़े एके-47 से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमले में उन्हें 11 गोलियां लगी थीं। वे नामधारी संप्रदाय के भीतर चल रहे शक्ति संघर्ष में एक अहम भूमिका निभा रहे थे और उन्हें प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता था। हत्या के पीछे संप्रदाय के अंदर चल रहे उत्तराधिकार विवाद को मुख्य कारण बताया गया था। सीबीआई ने 2017 में केस दर्ज कर जांच अपने हाथ में ली थी, लेकिन अब तक आरोपियों का पता नहीं चल सका है। एजेंसी ने मामले की गोपनीय जानकारी देने की अपील की है।

चंडीगढ़ हत्याकांड में टेरर नेटवर्क का खुलासा

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़ । चंडीगढ़ सेक्टर-11 स्थित श्री कुमार मेडिकल हॉल के कैशियर जानकीदास हत्याकांड की जांच अब अंतरराष्ट्रीय टेरर-क्राइम सिंडिकेट तक पहुंच गई है। 13 जून को हुई इस सनसनीखेज वारदात के बाद चंडीगढ़ पुलिस अब पाकिस्तान से संचालित नेटवर्क, सीमा पार हथियार तस्करी और टेरर फंडिंग के एंगल से जांच कर रही है। जम्मू की जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाए गए मास्टरमाइंड अमित कुमार उर्फ शराबी से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। पुलिस अब घायल शूटर सन्नी और आर्यन के सामने उसे बैठाकर क्रॉस-इंटरोगेशन करेगी। जांच में जर्मनी में बैठे गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों और पाकिस्तानी नेटवर्क के लिंक सामने आए हैं। पुलिस को शक है कि वारदात में इस्तेमाल तुर्की मेड जिगाना पिस्टल पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारत भेजी गई थी। अब स्लीपर सेल और फरार मददगारों की भी तलाश की जा रही है। जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क को खंगाल रही हैं।

हरियाणा ने कॉलेज कैडर के नए नियम जारी

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के अधीन कॉलेज कैडर (ग्रुप-बी) कर्मचारियों के लिए हरियाणा उच्च शिक्षा विभाग, उप-कार्यालय कॉलेज कैडर (ग्रुप-बी) सेवा नियम, 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। नए नियमों के अनुसार सुपरिंटेंडेंट पद पर अब सीधी भर्ती नहीं होगी। यह पद केवल पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण के माध्यम से भरा जाएगा।

पदोन्नति के लिए डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के रूप में कम से कम एक वर्ष या सहायक के रूप में 10 वर्ष का अनुभव अनिवार्य होगा। प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों के लिए स्नातक योग्यता और संबंधित अनुभव जरूरी रखा गया है। इस कैडर में फिलहाल सुपरिंटेंडेंट के 10 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनका वेतनमान पे लेवल-7 (44,900 से 1,42,400 रुपये) होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पदोन्नति वरिष्ठता कम मेरिट के आधार पर होगी। वरिष्ठता का निर्धारण सेवा अवधि के आधार पर किया जाएगा। यदि नियुक्ति एक ही दिन हो तो सीधी भर्ती को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रोबेशन अवधि एक से दो वर्ष की होगी और असंतोषजनक प्रदर्शन पर सेवा समाप्त भी की जा सकती है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी नियुक्तियों में पारदर्शिता और योग्यता को प्राथमिकता दी जाएगी। नए नियमों से प्रशासनिक व्यवस्था अधिक सुदृढ़ होगी और विभागीय कार्यों में दक्षता बढ़ेगी। इससे कर्मचारियों को स्पष्ट करियर प्रगति का मार्ग भी मिलेगा।

सरकार की एल्डरलाइन 14567 हेल्पलाइन बनी बुजुर्गों की सुरक्षा और सहायता का माध्यम

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़।

पंजाब सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण को मजबूत करने के उद्देश्य से 'एल्डरलाइन 14567' हेल्पलाइन को प्रभावी रूप से संचालित किया है। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि यह हेल्पलाइन राज्य के बुजुर्गों के लिए एक भरोसेमंद सहायता केंद्र के रूप में तेजी से उभरी है।

अब तक पंजाब भर से इस हेल्पलाइन पर प्राप्त 2.5 लाख से अधिक कॉलों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया जा चुका है। इसके माध्यम से 91 बेसहारा बुजुर्गों का रेस्क्यू कर उन्हें उनके परिवारों से मिलाया गया है। साथ ही, बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार और भरण-पोषण से जुड़े 1,000 से अधिक मामलों का समाधान भी किया गया है। डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी वरिष्ठ नागरिक स्वयं को असुरक्षित महसूस न करे।

बुजुर्गों की सुरक्षा और जीवन में बड़ा सुधार

इस हेल्पलाइन के माध्यम से अब तक 2.5 लाख से अधिक कॉलों का सफल निस्तारण किया जा चुका है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह सेवा व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंच रही है। इसके जरिए 91 बेसहारा बुजुर्गों को रेस्क्यू कर सुरक्षित रूप से उनके परिवारों से मिलाया गया, जिससे कई परिवारों में फिर से संबंध मजबूत हुए हैं। साथ ही, 1,000 से अधिक मामलों में बुजुर्गों के साथ हुए दुर्व्यवहार और भरण-पोषण संबंधी समस्याओं का समाधान किया गया है। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि बुजुर्ग अब स्वयं को असहाय और उपेक्षित महसूस नहीं करते, बल्कि उन्हें तुरंत सहायता मिलने का भरोसा है। इसके अलावा, वृद्धावस्था पेंशन, कानूनी सहायता और काउंसलिंग जैसी सेवाएं भी आसानी से उपलब्ध हो रही हैं।

चंडीगढ़ हत्याकांड में बड़ी सफलता, स्पेन में आखिरकार दबोचा गया गोल्डी ढिल्लों

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

सेक्टर-11 स्थित मेडिकल हॉल के कैशियर जानकी दास की हत्या के मामले में जांच एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। भारतीय एजेंसियों के सहयोग से स्पेन में गैंगस्टर और इस हत्याकांड के कथित मास्टरमाइंड गोल्डी ढिल्लों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लंबे समय से फरार चल रहा गोल्डी ढिल्लों राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) का वांछित आरोपी भी है। उसकी गिरफ्तारी के बाद अब उसे कानूनी प्रक्रिया पूरी कर भारत लाने की तैयारी की जा रही है, ताकि हत्या, रंगदारी और आपराधिक नेटवर्क से जुड़े मामलों में उससे विस्तृत पूछताछ की जा सके।

सूत्रों के अनुसार, गोल्डी ढिल्लों विदेश में बैठकर पंजाब, चंडीगढ़ और आसपास के राज्यों में अपने आपराधिक नेटवर्क का संचालन कर रहा था। जांच एजेंसियों का आरोप है कि वह अपने साथियों के जरिए कारोबारियों को धमकियां दिलवाता था और उनसे रंगदारी की मांग करता था। उसके खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। फरार रहने के दौरान उसकी गिरफ्तारी पर लाखों रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था।

गौरतलब है कि 13 जून को चंडीगढ़ के सेक्टर-11 स्थित श्री कुमार मेडिकल हॉल में कार्यरत कैशियर जानकी दास की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात उस समय हुई जब वह अपनी ड्यूटी पर मौजूद थे।

हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए थे। इस घटना से पूरे शहर में दहशत फैल गई थी और व्यापारियों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी। हत्या के कुछ समय बाद गोल्डी ढिल्लों ने इस वारदात की जिम्मेदारी लेने का दावा किया था। इसके बाद चंडीगढ़ के कई व्यापारियों को धमकी भरे संदेश भेजे गए और उनसे रंगदारी की मांग की गई। इन घटनाओं के बाद पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी थी। तकनीकी साक्ष्यों और खुफिया सूचनाओं के आधार पर गोल्डी ढिल्लों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही थी।

पीजीआई की टेलीमेडिसिन सेवा से लाखों मरीजों को घर बैठे मिलेगी विशेषज्ञ सलाह

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

देश के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों में शामिल पी.जी.आई. चंडीगढ़ में हर दिन 10 हजार से अधिक मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। लगातार बढ़ती मरीजों की संख्या के कारण अस्पताल की ओपीडी पर दबाव भी लगातार बढ़ रहा है। इस चुनौती से निपटने के लिए पी.जी.आई. ने अपनी टेलीमेडिसिन सेवाओं का दायरा तेजी से बढ़ाया है। इसका लाभ अब लाखों मरीजों को मिल रहा है। अस्पताल प्रशासन का मानना है कि डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से न केवल अस्पतालों पर भीड़ कम होगी, बल्कि मरीजों का समय, पैसा और अनावश्यक यात्रा भी बचेगी।

आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 के दौरान पी.जी.आई. की ओपीडी में 28.58 लाख से अधिक मरीजों ने इलाज करवाया। हर दिन हजारों मरीज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, राजस्थान और अन्य राज्यों से इलाज के लिए पी.जी.आई. पहुंचते हैं। इनमें बड़ी संख्या ऐसे मरीजों की होती है, जिन्हें केवल फॉलो-अप जांच, मेडिकल रिपोर्ट दिखाने या दवाओं में बदलाव कराने के लिए अस्पताल आना पड़ता है। ऐसे मरीजों के लिए टेलीमेडिसिन सेवा किसी वरदान से कम साबित नहीं हो रही।

पी.जी.आई. के टेलीमेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉ. अमित अग्रवाल ने बताया कि पहली बार डॉक्टर से प्रत्यक्ष परामर्श लेने के बाद मरीजों को हर बार अस्पताल आने की आवश्यकता नहीं होगी। फॉलो-अप परामर्श, जांच रिपोर्ट की समीक्षा और आवश्यक मेडिकल सलाह ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। इससे मरीजों को लंबी यात्रा, भीड़ और अतिरिक्त खर्च से राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म के माध्यम से करीब दो लाख स्वास्थ्य संबंधी पूछताछ की जा रही है, जबकि चार लाख से अधिक लोगों को विशेषज्ञों द्वारा स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी जा चुकी है। यह संख्या पिछले कुछ वर्षों की तुलना में लगभग दोगुनी हो गई है।

डॉ. अग्रवाल ने बताया कि जल्द ही पी.जी.आई. और देश के अन्य बड़े सरकारी अस्पतालों, जिनमें एम्स भी शामिल है, में ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म को अस्पताल सूचना प्रणाली (हॉस्पिटल इन्फॉर्मेशन सिस्टम) से जोड़ा जाएगा। इसके बाद मरीज का सीआर नंबर बनने के साथ ही उसे यह विकल्प मिलेगा कि वह अगली चिकित्सकीय सलाह अस्पताल में आकर लेना चाहता है या ऑनलाइन। इससे डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

उन्होंने बताया कि पी.जी.आई. में आने वाले लगभग 50 प्रतिशत मरीज केवल फॉलो-अप के लिए अस्पताल पहुंचते हैं। इनमें से अधिकांश को केवल जांच रिपोर्ट दिखानी होती है, दवा की खुराक में बदलाव कराना होता है या डॉक्टर की सामान्य सलाह लेनी होती है।

भबात-नाभा सड़क बदहाल गड्ढों से लोग रोजाना परेशान

भारतेन्दु संवाददाता, जीरकपुर । भबात और नाभा गांवों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क की बदहाल स्थिति क्षेत्र के हजारों लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गई है। लंबे समय से सड़क पर बने बड़े-बड़े गड्ढों और उखड़ी सतह के कारण वाहन चालकों और राहगीरों को रोजाना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की हालत लगातार खराब होती जा रही है, लेकिन कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन और संबंधित विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

भबात-नाभा सड़क की बदहाली, रोजाना जाम और दुर्घटनाओं का बढ़ा खतरा

स्थानीय निवासियों के अनुसार, यह सड़क भबात, नाभा, विक्टोरिया सिटी, रिवरडेल सोसाइटी और आसपास की कई रिहायशी कॉलोनियों को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। प्रतिदिन हजारों लोग इसी रास्ते से अपने कार्यालय, स्कूल, कॉलेज और अन्य जरूरी कार्यों के लिए आते-जाते हैं। सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे होने के कारण वाहन चालकों को बार-बार ब्रेक लगाने या अचानक वाहन मोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इससे दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना रहता है।

रिवरडेल सोसाइटी के मार्केट के सामने सड़क का हिस्सा सबसे अधिक क्षतिग्रस्त है। यहां बारिश के दिनों में गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे उनकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है।

डेराबस्सी में खुली सिगरेट बेचने वालों पर स्वास्थ्य विभाग की सख्त कार्रवाई

भारतेन्दु संवाददाता, डेराबस्सी

तंबाकू नियंत्रण कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सिविल अस्पताल डेराबस्सी की निगरानी टीम ने शनिवार को शहर में विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान विभिन्न बाजारों और व्यावसायिक क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया, जहां खुले में सिगरेट बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) के तहत कार्रवाई करते हुए चालान काटे गए और जुर्माना वसूला गया।

यह अभियान सिविल सर्जन डॉ. संगीता जैन के दिशा-निर्देशों पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में संचालित किया गया। निगरानी दल में उपनिरीक्षक राजेंद्र सिंह, दलबीर सिंह तथा स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मचारी भी शामिल रहे। टीम ने शहर के प्रमुख बाजारों, दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों सहित कुल 14 स्थानों का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान कई दुकानदार खुले में सिगरेट बेचते हुए पाए गए, जो कोटपा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। टीम ने ऐसे दुकानदारों के मौके पर ही चालान काटे और नियमानुसार जुर्माना वसूला। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भविष्य में यदि कोई दुकानदार खुले में सिगरेट बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ और अधिक सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दुकानदारों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री से संबंधित नियमों की जानकारी भी दी। उन्हें निर्देश दिए गए कि वे अपनी दुकानों पर निर्धारित चेतावनी बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाएं तथा तंबाकू उत्पादों की बिक्री से जुड़े सभी कानूनी प्रावधानों का पालन करें। अधिकारियों ने कहा कि कानून की अनदेखी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि तंबाकू का सेवन कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की गंभीर बीमारियों और अन्य कई जानलेवा रोगों का प्रमुख कारण है। ऐसे में तंबाकू नियंत्रण कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन बेहद आवश्यक है।

महिलाओं से वादाखिलाफी पर भाजपा ने सरकार को घेरा

केवल सिंह ढिल्लों बोले, एक हजार रुपये प्रतिमाह देने का वादा पूरा नहीं कर सकी राज्य सरकार, अन्य कार्यक्रमों पर भी उठाए सवाल

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने राज्य सरकार पर महिलाओं से किए गए चुनावी वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सभी 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये आर्थिक सहायता देने का वादा किया था, लेकिन सरकार अब अपने ही वादे से पीछे हटती नजर आ रही है। इससे महिलाओं में निराशा और असंतोष बढ़ रहा है।

पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के समय आम आदमी पार्टी ने हर पात्र महिला को हर महीने एक हजार रुपये देने की घोषणा की थी। इस वादे के आधार पर लाखों महिलाओं ने सरकार पर भरोसा जताया, लेकिन सरकार बनने के बाद अधिकांश महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल सका।

ढिल्लों ने सवाल उठाया कि यदि राज्य में लगभग सवा करोड़ महिलाएं हैं तो केवल 36 लाख महिलाओं को ही इस योजना का लाभ क्यों दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि बाकी महिलाओं को इस योजना से बाहर क्यों रखा गया है। उनका आरोप था कि सरकार ने चुनावी लाभ लेने के लिए बड़े-बड़े वादे किए, लेकिन उन्हें लागू करने में गंभीरता नहीं दिखाई।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित की जा रही लोक मिलनी सभाओं को भी राजनीतिक दिखावा करार दिया। उन्होंने कहा कि जनता की वास्तविक समस्याओं का समाधान करने के बजाय सरकार प्रचार पर अधिक ध्यान दे रही है। उनके अनुसार, यदि सरकार वास्तव में जनहित के लिए काम कर रही है तो उसे सबसे पहले महिलाओं से किए गए चुनावी वादों को पूरा करना चाहिए।

ढिल्लों ने मांग की कि सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए सभी वादों को समयबद्ध तरीके से लागू करे और महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के योजना का लाभ उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि भाजपा महिलाओं के अधिकारों और उनके हितों के मुद्दे को लगातार उठाती रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेशभर में महिलाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी। यदि सरकार ने जल्द अपने चुनावी वादों को पूरा नहीं किया तो पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से जनआंदोलन चलाकर महिलाओं की आवाज बुलंद करेगी।

आप सरकार पर वादे न निभाने का आरोप

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब की जनता से कई बड़े वादे किए थे। इनमें सबसे प्रमुख वादा 18 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक महिला को हर महीने एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का था। उनका आरोप है कि सरकार बनने के चार वर्ष बाद भी यह वादा सभी पात्र महिलाओं के लिए पूरी तरह लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि आखिर किन मानकों के आधार पर केवल सीमित संख्या में महिलाओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है। ढिल्लों ने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान राज्य में रोजगार बढ़ाने, भ्रष्टाचार खत्म करने, नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई करने, किसानों और व्यापारियों से जुड़े कई मुद्दों का समाधान करने तथा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने जैसे अनेक वादे किए गए थे। उनका आरोप है कि इनमें से कई घोषणाएं अब तक पूरी तरह धरातल पर नहीं उतर सकी हैं।

जालंधर में भाजपा नेताओं ने स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देकर किया नमन

भारतेन्दु संवाददाता,जालंधर

जालंधर में युगपुरुष स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि के अवसर पर शहर के स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ट्रेड विंग पंजाब के उपाध्यक्ष रविंद्र धीर अपने साथियों सहित स्मारक स्थल पर पहुंचे और उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। कार्यक्रम में पार्टी के कई अन्य नेता भी उपस्थित रहे।

इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता रविंद्र धीर ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी का जीवन भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और दर्शन का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने बहुत कम आयु में ही विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन किया और भारतीय अध्यात्म को वैश्विक पहचान दिलाई। उन्होंने आगे कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है और उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे।

कार्यक्रम में उपस्थित अन्य नेताओं ने भी स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनके विचारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से यह सीखा कि सभी जीवों में परमात्मा का वास होता है। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के प्रसार के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया।

स्वामी विवेकानंद ने सन उन्नीस सौ तिरानबे में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व कर पूरी दुनिया को भारतीय दर्शन से परिचित कराया। उनका जन्म बारह जनवरी अठारह सौ तिरसठ को कोलकाता में हुआ था। उन्होंने बाद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर समाज सेवा और अध्यात्म के कार्यों को नई दिशा दी।

रविंद्र धीर ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने मात्र पच्चीस वर्ष की आयु में गृहस्थ जीवन को त्यागकर संन्यास ग्रहण किया और अपना पूरा जीवन देश और धर्म के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका प्रसिद्ध संदेश 'उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए' आज भी युवाओं के लिए मार्गदर्शन का कार्य करता है। उन्होंने यह भी कहा कि स्वामी विवेकानंद का मानना था कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है और भारतीय अध्यात्म के बिना विश्व अधूरा है। इस अवसर पर उपस्थित नेताओं ने कहा कि उनके विचारों को अपनाकर ही समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ाया जा सकता है।

विवेकानंद जी प्रेरणा स्रोत

स्वामी विवेकानंद जी एक महान आध्यात्मिक विभूति थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का विश्व स्तर पर प्रचार किया। उनके विचार आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं और जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करते हैं।

अमृतसर फूड एंड ड्रग विभाग में लंबे कार्यकाल और तैनाती पर उठे सवाल

भारतेन्दु संवाददाता, अमृतसर । अमृतसर में फूड एंड ड्रग विभाग के भीतर अधिकारियों की लंबे समय से एक ही सीट पर तैनाती को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आने वाले इस विभाग में कई अधिकारियों पर आरोप है कि वे तय नियमों के बावजूद वर्षों से एक ही पद पर जमे हुए हैं। सरकारी नियमों के अनुसार किसी भी अधिकारी को एक ही सीट पर तीन साल से अधिक समय तक तैनात नहीं किया जा सकता, लेकिन अमृतसर में इस नियम की अनदेखी के आरोप सामने आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, कुछ अधिकारी तबादले के बाद कुछ समय के लिए दूसरे जिलों में भेजे जाते हैं, लेकिन जल्द ही फिर से अमृतसर लौटकर वही पुरानी सीट संभाल लेते हैं। इस लगातार वापसी ने विभागीय कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आशंका जताई जा रही है कि इसमें सिफारिशों और अंदरूनी मिलीभगत की भूमिका हो सकती है।

◆विभाग में तैनाती विवाद

आरोप यह भी हैं कि कुछ अधिकारी अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अन्य कर्मचारियों के खिलाफ झूठी शिकायतें भी करवाते हैं। कई मामलों में शिकायतों के आधार पर तबादले होते हैं और बाद में वही शिकायतकर्ता अधिकारी उस खाली हुई सीट पर पहुंच जाता है। इससे विभाग के भीतर अस्थिरता और असंतोष का माहौल बन रहा है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक, कुछ अधिकारी सरकारी कामकाज में भी सावधानी बरतने के लिए सीधे बातचीत की बजाय मैसेजिंग ऐप्स और इंटरनेट कॉल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनके संवाद का रिकॉर्ड आसानी से उपलब्ध न हो सके। व्यापारियों और दुकानदारों से संपर्क के तरीके को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

स्थानीय व्यापारी वर्ग और नागरिकों में इस स्थिति को लेकर नाराजगी है। उनका कहना है कि लंबे समय तक एक ही अधिकारी के एक ही क्षेत्र में रहने से निष्पक्ष कार्रवाई की संभावना कम हो जाती है और भ्रष्टाचार की आशंका बढ़ती है। कई लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि पहले भी कुछ अधिकारियों के कामकाज को लेकर शिकायतें सामने आई थीं, लेकिन उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

चन्नी-वड़िंग विवाद से पंजाब कांग्रेस में हलचल

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में बने असंतोष ने पार्टी की राजनीति को नई दिशा दे दी है। मोहाली स्थित चन्नी के आवास पर हुई बड़ी बैठक में सात पूर्व मंत्री, चार विधायक और 68 हलका इंचार्ज शामिल हुए। इस जुटान को केवल संगठनात्मक नाराजगी नहीं, बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले शक्ति संतुलन की बड़ी राजनीतिक लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस घटनाक्रम का असर केवल पंजाब कांग्रेस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राज्य की पूरी राजनीतिक दिशा पर भी पड़ेगा। कांग्रेस लंबे समय से सत्ता से बाहर है और उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती भाजपा, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल से मुकाबले से पहले अपने संगठन को मजबूत करना है। ऐसे समय में शीर्ष नेताओं के बीच असहमति पार्टी के कार्यकर्ताओं में भ्रम और अस्थिरता पैदा कर सकती है।

मोहाली बैठक से पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व संकट गहराया

हालांकि चन्नी गुट ने इस बैठक को संगठन को मजबूत करने की पहल बताया है, लेकिन राजनीतिक संदेश इससे कहीं अधिक बड़ा माना जा रहा है। इतने बड़े स्तर पर नेताओं का एक साथ आना यह संकेत देता है कि असंतोष व्यक्तिगत नहीं बल्कि व्यापक स्तर पर फैला हुआ है। यदि समय रहते इस स्थिति को संभाला नहीं गया तो यह कांग्रेस के लिए बड़ा संगठनात्मक संकट बन सकता है। अब इस पूरे मामले की निगाहें दिल्ली नेतृत्व पर टिक गई हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस हाईकमान को यह तय करना होगा कि मौजूदा प्रदेश नेतृत्व पर भरोसा रखा जाए या संगठन में बदलाव किया जाए।

यदि नेतृत्व को बरकरार रखा जाता है तो असंतुष्ट नेताओं को साथ लेकर चलना बड़ी चुनौती होगी। वहीं अगर बदलाव किया जाता है तो यह संदेश जाएगा कि दबाव की राजनीति सफल हो गई। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि चन्नी की सक्रियता केवल संगठनात्मक बदलाव तक सीमित नहीं है।

गुरदासपुर में बांध दरार से किसानों की डूबी फसलें, प्रशासन पर आरोप

भारतेन्दु संवाददाता,गुरदासपुर

गुरदासपुर में दीनानगर के पास गाहलड़ी हाइडल क्षेत्र के निकट धुस्सी बांध में आई दरार और उसके टूटने की घटना को लेकर विवाद गहरा गया है। इस मामले में किसान नेता हरदेव सिंह चिट्ठी ने पंजाब सरकार और प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि यह घटना किसी प्राकृतिक आपदा का परिणाम नहीं, बल्कि प्रशासनिक उदासीनता और विभागीय अनदेखी का नतीजा है।

हरदेव सिंह चिट्ठी ने कहा कि धुस्सी बांध की स्थिति लंबे समय से कमजोर और जर्जर बनी हुई थी। किसानों और स्थानीय लोगों द्वारा कई बार प्रशासन को इसकी स्थिति के बारे में चेतावनी दी गई थी, लेकिन समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि समय पर मरम्मत और मजबूती का काम किया जाता तो यह स्थिति पैदा नहीं होती।

उन्होंने कहा कि पानी के बढ़ते दबाव के कारण बांध टूट गया, जिससे आसपास के क्षेत्रों में किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है। कई खेतों में पानी भरने से धान और अन्य फसलें प्रभावित हो गई हैं, जिससे किसानों की आजीविका पर सीधा असर पड़ा है। चिट्ठी ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि अब घटना के बाद केवल औपचारिकता निभाई जा रही है और जमीनी स्तर पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही। किसान नेता ने मांग की कि इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किस स्तर पर लापरवाही हुई है।

प्रधानमंत्री मोदी आएंगे जालंधर, कैंट स्टेशन का करेंगे उद्घाटन

भारतेन्दु संवाददाता, जालंधर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री इस महीने के मध्य में पंजाब आ सकते हैं और जालंधर क्षेत्र में एक बड़े कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। रेलवे से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, 13 जुलाई को प्रधानमंत्री के जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। यह स्टेशन केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत आधुनिक रूप में विकसित किया गया है।

सूत्रों का यह भी कहना है कि इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री जालंधर में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। यह रैली राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसे आगामी चुनावी तैयारियों की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, अभी तक इस दौरे को लेकर किसी भी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। रेलवे के महाप्रबंधक ने भी स्पष्ट किया है कि कार्यक्रम का अंतिम शेड्यूल उच्च अधिकारियों के निर्देशों के बाद ही तय किया जाएगा।

प्रधानमंत्री के संभावित दौरे की खबर सामने आने के बाद प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जालंधर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। रेलवे सुरक्षा बल और पंजाब पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्टेशन और रैली स्थल के आसपास सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।

जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन को केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूरी तरह से आधुनिक बनाया गया है। इस योजना का उद्देश्य देशभर के रेलवे स्टेशनों को विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस करना है। स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए नई तकनीक, बेहतर प्रतीक्षालय, उन्नत सुरक्षा प्रणाली और आधुनिक ढांचे का विकास किया गया है।

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री का यह संभावित दौरा पंजाब की राजनीति में महत्वपूर्ण असर डाल सकता है। जालंधर और दोआबा क्षेत्र में इस कार्यक्रम के जरिए पार्टी अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति अपना सकती है। वहीं स्थानीय स्तर पर भी इस दौरे को लेकर लोगों में उत्सुकता देखी जा रही है। प्रधानमंत्री के संभावित दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां लगातार तैयारियों की समीक्षा कर रही हैं। रेलवे और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। स्थानीय नेताओं में भी हलचल तेज है और सभी इस दौरे को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मान रहे हैं।

जीरकपुर पावरकॉम कार्यालय में स्टाफ कमी से उपभोक्ता परेशान

भारतेन्दु संवाददाता, जीरकपुर

जीरकपुर में बिजली उपभोक्ताओं को इन दिनों भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पावरकॉम कार्यालय में कर्मचारियों की भारी कमी और पिछले लगभग डेढ़ महीने से चल रही मीटर रीडर्स की हड़ताल ने पूरी व्यवस्था को प्रभावित कर दिया है। स्थिति यह है कि जहां इस कार्यालय में लगभग चालीस कर्मचारियों की मंजूरशुदा संख्या है, वहीं वर्तमान में केवल दो से चार कर्मचारी ही पूरे कामकाज को संभाल रहे हैं। इसके चलते कार्यालय का दैनिक कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और उपभोक्ताओं को घंटों लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है।

बिजली बिलों में सुधार, नए कनेक्शन, नाम परिवर्तन, अकाउंट नंबर की जानकारी और अन्य जरूरी सेवाओं के लिए आने वाले उपभोक्ताओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार घंटों इंतजार के बाद भी उनका काम नहीं हो पाता, जिससे उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ता है। मीटर रीडर्स की हड़ताल के कारण पिछले कई सप्ताह से नियमित मीटर रीडिंग नहीं हो पा रही है, जिसके चलते बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को औसत बिल जारी किए जा रहे हैं।

स्थानीय उपभोक्ताओं का कहना है कि ये औसत बिल उनकी वास्तविक बिजली खपत से काफी अधिक आ रहे हैं, जिससे वे परेशान हैं। जब वे अपने बिलों में सुधार या संशोधन के लिए कार्यालय पहुंचते हैं, तो वहां कर्मचारियों की कमी के कारण उन्हें और अधिक समय तक इंतजार करना पड़ता है।

न्यूज ब्रीफ

गर्मी में बच्चों के लिए डॉक्टर की सलाह

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़ । गुरदासपुर सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, लेकिन हवा में अधिक नमी और उमस के कारण लोगों को 45 डिग्री से अधिक गर्मी का एहसास हो रहा है। भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है और सबसे अधिक खतरा छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा बुजुर्गों पर मंडरा रहा है। इसी को देखते हुए बाल रोग विशेषज्ञ डा. गुरप्रीत सिंह कलसी ने अभिभावकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने कहा कि बच्चों का शरीर तापमान नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होता, इसलिए उनमें डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। एक वर्ष से कम आयु के शिशु सबसे अधिक जोखिम में रहते हैं क्योंकि वे अपनी परेशानी व्यक्त नहीं कर पाते। डा. कलसी ने सलाह दी कि बच्चों को हल्के सूती कपड़े पहनाए जाएं, पर्याप्त पानी और घरेलू ठंडे पेय दिए जाएं तथा धूप में बाहर न जाने दिया जाए। उन्होंने कहा कि लापरवाही से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।

लिव-इन कपल हेरोइन सहित गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, जालंधर । जालंधर में सी.आई.ए. स्टाफ ने लुधियाना रोड स्थित लैदर कॉम्प्लेक्स के पास नाकाबंदी के दौरान एक लिव-इन कपल को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी कपूरथला के रहने वाले हैं और जालंधर में नशे की सप्लाई देने आ रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 101.57 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पुलिस के अनुसार, सी.आई.ए. इंचार्ज सुरिंदर कुमार कंबोज को सूचना मिली थी कि एक पुरुष और महिला कपूरथला से जालंधर में हेरोइन सप्लाई करने आने वाले हैं। सूचना के आधार पर नाकाबंदी की गई और जैसे ही दोनों वहां पहुंचे, उन्हें पकड़ लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रणजीत सिंह और प्रकाश कौर उर्फ काले के रूप में हुई है, जो कपूरथला में लिव-इन रिलेशन में रह रहे थे। जांच में सामने आया कि रणजीत सिंह पर पहले भी नाबालिग से दुष्कर्म और अपहरण का मामला दर्ज है, जबकि प्रकाश कौर पर नशा तस्करी के दो केस पहले से दर्ज हैं। पुलिस अब दोनों के नेटवर्क की जांच कर रही है और सप्लाई चेन से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में छापेमारी कर रही है।

गोल्डन टेंपल में तीर्थयात्रियों के पहचान पत्र हटाने पर हुआ विवाद

भारतेन्दु संवाददाता, अमृतसर

पंजाब में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत श्री दरबार साहिब (गोल्डन टेंपल) में शनिवार को उस समय विवाद की स्थिति बन गई जब श्रद्धालुओं के गले में पहने पहचान पत्रों को सेवादारों ने हटवाने के लिए कहा। ये श्रद्धालु राज्य के विभिन्न जिलों से आए थे और उनके गले में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की तस्वीर लगे पहचान पत्र थे।

जानकारी के अनुसार, जैसे ही तीर्थ यात्री श्री दरबार साहिब परिसर में पहुंचे, वहां मौजूद सेवादारों ने इन पहचान पत्रों पर आपत्ति जताई। सेवादारों का कहना था कि श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंथ दोषी घोषित किए जाने के बाद उनकी तस्वीर वाले पहचान पत्र गुरु घर की मर्यादा के अनुरूप नहीं हैं। इस कारण श्रद्धालुओं से अनुरोध किया गया कि वे ये कार्ड उतार दें।

स्थिति के दौरान श्रद्धालुओं और सेवादारों के बीच कुछ समय तक बहस भी देखने को मिली। हालांकि बाद में श्रद्धालुओं ने अपने गले से पहचान पत्र उतार दिए और दर्शन प्रक्रिया आगे बढ़ी। श्रद्धालुओं का कहना था कि ये पहचान पत्र उन्हें सरकार की ओर से तीर्थ यात्रा योजना के तहत दिए गए थे और उनका उद्देश्य केवल श्री दरबार साहिब में दर्शन करना था।

यह पूरा मामला धार्मिक और राजनीतिक विवादों से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। 15 जून को श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज ने आदेश जारी करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को पंथ विरोधी घोषित किया था। इसके बाद से ही सिख संगठनों में इस मुद्दे को लेकर मतभेद और बहस जारी है।

विवाद की पृष्ठभूमि में एक वायरल वीडियो भी बताया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री मान से जुड़े होने का दावा किया गया था। इस वीडियो को लेकर आम आदमी पार्टी ने इसे जनरेटेड और फर्जी बताया था।

लुधियाना के युवा हैंडबॉल खिलाड़ी पारस चड्ढा का भारतीय जूनियर टीम में एशियन चैंपियनशिप हेतु चयन

पारस चड्ढा का एशियन चैंपियनशिप हेतु चयन

भारतेन्दु संवाददाता, लुधियाना

लुधियाना शहर के लिए यह अत्यंत गर्व और उत्साह का क्षण है, जहां युवा खिलाड़ी पारस चड्ढा ने अपनी प्रतिभा और कठिन परिश्रम के बल पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर हासिल किया है। पारस चड्ढा का चयन वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली उन्नीसवीं एशियाई पुरुष जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय पुरुष जूनियर हैंडबॉल टीम में किया गया है। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता तेरह जुलाई से अट्ठाईस जुलाई 2026 तक चीन के चुजोउ शहर में आयोजित की जाएगी, जिसमें एशिया के कई देशों की शीर्ष टीमें भाग लेंगी।

पारस को पुरुष जूनियर हैंडबॉल टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया

पारस चड्ढा की इस उपलब्धि ने न केवल लुधियाना बल्कि पूरे पंजाब में खेल प्रेमियों को गौरवान्वित किया है। उनकी इस सफलता के पीछे वर्षों की कड़ी मेहनत, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण को प्रमुख कारण माना जा रहा है। स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए उन्होंने लगातार अपने प्रदर्शन में सुधार किया और राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।

इस उपलब्धि पर जिला खेल अधिकारी कुलदीप चुग, कोच गुरप्रीत सिंह, परवीन ठाकुर और गुरजीत सिंह ने पारस चड्ढा को हार्दिक बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि पारस जैसे युवा खिलाड़ी देश के खेल भविष्य की मजबूत नींव हैं, जो आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम और अधिक रोशन करेंगे। कोचों ने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय टीम इस प्रतियोगिता में पूरे समर्पण, अनुशासन और टीम भावना के साथ प्रदर्शन करेगी।

पारस चड्ढा की इस सफलता को क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत माना जा रहा है। खेल प्रेमियों और स्थानीय नागरिकों ने भी उन्हें शुभकामनाएं दीं और उम्मीद जताई कि वह आगामी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत को पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उनके चयन से क्षेत्र में खेल संस्कृति को भी नई ऊर्जा मिली है और युवा खिलाड़ियों में राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की प्रेरणा और अधिक मजबूत हुई है।

लुधियाना में नौकरानी 50 हजार चोरी कर फरार

भारतेन्दु संवाददाता, लुधियाना।

लुधियाना में घरेलू नौकरों द्वारा चोरी की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसा ही एक मामला सराभा नगर क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक घर में काम करने वाली नौकरानी 'निशा' पर मालकिन के घर से नकदी और मोबाइल चोरी कर फरार होने का आरोप लगा है।

पुलिस को दी गई शिकायत में डॉक्टर हरमिंदर प्रभाकर ने बताया कि 2 जुलाई को वह घर पर मौजूद थीं और दोपहर के समय आराम कर रही थीं। इसी दौरान उनका बेटा गौतम किसी काम से बाहर से घर लौटा। जब दरवाजा खुला तो महिला की नींद टूट गई। कुछ देर बाद उन्होंने घर के काम के लिए रखी नौकरानी निशा को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शक होने पर जब महिला ने कमरे की जांच की तो नौकरानी वहां मौजूद नहीं थी और उसका सामान भी गायब था। इसके बाद जब वह अपने बेडरूम में पहुंचीं तो वहां रखा मोबाइल फोन भी नहीं मिला। स्थिति गंभीर होने पर जब अलमारी की जांच की गई तो उसके ताले टूटे हुए थे और उसमें रखे 50 हजार रुपये नकद गायब थे।

पंजाब में बारिश से राहत, 5 जुलाई से भारी बारिश का अलर्ट

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

चंडीगढ़ में भीषण गर्मी के बीच शुक्रवार देर शाम मौसम ने अचानक करवट ले ली, जिससे पंजाब के कई जिलों में तेज बारिश दर्ज की गई। दिनभर की उमस और तपिश से परेशान लोगों को बारिश के बाद कुछ समय के लिए राहत जरूर मिली, लेकिन नमी बढ़ने के कारण वातावरण में उमस फिर से बढ़ गई, जिससे राहत सीमित ही रही।

लोगों ने बताया कि अचानक हुई बारिश से तापमान में हल्की गिरावट महसूस की गई, लेकिन हवा में नमी अधिक होने के कारण चिपचिपी गर्मी का अहसास बना रहा। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने से सड़कों पर पानी भी भर गया और कुछ जगहों पर यातायात भी प्रभावित हुआ।

मौसम विभाग के अनुसार, बारिश के बाद वातावरण में नमी बढ़ने से उमस का स्तर बढ़ जाता है, जिससे असहजता महसूस होती है। विभाग ने अनुमान जताया है कि यदि आने वाले दिनों में लगातार बारिश होती रही तो राज्य के तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है और मौसम में ठंडक बढ़ सकती है।

मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी जारी की है कि 5 जुलाई से पंजाब के कई हिस्सों में भारी बारिश, गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं की संभावना है। हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे पेड़ों के गिरने और बिजली आपूर्ति बाधित होने की आशंका भी बनी रहेगी। इस चेतावनी को देखते हुए विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें।

विवाद गैर-शैक्षणिक ड्यूटी के विरोध में शिक्षकों-प्रशासन में बढ़ा टकराव

लुधियाना में अध्यापकों और प्रशासन के बीच बढ़ा विवाद

भारतेन्दु संवाददाता, लुधियाना

लुधियाना में सरकारी स्कूल अध्यापकों और जिला प्रशासन के बीच तनाव बढ़ गया है। मामला 'ड्रग एंड सोशियो इकोनॉमिक सेंसस' के तहत मैपिंग और ट्रेनिंग ड्यूटी से जुड़ा है, जिसमें बड़ी संख्या में अध्यापक ड्यूटी ज्वाइन करने नहीं पहुंचे। शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के सख्त निर्देशों के बावजूद अध्यापकों की अनुपस्थिति से प्रशासन नाराज हो गया है और अब कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

जानकारी के अनुसार, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 2 जून को जारी आदेश में कई अध्यापकों को अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में ड्यूटी के लिए बुलाया गया था, लेकिन किसी भी अध्यापक ने उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। इसके बाद विभाग ने दोबारा पत्र जारी कर 3 जून को ड्यूटी ज्वाइन करने के निर्देश दिए, फिर भी अधिकांश अध्यापक अनुपस्थित रहे।

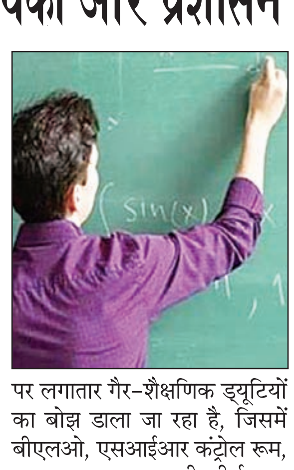

अध्यापकों का कहना है कि उन पर लगातार गैर-शैक्षणिक ड्यूटियों का बोझ डाला जा रहा है, जिसमें बीएलओ, एसआईआर कंट्रोल रूम, जनगणना, चुनाव ड्यूटी, तीर्थ यात्रा योजना और स्वास्थ्य योजनाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं। उनका आरोप है कि इससे उनकी मुख्य जिम्मेदारी, यानी छात्रों को पढ़ाना, प्रभावित हो रहा है। अध्यापकों ने इसे 'मानसिक उत्पीड़न' बताते हुए कहा कि वे केवल सरकारी ड्यूटियों में ही उलझे रहते हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था कमजोर हो रही है।

अध्यापकों ने यह भी आरोप लगाया कि 'ड्रग एंड सोशियो इकोनॉमिक सेंसस' के नाम पर राजनीतिक प्रचार किया जा रहा है और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। उनका कहना है कि ड्यूटी को स्वैच्छिक बताया जाता है, लेकिन बाद में अनुपस्थित रहने पर नोटिस और कार्रवाई की धमकी दी जाती है।

वहीं प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि ड्यूटी को गंभीरता से न लेने वाले अध्यापकों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्कूल प्रमुखों को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। केवल कुछ विशेष ड्यूटियों को ही छूट दी गई है।

इस पूरे मामले ने शिक्षा विभाग और अध्यापकों के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर दी है, जिससे आगे और विवाद बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी आदेशों की अवहेलना किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी संबंधित कर्मचारियों को तुरंत ड्यूटी पर उपस्थित होने को कहा गया है।

सरहिंद रेलवे स्टेशन पर 'रेल रोको' प्रदर्शन

भारतेन्दु संवाददाता, फतेहगढ़

फतेहगढ़ साहिब में बंदी सिंहों की रिहाई की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन देखने को मिला, जहां कौमी इंसाफ मोर्चा की ओर से सरहिंद रेलवे स्टेशन पर रेल रोको प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर ट्रेनों का आवागमन रोक दिया, जिससे कई यात्री ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

यह प्रदर्शन उन बंदी सिंहों की रिहाई की मांग को लेकर किया गया, जो अपनी सजा पूरी करने के बाद भी लंबे समय से विभिन्न जेलों में बंद बताए जा रहे हैं। कौमी इंसाफ मोर्चा का कहना है कि इन बंदियों को न्याय नहीं मिल रहा है और उनकी रिहाई को लेकर सरकार लगातार उदासीन रवैया अपना रही है। इसी कारण से मोर्चा ने एक बार फिर बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया।

प्रदर्शन में विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ कई राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हुए। बड़ी संख्या में लोग सरहिंद रेलवे स्टेशन पर एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान रेलवे ट्रैक पूरी तरह जाम हो गया, जिससे कई ट्रेनें अलग-अलग स्टेशनों पर रोकनी पड़ीं और यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा।

इस मौके पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य करनैल सिंह पंजोली, शेर-ए-पंजाब किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरिंदर सिंह भंगू सहित अन्य नेताओं ने संबोधित किया। नेताओं ने कहा कि मोहाली में कौमी इंसाफ मोर्चा लंबे समय से शांतिपूर्ण धरना देकर बंदी सिंहों की रिहाई की मांग कर रहा है, लेकिन सरकारों द्वारा इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है।

नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही इस संवेदनशील मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखा रही हैं, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि बार-बार ज्ञापन देने और बातचीत के बावजूद कोई समाधान नहीं निकाला गया, जिसके कारण अब आंदोलन को और तेज करने का फैसला लिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा और आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे।

हिमाचल में जंगलों की आग से पर्यावरण और जैव विविधता को पहुंच रहा गंभीर नुकसान

हिमाचल प्रदेश अपने घने जंगलों, बर्फ से ढके पहाड़ों, स्वच्छ नदियों और जैव विविधता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। देवदार, चीड़, बान, खरसू और कई दुर्लभ वनस्पतियों से भरपूर हिमाचल के जंगल केवल प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक नहीं हैं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और लोगों के जीवन का आधार भी हैं लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जंगलों में लगने वाली आग एक गंभीर समस्या बनकर उभरी है।

गर्मियों के मौसम में प्रदेश के कई जिलों-जैसे शिमला, मंडी, सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, चंबा और कुल्लू में लगातार वनाग्नि की घटनाएं सामने आती हैं। तेज गर्मी, सूखा मौसम, चीड़ की सूखी पत्तियां और मानवीय लापरवाही मिलकर इस संकट को और भयावह बना रही हैं। जंगलों में लग रही आग केवल पेड़ों को नहीं जलाती, बल्कि यह हिमाचल की पर्यावरणीय सुरक्षा, जल स्रोतों, वन्य जीवों, पर्यटन और स्थानीय लोगों के भविष्य को भी खतरे में डाल रही है।

हिमाचल में जंगलों की आग का सबसे बड़ा नुकसान पर्यावरण को होता है। जंगल पृथ्वी के 'फेफड़े' माने जाते हैं क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। जब हजारों हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आते हैं तो वातावरण में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और जहरीली गैसें फैलती हैं। इससे वायु प्रदूषण बढ़ता है और जलवायु परिवर्तन की समस्या और गंभीर हो जाती है। हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य में तापमान बढ़ने का असर ग्लेशियरों पर भी पड़ता है। ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगते हैं, जिससे भविष्य में जल संकट की संभावना बढ़ जाती है। वनाग्नि मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत को भी नष्ट कर देती है, जिससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती है और नए पौधों का विकास प्रभावित होता है।

विशाल कल्याण
सहायक प्रोफेसर, महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, सोलन

वनों में लगने वाली आग का दूसरा बड़ा नुकसान जैव विविधता को होता है। हिमाचल के जंगल अनेक दुर्लभ वनस्पतियों और वन्य जीवों का घर हैं। तेंदुआ, कस्तूरी मृग, हिमालयी मोनाल, भालू, जंगली खरगोश, लोमड़ी और कई पक्षी प्रजातियां इन जंगलों पर निर्भर हैं। आग लगने पर कई छोटे जीव और पक्षी जलकर मर जाते हैं, जबकि बड़े जानवर अपने आवास छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। इससे मानव-वन्यजीव संघर्ष भी बढ़ता है, क्योंकि जानवर भोजन और पानी की तलाश में गांवों की ओर आने लगते हैं। कई औषधीय पौधे, जो केवल हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, आग के कारण नष्ट हो जाते हैं। यह नुकसान केवल वर्तमान के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी गंभीर खतरा है। हिमाचल की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका है और जंगलों की आग इस क्षेत्र को भी प्रभावित कर रही है। राज्य में हर साल लाखों पर्यटक प्राकृतिक सुंदरता और ठंडे मौसम का आनंद लेने आते हैं लेकिन जब पहाड़ धुएं से भर जाते हैं और जंगल जलते दिखाई देते हैं, तो पर्यटकों की संख्या कम होने लगती है।

शिमला, मनाली, धर्मशाला और कसौली जैसे पर्यटन स्थलों के आसपास आग की घटनाएं प्रदेश की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं। धुएं और प्रदूषण के कारण पर्यटकों को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे होटल, टैक्सी, रेस्तरां और छोटे व्यापारियों की आय प्रभावित होती है। पर्यटन पर निर्भर हजारों परिवारों के रोजगार पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। वनाग्नि का प्रभाव ग्रामीण जीवन पर भी गहराई से पड़ता है। हिमाचल के अनेक गांव जंगलों के पास बसे हुए हैं और ग्रामीण अपनी दैनिक आवश्यकताओं-जैसे पशुओं के लिए चारा, ईंधन की लकड़ी और पानी के लिए जंगलों पर निर्भर रहते हैं।

आग लगने से चारा और वन संसाधन नष्ट हो जाते हैं, जिससे ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार आग गांवों तक पहुंच जाती है और घरों, खेतों तथा पशुओं को भी नुकसान पहुंचाती है। किसानों की फसलें जल जाती हैं और आर्थिक नुकसान होता है। जंगलों के नष्ट होने से जल स्रोत सूखने लगते हैं, क्योंकि पेड़ वर्षा जल को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की कमी बढ़ जाती है। हर वर्ष हिमाचल प्रदेश में हजारों हेक्टेयर वन क्षेत्र आग की चपेट में आ जाता है, जिससे करोड़ों रुपये की वन संपदा नष्ट होती है। केवल पेड़ों का ही नहीं, बल्कि मिट्टी, जैव विविधता और पर्यावरणीय सेवाओं का भी भारी नुकसान होता है। विशेषज्ञों के अनुसार वनाग्नि से होने वाला वास्तविक नुकसान सरकारी आँकड़ों से कहीं अधिक होता है, क्योंकि इसके प्रभाव लंबे समय तक दिखाई देते हैं। एक बार जंगल जल जाने के बाद उस क्षेत्र को दोबारा विकसित होने में कई दशक लग सकते हैं। हिमाचल में वनाग्नि के पीछे प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारण जिम्मेदार हैं। अत्यधिक गर्मी, कम वर्षा और सूखी हवाएँ आग को फैलाने में मदद करती हैं, जबकि लोगों की लापरवाही समस्या को और गंभीर बना देती है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

हिमाचल को नशामुक्त बनाने के लिए जनता को बनना होगा पुलिस का सहयोगी

देवभूमि हिमाचल प्रदेश आज एक गंभीर सामाजिक चुनौती का सामना कर रहा है। यह चुनौती है युवाओं में तेजी से बढ़ते नशे के प्रचलन की। कभी अपनी संस्कृति, सभ्यता और शांत वातावरण के लिए पहचाने जाने वाला हिमाचल आज नशे जैसी भयावह समस्या से जूझ रहा है। विशेष रूप से केमिकल और सिंथेटिक नशे का बढ़ता उपयोग समाज और परिवारों के लिए गहरी चिंता का विषय बन चुका है। यह केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक पतन का संकेत भी है।

प्रदेश में आए दिन पुलिस द्वारा नशे के सौदागरों और नशा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस लगातार नशा तस्करों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। बावजूद इसके जिस तेजी से युवाओं में नशे का फैलाव हो रहा है, वह बेहद चिंताजनक है। नशे की गिरफ्त में आकर कई युवा अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। अनेक परिवार अपने बच्चों को खो चुके हैं और कई घरों के चिराग हमेशा के लिए बुझ गए हैं। यह स्थिति केवल प्रशासन के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए खतरे की घंटी है।

ठाकुर हेमराज राणा
स्वतंत्र लेखक, सिरमौर

हिमाचल प्रदेश पुलिस नशे के खिलाफ लगातार सख्त अभियान चला रही है। जगह-जगह छापेमारी, जागरूकता अभियान, मैराथन दौड़, नशे के खिलाफ लेखन और सांस्कृतिक कार्य, मों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन उन व्यक्तियों और संस्थाओं को भी सम्मानित करता है जो समाज में नशामुक्ति को लेकर सकारात्मक कार्य कर रहे हैं। यह प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय हैं और समाज में पुलिस के प्रति विश्वास को मजबूत करते हैं।

इसके साथ ही प्रदेश सरकार भी नशे के खिलाफ कठोर कदम उठा रही है। सरकार से अपेक्षा है कि नशा तस्करों और नशे के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ और अधिक सख्त कार्रवाई की जाए। उनकी अवैध संपत्तियों को जब्त कर उसे जनहित और प्रदेश के विकास कार्यों में लगाया जाना चाहिए। इससे समाज में एक कड़ा संदेश जाएगा कि नशे का कारोबार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

हालांकि केवल पुलिस और सरकार के प्रयासों से इस समस्या का पूर्ण समाधान संभव नहीं है। जब तक आम जनता पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं करेगी, तब तक हिमाचल को पूरी तरह नशामुक्त बनाना कठिन रहेगा। समाज के बुद्धिजीवियों, शिक्षकों, अभिभावकों और युवाओं को इस लड़ाई में आगे आना होगा। नशे की समस्या को किसी दूसरे घर की समस्या समझने के बजाय अपने घर और समाज की समस्या मानना होगा।

अक्सर देखा जाता है कि कई क्षेत्रों में लोग नशा कारोबारियों की जानकारी होने के बावजूद पुलिस को सूचना नहीं देते। कुछ लोग डर या सामाजिक दबाव के कारण चुप रहते हैं। यही चुप्पी नशा तस्करों के हौसले बढ़ाती है। यदि जनता समय-समय पर पुलिस को सही जानकारी और सहयोग दे, तो नशे के बड़े नेटवर्क को आसानी से तोड़ा जा सकता है। समाज और पुलिस के बीच मजबूत तालमेल ही इस समस्या से लड़ने का सबसे प्रभावी उपाय है।

आज जरूरत इस बात की है कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए परिवार और समाज मिलकर सकारात्मक माहौल तैयार करें। खेल, शिक्षा, रोजगार और सांस्कृतिक गतिविधियों की ओर युवाओं को प्रेरित करना होगा। स्कूलों और कॉलेजों में नशे के दुष्प्रभावों को लेकर नियमित जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। अभिभावकों को भी अपने बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए और उनके साथ संवाद बनाए रखना चाहिए। नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को बर्बाद कर देता है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

> **कलाविशेष** में निपुण भले ही चित्र में कितने ही पुष्प बना दें पर क्या वे उनमें सुगंध पा सकते हैं और फिर भ्रमर उनसे रस कैसे पी सकेंगे।
>
> -पंडितराज जगन्नाथ

संपादकीय

भारत और जापान के संबंध नए आयामों पर

भारत और जापान के संबंध अब एक नए और व्यापक स्वरूप में विकसित होते दिखाई दे रहे हैं। यह रिश्ता अब केवल आर्थिक सहयोग या व्यापारिक साझेदारी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह एक मजबूत, बहुआयामी और दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी का रूप ले चुका है। नई दिल्ली में आयोजित भारत-जापान वार्षिक शिखर वार्ता ने इस दिशा में एक स्पष्ट और महत्वपूर्ण संकेत दिया है कि आने वाले वर्षों में दोनों देश मिलकर अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को और अधिक गहरा करेंगे। इनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), रक्षा, ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, हरित प्रौद्योगिकी और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं जैसे रणनीतिक क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दोनों देशों के बीच विश्वास को सबसे बड़ी रणनीतिक पूंजी बताया जाना इस रिश्ते की गहराई और मजबूती को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। यह विश्वास ही वह आधार है जिस पर भारत और जापान अपनी साझेदारी को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। आज जब वैश्विक व्यवस्था तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, ऐसे में भारत और जापान का सहयोग अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है।

वर्तमान समय में इंडो-पैसिफिक क्षेत्र विश्व राजनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था का केंद्र बन चुका है। इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अस्थिरता और नई तकनीकों की तीव्र प्रतिस्पर्धा के बीच भारत और जापान का साथ केवल दोनों देशों के हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे एशिया में स्थिरता, शांति और विकास का मजबूत आधार बन सकता है। दोनों ही देश लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं और नियम-आधारित वैश्विक प्रणाली के समर्थक हैं, जिससे यह साझेदारी और अधिक मजबूत तथा विश्वसनीय बनती है। भारत में जापान द्वारा एक हजार बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। इससे न केवल स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। यह कदम पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इसी प्रकार सेमीकंडक्टर उद्योग, बैटरी निर्माण, इलेक्ट्रिक वाहन और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में जापानी निवेश भारत की औद्योगिक और विनिर्माण क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक होगा। भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसे अभियानों को इससे बड़ा समर्थन मिलेगा। इससे भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक मजबूत और विश्वसनीय केंद्र के रूप में उभर सकेगा। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग का विस्तार भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बदलती वैश्विक सुरक्षा परिस्थितियों को देखते हुए भारत और जापान का संयुक्त रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, और सैन्य अभ्यास हिंद महासागर तथा इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभा सकता है। यह सहयोग केवल सैन्य क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानवीय सहायता, आपदा प्रबंधन और समुद्री व्यापार की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण पहलू भी शामिल हैं।

हालांकि इस रणनीतिक साझेदारी की वास्तविक सफलता केवल समझौतों या घोषणाओं पर निर्भर नहीं करेगी। आवश्यक है कि जिन परियोजनाओं की घोषणा की गई है, उन्हें समयबद्ध और प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारा जाए। इसके लिए भारत को जापानी निवेशकों के लिए एक सरल, पारदर्शी और स्थिर कारोबारी वातावरण उपलब्ध कराना होगा। साथ ही तेज निर्णय प्रक्रिया और मजबूत बुनियादी ढांचा भी सुनिश्चित करना होगा, जिससे निवेशकों का विश्वास और अधिक मजबूत हो सके। दूसरी ओर, भारतीय उद्योगों को भी जापान की कार्य संस्कृति से सीख लेने की आवश्यकता है, जिसमें गुणवत्ता, अनुशासन, समय पालन और नवाचार पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यदि भारतीय उद्योग इन मूल्यों को अपनाते हैं तो वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में और अधिक मजबूती से खड़े हो सकते हैं। भारत और जापान का यह संबंध केवल व्यापार, निवेश या तकनीकी सहयोग का संबंध नहीं है, बल्कि यह साझा मूल्यों, पारस्परिक विश्वास और दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टि पर आधारित है। दोनों देशों के बीच यह समझ और सहयोग भविष्य में और अधिक गहरा होने की पूरी संभावना रखता है।

यदि यह साझेदारी इसी गति और दिशा में आगे बढ़ती रही, तो यह न केवल दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी, बल्कि पूरे एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि का एक नया अध्याय भी लिखेगी। बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत और जापान का यह संबंध वास्तव में इक्कीसवीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक समीकरणों में से एक बनकर उभर रहा है। यह साझेदारी आने वाले समय में वैश्विक शक्ति संतुलन को भी प्रभावित करने की क्षमता रखती है। जैसे-जैसे तकनीकी प्रगति, हरित ऊर्जा और डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, वैसे-वैसे भारत और जापान का सहयोग वैश्विक विकास का एक महत्वपूर्ण इंजन बन सकता है। दोनों देशों के बीच यह रणनीतिक तालमेल न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि विश्व व्यवस्था में एक सकारात्मक और स्थायी परिवर्तन का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। इसके अतिरिक्त, दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे युवाओं में आपसी समझ और सहयोग की भावना मजबूत होगी। पर्यटन, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में संयुक्त प्रयास भविष्य की नई संभावनाओं को जन्म देंगे। यदि यह सहयोग निरंतर जारी रहता है, तो भारत-जापान साझेदारी वैश्विक स्तर पर एक आदर्श रणनीतिक मॉडल के रूप में स्थापित हो सकती है।

-शिवांश धाकड़

एड्स एक गंभीर जानलेवा बीमारी, जागरूकता और सुरक्षित जीवनशैली से ही संभव है प्रभावी बचाव

आधुनिक युग में विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल की गई हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ बीमारियां आज भी मानव समाज के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई हैं। एड्स ऐसी ही एक घातक और जानलेवा बीमारी है, जिसने पूरी दुनिया में भय और चिंता का वातावरण पैदा किया। भारत में भी एड्स ने धीरे-धीरे अपनी गहरी पैठ बना ली है। कब और कैसे इस बीमारी के विषाणु हमारे देश में पहुंचे, इसका स्पष्ट पता नहीं चल पाया, लेकिन जब तक लोगों को इसकी गंभीरता का एहसास हुआ, तब तक यह बीमारी हजारों लोगों को अपनी चपेट में ले चुकी थी।

डॉ. पीसी कौंडल
गांव ददोह, (बल्ह) जिला मंडी

भारत में एड्स का पहला रोगी वर्ष 1986 में चेन्नई में पाया गया, जबकि हिमाचल प्रदेश में इसका पहला मामला वर्ष 1992 में सामने आया। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 1995 तक विश्वभर में करोड़ों लोग एचआईवी सं, मण का शिकार हो चुके थे। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। समय के साथ यह बीमारी तेजी से फैलती गई और आज भी यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

एड्स वास्तव में एचआईवी नामक वायरस के कारण होने वाला रोग है। यह वायरस शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को धीरे-धीरे कमजोर कर देता है। मानव शरीर में मौजूद प्रतिरक्षा कोशिकाएं रोगों से लड़ने का कार्य करती हैं, लेकिन एचआईवी वायरस इन कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। परिणामस्वरूप सं, मित व्यक्ति सामान्य बीमारियों का भी आसानी से शिकार हो जाता है। इस बीमारी को विकसित होने में कई वर्षों का समय लग सकता है, इसलिए कई बार व्यक्ति लंबे समय तक यह नहीं जान पाता कि वह सं, मित है।

एचआईवी संक्रमित व्यक्ति में शुरूआती दौर में कोई विशेष लक्षण दिखाई नहीं देते। हालांकि समय के साथ शरीर कमजोर होने लगता है। लगातार बुखार रहना, वजन घटना, भूख कम लगना, दस्त, कमजोरी, मुंह में छाले, निमोनिया और शरीर में गांठें बनना इसके सामान्य लक्षण माने जाते हैं।

लेकिन केवल लक्षणों के आधार पर इस बीमारी की पहचान संभव नहीं है। इसकी पुष्टि केवल चिकित्सकीय जांच से ही हो सकती है।

एड्स के फैलने के मुख्य कारणों में असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त चढ़ाना, सं, मित सुई या इंजेक्शन का उपयोग तथा संक्रमित मां से बच्चे में सं, मण शामिल हैं। इसलिए इस बीमारी के प्रति जागरूकता बेहद जरूरी है। यह रोग छूने, साथ बैठने, भोजन साझा करने या सामान्य सामाजिक संपर्क से नहीं फैलता। समाज में आज भी एड्स को लेकर कई भ्रांतियां और भेदभाव देखने को मिलते हैं, जिन्हें दूर करना आवश्यक है।

चूंकि एड्स का पूर्ण इलाज अभी तक संभव नहीं है, इसलिए बचाव ही इसका सबसे प्रभावी उपाय माना जाता है। हमें अनजान व्यक्तियों से असुरक्षित संबंध बनाने से बचना चाहिए। रक्त चढ़ाने से पहले उसकी जांच सुनिश्चित करनी चाहिए तथा हमेशा सुरक्षित और स्वच्छ सुई का ही प्रयोग करना चाहिए। साथ ही समाज में जागरूकता फैलाना भी हमारी जिम्मेदारी है। आज आवश्यकता इस बात की है कि एड्स के प्रति डर नहीं बल्कि जागरूकता बढ़ाई जाए। एड्से से संक्रमित हुए व्यक्तियों के साथ भेदभाव करने के बजाय उन्हें सहयोग और सहानुभूति दी जानी चाहिए। यदि समय रहते लोग जागरूक हो जाएं, तो इस बीमारी पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। वास्तव में 'रोकथाम इलाज से बेहतर है' की कहावत एड्स जैसी बीमारी पर पूरी तरह लागू होती है।एड्स एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है, इसलिए इससे जुड़े सभी पहलुओं को समझना और समाज में सही जानकारी फैलाना अत्यंत आवश्यक है। कई बार गलत धारणाओं और भ्रांतियों के कारण लोग संक्रमित व्यक्तियों से दूरी बनाने लगते हैं, जिससे सामाजिक भेदभाव बढ़ता है।

जबकि सच्चाई यह है कि एड्स सामान्य संपर्क जैसे साथ बैठने, हाथ मिलाने या भोजन साझा करने से नहीं फैलता। आज चिकित्सा विज्ञान में इतनी प्रगति हो चुकी है कि समय पर जांच और उचित उपचार से एचआईवी संक्रमण को नियंत्रित किया जा सकता है और व्यक्ति लंबे समय तक सामान्य जीवन जी सकता है। इसके लिए नियमित दवाइयों का सेवन और डॉक्टर की सलाह का पालन बहुत जरूरी है। सरकार और विभिन्न सामाजिक संस्थाएं भी एड्स जागरूकता फैलाने के लिए लगातार अभियान चला रही हैं।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

व्यक्तित्व विशेष

भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी

पीवी सिंधु

पीवी सिंधु का जन्म 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद, तेलंगाना में हुआ था। उनका पूरा नाम पुसरला वेंकट सिंधु है। वे भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन कर चुकी हैं। उनके पिता पी. वी. रमना और माता विजया दोनों ही वॉलीबॉल खिलाड़ी रहे हैं, जिससे उन्हें खेल का माहौल बचपन से मिला।

सिंधु ने कोच पुलेला गोपीचंद से प्रशिक्षण लिया। उन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में रजत पदक और 2020 टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। वे विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। सिंधु अपनी मेहनत, अनुशासन और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जानी जाती हैं।उन्होंने एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी कई पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। सिंधु आज युवाओं के लिए प्रेरणा का बड़ा स्रोत बनी हुई हैं और निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं।

कविता

तुम भी करो गौर

कैप्टन (डॉ.) जय महलवाल (अनजान), ई 01 प्रोफेसर कॉलोनी, राजकीय महाविद्यालय, बिलासपुर (हि.प्र.)

मतदान के लिए हो जाओ तैयार, कर लो थोड़ी सी बातों पर गौर।
एक तो वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर न ले जाएं फोन।
न लगाएं किसी पार्टी का चिन्ह, न ही लांघे कोई प्रतिबंधित जोन।
आपसी रिश्ते बनाएं रखें मधुर, मतदान करें बिलकुल होकर मुखर।
किसी से न करें कोई दंगा, न ही किसी को दें बिन मतलब का डंडा।
वोट करते समय जरूर सुनें बीप की आवाज।
पर्ची देखकर सुनिश्चित करें मतदान का आगाज।
बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें मतदान में।
मनचाहे और ईमानदार उम्मीदवार को जिताएं जो हो मैदान में।
दूसरों को प्रोत्साहित करें वोट देने के लिए।
मत झांसे में आएं पैसे देने वालों के।
मजबूत लोकतंत्र बनाएं आगे आने वालों के लिए।
विश्वगुरु है भारत अपना ये संदेश दें दुनिया वालों को।

महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए सामाजिक जिम्मेदारी आवश्यक

भारत में किसी बस स्टॉप पर खड़ी महिला केवल एक यात्री नहीं होती, बल्कि वह समाज की अनेक परतों, संघर्षों और उम्मीदों का प्रतीक होती है। वह बस का इंतजार करती दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में वह अपने अधिकारों, अवसरों और सम्मानजनक अस्तित्व की प्रतीक्षा भी कर रही होती है।

हमारे समाज में महिलाओं की सार्वजनिक उपस्थिति को आज भी पुरुषों की तुलना में अलग दृष्टि से देखा जाता है। यदि कोई पुरुष देर रात सड़क पर दिखाई दे तो यह सामान्य माना जाता है, लेकिन किसी महिला की उपस्थिति पर तुरंत सवाल उठने लगते हैं। यही मानसिकता महिलाओं की स्वतंत्र आवाजाही के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है।

डॉ. प्रियंका सौरभ
सामाजिक चिंतक

महिलाओं के लिए घर से बाहर निकलना केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि सामाजिक और मानसिक चुनौतियों से गुजरने की प्रि, या है। महानगरों से लेकर छोटे कस्बों तक महिलाएं सार्वजनिक स्थानों पर स्वयं को असुरक्षित महसूस करती हैं। उनके लिए यात्रा का अर्थ केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास, साहस और धैर्य की परीक्षा देना भी होता है। कई छात्राएं दूर के कॉलेजों में प्रवेश नहीं लेतीं क्योंकि यात्रा सुरक्षित नहीं होती। अनेक महिलाएं बेहतर नौकरी के अवसर छोड़ देती हैं क्योंकि देर शाम घर लौटना जोखिमपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार असुरक्षित परिवहन व्यवस्था महिलाओं की स्वतंत्रता ही नहीं, देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति को भी प्रभावित करती है।

महिलाओं के लिए सस्ती और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था केवल सुविधा नहीं, बल्कि सामाजिक समानता का माध्यम है। जब सरकारें महिलाओं के लिए मुफ्त या रियायती बस यात्रा जैसी योजनाएं लागू करती हैं, तो उससे केवल आर्थिक राहत नहीं मिलती बल्कि महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और सामाजिक भागीदारी के नए रास्ते खुलते हैं। कई परिवारों में आज भी महिलाओं की पढ़ाई या नौकरी पर होने वाला खर्च अतिरिक्त बोझ माना जाता है।

ऐसे में यात्रा व्यय कम होना उनके आत्मनिर्भर बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। यह समझना आवश्यक है कि घर से बाहर निकलने वाली हर महिला नौकरी पर ही नहीं जाती; वह अपने जीवन के किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर बढ़ रही होती है। कोई महिला बीमार माँ की देखभाल के लिए दूसरे शहर जा रही होती है, कोई विवाह के बाद छूटी पढ़ाई को फिर से शुरू करने का प्रयास कर रही होती है, तो कोई अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अतिरिक्त काम कर रही होती है। कई बार वह केवल कुछ क्षणों की मानसिक शांति पाने के लिए घर से बाहर निकलती है, क्योंकि घर के भीतर उसका अवैतनिक श्रम कभी समाप्त नहीं होता। भारतीय समाज में महिलाओं का घरेलू श्रम आज भी बड़े पैमाने पर अदृश्य माना जाता है। भोजन बनाना, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना, घर की साफ-सफाई और अनगिनत छोटे-बड़े कार्य-ये सब परिवार की नींव हैं, लेकिन इनका आर्थिक मूल्य नहीं आंका जाता। ऐसे में जब कोई महिला घर से बाहर निकलती है तो वह केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि अनेक जिम्मेदारियों का भार उठाए हुए निकलती है।

उसके पास समय सीमित होता है, संसाधन कम होते हैं और सामाजिक अपेक्षाएं अधिक होती हैं। सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं को असहज व्यवहार, असुरक्षा और असमानता का सामना करना पड़ता है।

यह स्थिति केवल कानून नहीं, बल्कि सामाजिक सोच में बदलाव की मांग करती है। महिलाओं की स्वतंत्र आवाजाही लोकतंत्र और समानता का आधार है, जिसे सुरक्षित और सम्मानजनक बनाना पूरे समाज की जिम्मेदारी है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि महिला सुरक्षा को केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इसे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बनाया जाए। सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त निगरानी, सीसीटीवी कैमरे, महिला हेल्पलाइन और प्रशिक्षित स्टाफ की तैनाती अनिवार्य होनी चाहिए। केवल सुविधाएं उपलब्ध कराना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका सही क्रियान्वयन भी उतना ही जरूरी है।

शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में सुरक्षित और सुलभ परिवहन व्यवस्था विकसित करना समय की मांग है। यदि महिलाएं बिना डर के यात्रा कर सकें, तो वे शिक्षा, रोजगार और सामाजिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय रूप से भाग ले सकेंगी। इससे न केवल उनका व्यक्तिगत विकास होगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही समाज में मानसिकता परिवर्तन की भी अत्यंत आवश्यकता है। महिलाओं के प्रति सम्मान और समानता की भावना को बचपन से ही शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जाना चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में जेंडर सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए ताकि नई पीढ़ी एक सुरक्षित और समान समाज की दिशा में आगे बढ़ सके।

मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्हें महिलाओं से जुड़े मुद्दों को सकारात्मक और जागरूकता बढ़ाने वाले तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, न कि सनसनी फैलाने के रूप में। इसके अलावा, महिलाओं को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए और किसी भी प्रकार के अन्याय या उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। यदि सरकार, समाज और परिवार मिलकर प्रयास करें, तो महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण तैयार किया जा सकता है, जहां वे बिना भय के अपने सपनों को पूरा कर सकें।

(ये लेखिका के निजी विचार हैं)

'भारतेन्दु शिखर

प्रकाशक, मुद्रक, संपादक एवं स्वामी शिवांश धाकड़ द्वारा शर्मा भवन, न्यू रणजीत नगर, एप्पल फ्रूट मंडी, नजदीक ढली टनल, शिमला (हि.प्र.) 171006 से प्रकाशित एवं बायोसर्ट इंटरनेशनल प्रा. लि. प्लॉट नंबर 8, फेज-2 इंडस्ट्रियल एरिया, नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि.प्र.), पिन नंबर-176047 से मुद्रित। समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद शिमला न्यायालय के अधीन होंगे।

आरएनआई संदर्भ संख्या-HPHIN/2000/02437
ई-मेल : bhartendunewsmedia@gmail.com, फोन नंबर : 88946-77702

युवक ने महिला की हत्या करके 15 साल पहले हुए अपने पिता के अपमान का बदला लिया

एजेंसी, उरई

उत्तर प्रदेश में जालौन जिले के रामपुरा थाना क्षेत्र स्थित ग्राम जायघा में घर के बाहर चारपाई पर सो रही महिला की निर्मम हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर शनिवार को खुलासा कर दिया है। पुलिस ने दावा किया है कि यह ब्लाइंड मर्डर 15 साल पुरानी रंजिश का है। आरोपित ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वर्षों पहले मृतक महिला ने उसके पिता की चप्पलों से पिटाई की थी। इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने अपने साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया है।

अपर पुलिस अधीक्षक ईशान सोनी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि गुरुवार देर रात जायघा गांव निवासी मीना देवी घर के बाहर चारपाई पर सो रही थीं। इसी दौरान हमलावरों ने उन पर कुल्हाड़ी और बांस के डंडे से ताबड़तोड़ वार कर उनकी हत्या कर दी थी। शुक्रवार सुबह जब परिजनों और ग्रामीणों ने महिला का रक्तरंजित शव देखा तो पुलिस को सूचित किया। रामपुरा पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की।

मृतका के पुत्र देवेंद्र सिंह ने गांव के ही दो लोगों पर पुरानी रंजिश के चलते मां की हत्या कराने का आरोप लगाते हुए नामजद तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने साक्ष्य जुटाए और चेकिंग अभियान के दौरान दोनों आरोपित रन सिंह और लला उर्फ सहदेव को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में मुख्य आरोपित रन सिंह ने बताया कि करीब 15 वर्ष पहले किसी विवाद के दौरान उसके पिता की गांव में मृतका मीना देवी ने चप्पलों से पिटाई कर दी थी। पिता की उस बेइज्जती का बदला लेने की भावना उसके मन में लगातार बनी रही।

वहीं, दूसरे आरोपित लला उर्फ सहदेव की भी मृतका से पुरानी रंजिश थी। इसके बाद एक आरोपित ने बांस के डंडे से और दूसरे ने कुल्हाड़ी से महिला के सिर पर कई वार किए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद दोनों आरोपित हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और डंडे को नदी किनारे झाड़ियों में फेंक आए।

25 हजार के इनामी जाली नोट तस्कर को एटीएस ने दबोचा

एटीएस ने बांग्लादेश से जुड़े जाली नोट तस्करी गिरोह के सक्रिय सदस्य जाकिर को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से किया गिरफ्तार

एजेंसी, लखनऊ

उत्तर प्रदेश की आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने जाली भारतीय मुद्रा की तस्करी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह के सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। यह गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से की गई है, जहां से आरोपी जाकिर को दबोचा गया। आरोपी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था और उसे आगे की पूछताछ के लिए वाराणसी लाया गया है।

एटीएस द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, पिछले कुछ समय से खुफिया इनपुट मिल रहे थे कि बांग्लादेश में छपी भारतीय जाली नोटों की तस्करी पश्चिम बंगाल के रास्ते उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में की जा रही है। इस सूचना के आधार पर एटीएस ने विस्तृत जांच शुरू की। जांच के दौरान सामने आया कि यह पूरा नेटवर्क एक संगठित गिरोह के रूप में काम कर रहा था, जिसमें कई राज्यों और पड़ोसी देशों के लोग शामिल हैं। इससे पहले भी एटीएस ने वाराणसी से सुलेमान अंसारी और इदरीश को दो लाख रुपये के जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्हें यह जाली नोट मालदा निवासी जाकिर उपलब्ध कराता था। जाकिर के तार बांग्लादेश से भी जुड़े हुए पाए गए, जहां से रफीकुल नामक व्यक्ति जाली नोट भारत में भेजता था।

जानकारी के अनुसार, बांग्लादेश में छपे ये जाली नोट पहले पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में पहुंचाए जाते थे। वहां से जाकिर इन नोटों को प्राप्त कर अपने नेटवर्क के जरिए उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में सप्लाई करता था। यह गिरोह सुनियोजित तरीके से नकली मुद्रा को देश के अलग-अलग हिस्सों में फैलाने का काम कर रहा था। एटीएस ने शुक्रवार को मालदा में

छापेमारी कर आरोपी जाकिर को गिरफ्तार कर लिया और उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत वाराणसी लाया गया, जहां उससे गहन पूछताछ की जा रही है।

अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आने की संभावना है, जिससे इस पूरे नेटवर्क की परतें खुल सकती हैं। एटीएस ने यह भी स्पष्ट किया है कि आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ भी जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई को जाली मुद्रा तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता माना जा रहा है।

जाली नोट तस्करी मामले में गिरफ्तार आरोपी जाकिर से एटीएस की पूछताछ लगातार जारी है। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि उससे गिरोह के अन्य सदस्यों और उनके ठिकानों के बारे में अहम जानकारी मिल सकती है। शुरुआती पूछताछ में यह भी सामने आया है कि यह नेटवर्क केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं था, बल्कि पश्चिम बंगाल, बिहार और अन्य राज्यों में भी सक्रिय रूप से काम कर रहा था। एटीएस अब इस पूरे अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है।

अधिकारियों के अनुसार, बांग्लादेश से आने वाले नकली नोटों की सप्लाई चेन को पूरी तरह खत्म करना मुख्य लक्ष्य है। इस कार्रवाई के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने सीमावर्ती इलाकों में निगरानी और कड़ी करने की तैयारी में हैं, ताकि इस तरह की अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। एटीएस ने बताया कि नेटवर्क की वित्तीय जांच भी की जा रही है। संदिग्ध बैंक लेनदेन और संपर्कों की पड़ताल जारी है, जिससे पूरे गिरोह का खुलासा हो सके।

न्यूज ब्रीफ

सुरक्षा जवान द्वारा पकड़ी कार्बाइन से अचानक फायर होने से लोग घायल हुए मामला जांच

एजेंसी, वाराणसी। काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट पर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब तैनात एक सुरक्षा जवान की कार्बाइन से अचानक गोली चल गई। बताया जा रहा है कि जवान हथियार को संभाल रहा था, तभी अचानक फायर हो गया। गोली सीधे सड़क पर लगी, जिससे पास मौजूद पत्थर के टुकड़े उछलकर तीन लोगों को लग गए और वे घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कारणों की जांच की जा रही है।

घरेलू विवाद में महिला ने पति की हत्या कर बाथरूम में छिपाया शव,45 दिन बाद राजफाश

एजेंसी, आगरा। एक चौंकाने वाले मामले में एक महिला पर अपने पति की हत्या कर शव को बाथरूम में दफनाने का आरोप लगा है। जानकारी के अनुसार, पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद और मारपीट होती थी, जिससे परेशान होकर महिला ने कथित रूप से यह कदम उठाया। हत्या के बाद उसने शव को बाथरूम के अंदर गड्ढा खोदकर दफना दिया और उस पर फर्श भी बनवा दिया, ताकि किसी को शक न हो। वह लगभग 45 दिनों तक उसी घर में सामान्य रूप से रहती रही और उसी बाथरूम का उपयोग भी करती रही। बाद में मामले का खुलासा होने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी और पूरे घटनाक्रम की तहकीकात की जा रही है।

लखनऊ, मथुरा समेत 3 शहरों में बारिश 28 जिलों में अलर्ट जारी

एजेंसी, उत्तर प्रदेश। मानसूनी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। शनिवार को लखनऊ में अचानक मौसम बदल गया और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। मथुरा में सुबह दो घंटे तक बारिश से निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जबकि हाथरस में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया और कई जगह बिजली आपूर्ति बाधित हुई। प्रदेश के 28 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। कानपुर में भारी बारिश ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछले 24 घंटे में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई, हालांकि सीजन का कुल आंकड़ा अभी भी सामान्य से कम है।

स्टेट शूटिंग चैम्पियनशिप में मुरादाबाद के खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन

एजेंसी, मुरादाबाद। नई दिल्ली स्थित डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज में एक से चार जुलाई तक आयोजित 49वीं उत्तर प्रदेश स्टेट शूटिंग प्रतियोगिता में मुरादाबाद की हॉक आई शूटिंग एकेडमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में एकेडमी के कई निशानेबाजों ने भाग लिया, जिनमें आयुष अग्रवाल और रुद्र प्रताप सिंह सहित अन्य खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर इन खिलाड़ियों ने आगामी प्री-नेशनल शूटिंग प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई कर लिया है, जिससे उन्होंने अपने संस्थान और जनपद का नाम रोशन किया है। कोच पुष्कर देओल और उत्सव विश्नोई ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

प्रयागराज में अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई एक युवक की मौत, दूसरा घायल

एजेंसी, प्रयागराज। प्रयागराज के नैनी कोतवाली थाना क्षेत्र में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और उसका साथी घायल हो गया। जानकारी के अनुसार, शिवाला पार्क के पास एक अनियंत्रित कार अचानक पेड़ से जा टकराई। हादसे में नैनी क्षेत्र के खरकौनी गांव निवासी 22 वर्षीय अनुज भारतीय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और परिजनों को सूचना दी। मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

मानसिक तनाव के चलते अलग-अलग थाना क्षेत्रों में महिला समेत विभिन्न चार लोगों ने की आत्महत्या

एजेंसी, नोएडा

नोएडा के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मानसिक तनाव के चलते चार लोगों द्वारा आत्महत्या करने की दुखद घटनाएं सामने आई हैं। इन मामलों ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है और पुलिस ने सभी मामलों की जांच शुरू कर दी है। सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

पहली घटना थाना फेस-दो क्षेत्र के गेझा गांव की है, जहां 36 वर्षीय अमीनुर पुत्र मुर्तजा मंडल ने अपने घर में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

दूसरी घटना थाना सूरजपुर क्षेत्र की है, जहां 23 वर्षीय हेमंत कुमार पुत्र अजय कुमार, निवासी सेक्टर डेल्टा-1 ने अपने घर में आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि उन्होंने भी पंखे से फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। तीसरी घटना थाना फेस-3 क्षेत्र के गढ़ी चौखंडी गांव की है, जहां 28 वर्षीय भारती, पत्नी जितेंद्र कुमार, ने अपने घर में आत्महत्या कर ली। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मानसिक तनाव को कारण बताते हुए चार लोगों ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया

चौथी घटना थाना बिसरख क्षेत्र की है, जहां 40 वर्षीय रघुवीर अहिरवार, पुत्र बिकोड़े लाल, निवासी ग्रेटर नोएडा सेक्टर-3 में रहते थे। उन्होंने भी मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। लगातार सामने आ रही इन घटनाओं से स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है। पुलिस सभी मामलों की गहनता से जांच कर रही है और आत्महत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। नोएडा पुलिस ने कहा है कि सभी मामलों में अलग-अलग कारणों की जांच की जा रही है और परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

जेसीज चौराहे पर डंपर की टक्कर से सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी की मौके पर मौत

एजेंसी,औरैया। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के व्यस्ततम जेसीज चौराहे पर शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और यातायात भी कुछ समय के लिए बाधित हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक डंपर जो मिट्टी खाली करके लौट रहा था, जेसीज चौराहे पर तेज गति से आ रहा था। इसी दौरान उसने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार सड़क पर गिर पड़ा और गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया।

घटना की सूचना मिलते ही सदर कोतवाली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही सड़क पर बाधित यातायात को भी जल्द ही सुचारु करा दिया गया। कोतवाली सदर प्रभारी राजकुमार सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान भारतीय सेना से सेवानिवृत्त जवान सुरेश सिंह सेंगर (55) के रूप में हुई है। वे वर्तमान में एनटीपीसी में कार्यरत थे और अपने क्षेत्र में एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार डंपर चालक की तलाश की जा रही है।

आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाया जा सके। इस घटना से स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश और शोक व्याप्त है। पुलिस ने बताया कि डंपर की तेज रफ्तार और लापरवाही इस हादसे का मुख्य कारण मानी जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने चौराहे पर ट्रैफिक व्यवस्था और भारी वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही पर सवाल उठाए हैं। प्रशासन से मांग की जा रही है कि व्यस्त चौराहों पर स्पीड कंट्रोल और निगरानी बढ़ाई जाए ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके।

स्वामी विवेकानंद का जीवन भारत की सनातन चेतना का एक जीवंत प्रकाश-स्तंभ:आनंदी बेन पटेल

एजेंसी, देवरिया

स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि के अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शनिवार को जन भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि दी और उनके आदर्शों को नमन किया। इस अवसर पर जन भवन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा उनके विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लिया।

◆ **विवेकानंद के विचारों पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति**

कार्यक्रम के दौरान शिक्षा विभाग की ओर से स्वामी विवेकानंद के जीवन, व्यक्तित्व और विचारों पर आधारित सांस्कृतिक एवं शैक्षिक प्रस्तुतियां दी गईं। 'स्वामी विवेकानंद की बातें अमल में लाओ' गीत पर समूह गायन प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही 1893 में शिकागो विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके ऐतिहासिक उद्बोधन के अंशों का नाट्य रूपांतरण किया गया, जिसमें उनके सार्वभौमिक बंधुत्व, मानवता, सहिष्णुता और भारतीय संस्कृति के संदेश को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि स्वामी विवेकानंद भारत की सनातन चेतना के प्रतीक थे, जिन्होंने अपने संक्षिप्त जीवन में आध्यात्मिक और राष्ट्रीय चेतना का व्यापक संचार किया। उन्होंने कहा कि विवेकानंद ने उस समय देश के उज्ज्वल भविष्य की कल्पना की जब भारत पराधीनता और निराशा के दौर से गुजर रहा था। उनके अनुसार भारत के पास मानवता, करुणा, ज्ञान और आध्यात्मिकता की समृद्ध परंपरा है।

आनंदीबेन पटेल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का संदेश आज भी प्रासंगिक है, विशेषकर 'उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत' युवाओं के लिए प्रेरणास्त्रोत है। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, सम्मान और सेवा को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताया। राज्यपाल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी समाज को दिशा देने वाले हैं और उनके संदेशों को जीवन में अपनाना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से विवेकानंद के जीवन संदेशों को प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया। प्रतिभागियों ने 'उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत' का संदेश दोहराया। अधिकारियों ने कहा कि उनके विचार आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

राजस्व परिषद की नई पहल : न्यायालयों में प्रमाणित स्कैन प्रति से होगी कार्यवाही, मूल अभिलेख रहेंगे सुरक्षित

एजेंसी, लखनऊ

राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद ने न्यायिक व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और दक्ष बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल की शुरुआत की है। इस नई व्यवस्था के तहत अब राजस्व परिषद के न्यायालयों में किसी भी वाद की सुनवाई के दौरान मूल अभिलेखों के स्थान पर 'प्रमाणित पूर्ण स्कैन प्रति' का उपयोग किया जाएगा।

राजस्व परिषद की अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल के निर्देशों के अनुसार यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य मूल अभिलेखों को सुरक्षित रखना, उन्हें बार-बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की आवश्यकता को समाप्त करना तथा न्यायिक प्रक्रिया को तेज और अधिक प्रभावी बनाना है। नई प्रणाली के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा भेजी जाने वाली वाद पत्रावली की स्कैन प्रतियों में सभी दस्तावेज़ जैसे प्रत्येक पृष्ठ, आदेश पत्र, मानचित्र, नोटशीट और अन्य संलग्न अभिलेख क्रमवार और स्पष्ट रूप से शामिल करना अनिवार्य होगा।

इसके साथ ही संबंधित राजस्व रिकॉर्ड कीपर (आरआरके) द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र भी संलग्न किया जाएगा, जिससे दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित की जा सके। राजस्व परिषद ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल विशेष परिस्थितियों में ही मूल अभिलेख तलब किए जाएंगे, अन्यथा सभी कार्यवाही स्कैन की गई प्रमाणित प्रतियों के आधार पर ही की जाएगी। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि दस्तावेजों के क्षतिग्रस्त होने या गुम होने की संभावना भी कम हो जाएगी।

यदि किसी स्तर पर अपूर्ण या अप्रमाणित स्कैन प्रति प्रस्तुत की जाती है, तो संबंधित आरआरके को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी मानते हुए उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इस पहल के माध्यम से राजस्व परिषद न्यायिक प्रक्रिया को डिजिटल दिशा में आगे बढ़ा रहा है। भविष्य में इस प्रणाली को पूरी तरह ऑनलाइन किए जाने की योजना भी है।

गौरीगंज के चार बार विधायक रहे दादा तेजभान सिंह का निधन

एजेंसी, अमेठी

अमेठी जनपद की गौरीगंज विधानसभा सीट से चार बार विधायक रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व संघ प्रचारक दादा तेजभान सिंह का शनिवार को लखनऊ स्थित मैक्स हॉस्पिटल में निधन हो गया। वह लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनके निधन की खबर से अमेठी सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। राजनीतिक, सामाजिक और विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने इसे अपूरणीय क्षति बताया है।

दादा तेजभान सिंह युवावस्था में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और बाद में जनसंघ तथा भाजपा की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने वर्ष 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर गौरीगंज से पहली बार विधानसभा चुनाव जीता। इसके बाद 1991, 1993 और 1996 में भाजपा के प्रत्याशी के रूप में लगातार जीत दर्ज की। चार बार विधायक रहने वाले तेजभान सिंह अपने सरल, सहज और मिलनसार व्यक्तित्व के लिए क्षेत्र में 'दादा' के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में सिद्धांतों को प्राथमिकता दी और संगठन के प्रति निष्ठा बनाए रखी।

वर्ष 2017 में टिकट न मिलने के बावजूद उन्होंने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। उनके निधन पर भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। दादा तेजभान सिंह के निधन पर क्षेत्र में गहरा शोक व्याप्त है। उनके समर्थकों ने उन्हें एक सादगीपूर्ण, ईमानदार और जनप्रिय नेता बताया।

गिरफ्तारी आरोपी मारपीट और आपराधिक मामलों में फरार चल रहा था और ठिकाने बदल रहा था

50 हजार का इनामी बदमाश रेलवे स्टेशन से किया गिरफ्तार

एजेंसी, वाराणसी

उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की अयोध्या फील्ड इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बलिया जिले से घोषित 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को शनिवार को वाराणसी स्थित बनारस रेलवे स्टेशन से उस समय दबोचा गया जब वह ट्रेन पकड़कर फरार होने की फिराक में था।

आरोपी के खिलाफ बलिया के कोतवाली और सुखपुरा थानों में मारपीट समेत कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक प्रेमश कुमार शुक्ल ने जानकारी दी कि अयोध्या फील्ड यूनिट की टीम उपनिरीक्षक सौरभ मिश्र के नेतृत्व में मुख्य आरक्षी संतोष सिंह, नीरज सिंह, चंद्रप्रकाश, कमांडो राजकुमार और आरक्षी चालक सर्वेश यादव के साथ फरार और इनामी अपराधियों की तलाश में वाराणसी में अभियान चला रही थी।

इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि बलिया के रामपुर उदयभान गांव का निवासी मनोज यादव रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार पर मौजूद है और वह किसी ट्रेन से फरार होने की योजना बना रहा है। सूचना मिलते ही टीम ने तुरंत घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद की गई पूछताछ में मनोज यादव ने स्वीकार किया कि वर्ष 2021 में उसके करीबी मित्र आदित्य पांडेय के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी।

इसी घटना का बदला लेने के लिए उसने 10 से 12 युवकों का एक समूह तैयार किया और कई बार मारपीट की घटनाओं को अंजाम दिया। उसने यह भी स्वीकार किया कि इलाके में अपना वर्चस्व स्थापित करने और लोगों में डर पैदा करने के उद्देश्य से वह आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी पहले भी जेल जा चुका है।

जेल से रिहा होने के बाद पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए वह तमिलनाडु चला गया था, लेकिन बीच-बीच में वह बलिया आता-जाता रहता था। लगातार फरार रहने और मारपीट के मामलों में वांछित होने के कारण उसके ऊपर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह लगातार ठिकाने बदलता रहा और छिपकर रह रहा था।

एसटीएफ ने बताया कि आरोपी को आगे की विधिक कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया है। साथ ही उसके आपराधिक नेटवर्क और अन्य मामलों की भी गहन जांच की जा रही है, ताकि उसके पूरे गिरोह और गतिविधियों का खुलासा किया जा सके। एसटीएफ ने बताया कि आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस से बच रहा था। गिरफ्तारी के बाद उससे जुड़े अन्य सहयोगियों की भी जांच की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में उसके पूरे आपराधिक नेटवर्क का खुलासा होगा और कई अन्य घटनाओं में भी जानकारी सामने आएगी।

बिजली करंट से युवक की मौत, बिना पुलिस सूचना हुआ अंतिम संस्कार

एजेंसी, मीरजापुर

राजगढ़ थाना क्षेत्र के सरसों गांव में शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक हादसे में 18 वर्षीय युवक आदित्य की विद्युत करंट लगने से मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया और गांव में शोक का माहौल फैल गया। जानकारी के अनुसार, आदित्य अपने चाचा पंकज के साथ गांव में रहता था, जबकि उसके माता-पिता बाहर काम करते हैं। घटना उस समय हुई जब आदित्य भोजन करने के बाद अपने कच्चे मकान में सोने गया था। रात करीब 11 बजे वह पंखा चलाने के लिए बिजली के बोर्ड में तार जोड़ रहा था।

बताया जा रहा है कि उस समय बोर्ड का स्विच चालू था और आदित्य नंगे पैर खड़ा था। इसी दौरान वह करंट की चपेट में आ गया और मौके पर ही जमीन पर गिर पड़ा। परिजन तुरंत उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बेटे की मौत की खबर मिलते ही

◆ **दो भाइयों में 18 वर्षीय छोटे बेटे की असमय मौत से शोक**

माता-पिता भी गांव पहुंच गए, जिससे परिवार में चीख-पुकार मच गई। आदित्य दो भाइयों में छोटा था और उसकी असमय मौत से पूरा परिवार सदमे में है।

राजगढ़ थाना प्रभारी बालमुकुंद मिश्र ने बताया कि इस घटना की कोई औपचारिक सूचना पुलिस को नहीं दी गई और परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस अब मामले की जानकारी जुटा रही है। पुलिस ने बताया कि मामले में किसी प्रकार की लापरवाही या अन्य कारणों की भी जांच की जा रही है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से अपील की है कि बिजली सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके। थाना प्रभारी ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है और परिजनों से भी जानकारी जुटाई जा रही है।

फरीदाबाद में 3.45 किलो चूरा पोस्त सहित नशा तस्कर गिरफ्तार

भारतेंदु संवाददाता, फरीदाबाद

हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की फरीदाबाद यूनिट ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 किलो 450 ग्राम चूरा पोस्त के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पलवल जिले के गांव राखौता निवासी मेहरचंद के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो फरीदाबाद यूनिट के प्रभारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने शनिवार को बताया कि यूनिट में तैनात सहायक उपनिरीक्षक बिजेंद्र सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि मेहरचंद होडल-पलवल रोड स्थित शेरे पंजाब नामक होटल की आड़ में अवैध रूप से चूरा पोस्त की बिक्री कर रहा है। सूचना में यह भी बताया गया था कि आरोपी ने होटल के एक कमरे में भारी मात्रा में नशीला पदार्थ छिपाकर रखा हुआ है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने तत्काल छापेमारी की। मौके पर राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में नियमानुसार तलाशी ली गई।

तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 3 किलो 450 ग्राम चूरा पोस्त बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया और नशीले पदार्थ को जब्त कर लिया। पूछताछ के दौरान पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी यह नशीला पदार्थ कहां से लाता था और किन लोगों को इसकी सप्लाई करता था। साथ ही इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है।

चानौत में पानी के लिए 51वें दिन आंदोलन तेज, ट्रैक्टर पर जलघर पहुंचीं कुमारी सैलजा

टी-कनेक्शन से पेयजल की मांग को लेकर ग्रामीणों ने ट्रैक्टर मार्च और मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया

भारतेंदु संवाददाता, हांसी

हरियाणा के चानौत गांव में टी कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने की मांग को लेकर पिछले 51 दिनों से चल रहा ग्रामीणों का आंदोलन शुक्रवार को नए चरण में पहुंच गया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा सांसद कुमारी सैलजा आंदोलन में शामिल होने के लिए धरनास्थल पहुंचीं।

उन्होंने ग्रामीणों के समर्थन में ट्रैक्टर पर सवार होकर ट्रैक्टर मार्च में हिस्सा लिया और सरकार से गांव की लंबे समय से लंबित मांग को जल्द पूरा करने की अपील की। शुक्रवार को आयोजित ट्रैक्टर मार्च में सैकड़ों ट्रैक्टर तिरंगों से सजाकर निकाले गए। यह काफिला खरकड़ी चौक से शुरू होकर जलघर तक पहुंचा। इसके बाद कुमारी सैलजा ग्रामीणों के साथ पैदल मार्च करते हुए वापस धरनास्थल लौटीं।

पूरे मार्ग पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और पानी की मांग को लेकर नारेबाजी करते रहे। आंदोलन के दौरान गांव में एकजुटता का अनोखा दृश्य भी देखने को मिला। बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने हाथों में हाथ डालकर मानव श्रृंखला बनाई। इस मानव श्रृंखला के माध्यम से ग्रामीणों ने अपने अधिकारों के लिए एकजुट रहने का संदेश दिया। आंदोलन में 36 बिरादरी के लोगों के अलावा विभिन्न खापों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और ग्रामीणों की मांग का समर्थन किया।

धरनास्थल पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कुमारी सैलजा ने कहा कि स्वच्छ पेयजल प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है। यदि किसी गांव के लोग अपने अधिकार के लिए 51 दिनों तक लगातार धरने पर बैठे हैं तो यह सरकार के लिए गंभीर चिंतन का विषय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब 36 इंच की मुख्य पाइपलाइन गांव से होकर गुजर रही है, तब चानौत को टी-कनेक्शन देने में आखिर देरी क्यों की जा रही है।

सैलजा ने आरोप लगाया कि सरकार को जनता की बुनियादी समस्याओं के समाधान पर प्राथमिकता से काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की मांग पूरी तरह जायज है और इसे अनावश्यक रूप से लंबित रखना उचित नहीं है। उन्होंने प्रशासन से तुरंत सकारात्मक पहल करते हुए गांव को टी कनेक्शन उपलब्ध कराने और पेयजल संकट का स्थायी समाधान निकालने की मांग की। समाधान को लेकर ग्रामीणों ने दबाव बनाए रखने की बात कही। ट्रैक्टर मार्च के बाद गांव में माहौल और गर्म हो गया।

मानसिक तनाव से परेशान युवक ने बहन के ससुराल में की आत्महत्या

भारतेंदु संवाददाता, चरखी दादरी। हरियाणा के चरखी दादरी जिले के गांव खातीवास में शनिवार अलसुबह एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतरवाकर कब्जे में लिया तथा पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया। पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। मृतक की पहचान महेंद्रगढ़ जिले के गांव जाटवास निवासी कर्मबीर के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार कर्मबीर के माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका था। इसके बाद वह अपनी बहनों के पास रहकर जीवनयापन कर रहा था। बताया जा रहा है कि वह इन दिनों अपनी बहन की ससुराल, गांव खातीवास में रह रहा था। जानकारी के अनुसार शनिवार तड़के करीब चार बजे कर्मबीर घर के समीप बने टीन शेड में गया। कुछ देर बाद उसने वहीं फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह जब परिजनों की नजर उस पर पड़ी तो वह फंदे से लटका हुआ मिला। यह दृश्य देखकर परिवार के लोगों के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत डायल 112 पर फोन कर पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास मौजूद लोगों से भी जानकारी जुटाई। इसके बाद शव को नीचे उतरवाकर पंचनामा की कार्रवाई पूरी की गई और पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। परिजनों का कहना है कि कर्मबीर पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। हालांकि, उसने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया, इसका स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आया है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि परिजनों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सहित अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस को मौके से किसी प्रकार का सुसाइड नोट मिलने की सूचना नहीं है। मामले की जांच जारी है।पुलिस ने बताया कि मामले में सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

न्यूज ब्रीफ

पंचकूला में युवक की हत्या, कुछ घंटे बाद दोस्त का शव भी मिला

भारतेंदु संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा के पंचकूला के सेक्टर-19 में शुक्रवार देर रात दो युवकों की हत्या से सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान 20 वर्षीय संजीत और उसके दोस्त अर्जुन के रूप में हुई है। पहले देर रात संजीत का शव धारदार हथियार से हमला किए जाने के बाद बरामद हुआ। शुरुआती जांच में पुलिस को पुरानी रंजिश के चलते हत्या किए जाने की आशंका है। घटना के कुछ घंटे बाद शनिवार सुबह करीब चार बजे उसी स्थान से अर्जुन का शव भी मिला। शुरुआत में पुलिस को संजीत की हत्या में अर्जुन की भूमिका पर संदेह था, लेकिन उसकी भी हत्या होने के बाद मामला और उलझ गया है। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर जांच तेज कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है और जल्द ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा।

करनाल में तेज रफ्तार ट्रक ने दो युवकों को कुचला, दोनों की मौत

भारतेंदु संवाददाता, करनाल। हरियाणा के करनाल में नमस्ते चौक के पास शनिवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक अपनी बाइक के पास खड़े होकर कुछ खाने-पीने के लिए रुके थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। हादसा इतना भीषण था कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। पुलिस ने ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। मामले की जांच जारी है।

भाजपा नेता की फैक्ट्री में लगी आग कैमिकल ड्रम सुरक्षित बाहर निकाले

भारतेंदु संवाददाता, करनाल। भाजपा नेता की फैक्ट्री में शनिवार को अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें और काला धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देने से आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। फैक्ट्री में रखे कैमिकल ड्रमों के कारण बड़े हादसे की आशंका थी। एहतियात के तौर पर दमकल कर्मियों ने ड्रमों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे संभावित विस्फोट टल गया। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस और संबंधित विभाग मामले की जांच कर रहे हैं तथा नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

युवक ने सल्फास खाकर की आत्महत्या मनसरोवर पार्क में मिला शव

भारतेंदु संवाददाता, रोहतक। शहर के मानसरोवर पार्क में शनिवार को एक युवक मृत अवस्था में मिला। सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। मृतक की उम्र करीब 25 वर्ष बताई जा रही है। घटनास्थल से सल्फास की खाली डिब्बी बरामद होने के बाद पुलिस प्रारंभिक तौर पर आत्महत्या की आशंका जता रही है। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और अन्य थानों को भी सूचना भेजी गई है। शव की शिनाख्त के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृतक की पहचान होने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है तथा परिजनों की तलाश जारी है।

रेता-बजरी से भरा ट्रक खाली करते समय दबकर हेल्पर की मौत

भारतेंदु संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के सेक्टर-113 स्थित रेता बजरी के स्टॉक पॉइंट पर ट्रक खाली करते समय हुए हादसे में एक हेल्पर की मौत हो गई। मृतक की पहचान 16 वर्षीय प्रियांशु, निवासी जिला नैनीताल के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पिता की शिकायत पर ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत के अनुसार, रात ट्रक बजरी लेकर स्टॉक पॉइंट पहुंचा था। चालक ने प्रियांशु को ट्रक का डाला खोलने के लिए कहा। डाला खुलते ही बजरी उसके पैरों पर गिर गई। प्रियांशु ने कई बार चालक को आवाज लगाई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और ट्रक को ऊपर उठाकर पूरी बजरी खाली कर दी। इससे वह बजरी के नीचे दब गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

सिरसा में चारा काटते समय करंट लगने से दो दोस्तों की मौत, गांव में पसरा मातम

भारतेंदु संवाददाता, सिरसा

हरियाणा के सिरसा जिले में शनिवार को एक दर्दनाक हादसे में करंट लगने से दो दोस्तों की मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक दोनों युवक अपने-अपने परिवार के इकलौते बेटे थे, जिससे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार, दोनों युवक खेत में चारा काटने के लिए मशीन चला रहे थे।

इसी दौरान मशीन में अचानक बिजली का करंट उतर आया। करंट की चपेट में आने से दोनों युवक गंभीर रूप से झुलस गए। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि मशीन में तकनीकी खराबी या बिजली के तार में लीकेज के कारण करंट फैला।

पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही बिजली विभाग से भी तकनीकी रिपोर्ट मांगी गई है। हादसे के बाद गांव में मातम का माहौल है। दोनों युवक बचपन से अच्छे दोस्त थे और अक्सर खेती के कार्य साथ मिलकर किया करते थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक साथ काम करते हुए दोनों की जिंदगी इस तरह खत्म हो जाएगी।

परिजनों का कहना है कि दोनों परिवारों की सारी उम्मीदें इन्हीं बेटों पर टिकी थीं। ग्रामीणों ने प्रशासन से हादसे की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों या जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

स्कूल के पास कार छोड़ लापता शिक्षक चाचा के घर से सकुशल बरामद हुए

भारतेंदु संवाददाता, करनाल

हरियाणा में रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुए एक सरकारी शिक्षक आखिरकार अपने चाचा के घर से सकुशल बरामद हो गए। शिक्षक के मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली है। हालांकि, इस पूरे मामले ने नया मोड़ तब ले लिया जब शिक्षक द्वारा छोड़े गए एक नोट में एसडीएम पर धमकाने का गंभीर आरोप लगाया गया।

जानकारी के अनुसार, शिक्षक अपनी कार स्कूल के पास छोड़कर अचानक लापता हो गए थे। कार मिलने के बाद पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की। जांच के दौरान सामने आया कि शिक्षक ने अपनी पहचान छिपाने और लोकेशन बदलने के लिए लगातार दो रिक्शों का इस्तेमाल किया। इसके बाद वह अपने चाचा के घर पहुंच गए, जहां से पुलिस ने उन्हें सुरक्षित बरामद कर लिया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि शिक्षक ने जाने से पहले एक नोट छोड़ा था। इस नोट में उन्होंने एक एसडीएम पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और धमकाने का आरोप लगाया है।

नोट मिलने के बाद पुलिस ने उसे जांच के दायरे में शामिल कर लिया है और उसके आधार पर पूरे घटनाक्रम की पड़ताल की जा रही है। फिलहाल शिक्षक सुरक्षित हैं और पुलिस उनसे पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि सभी तथ्यों की निष्पक्ष जांच की जाएगी और यदि किसी अधिकारी की भूमिका सामने आती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि मामले के हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है।

हांसी में लेनदेन विवाद से आहत किसान ने जहर निगला, इलाज के दौरान मौत

भारतेंदु संवाददाता, हांसी

हरियाणा के हांसी क्षेत्र में लेनदेन के विवाद से परेशान एक किसान ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मृतक के पास से मिले सुसाइड नोट को अपने कब्जे में लेकर जांच का हिस्सा बनाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, किसान का कुछ लोगों के साथ पैसों के लेनदेन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। परिजनों का आरोप है कि विवाद के दौरान आरोपियों ने किसान के साथ मारपीट भी की थी, जिससे वह मानसिक रूप से काफी परेशान था। इसी तनाव के चलते उसने जहरीला पदार्थ निगल लिया।

किसान की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया, लेकिन डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। किसान की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। जांच के दौरान पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, नोट में किसान ने अपनी परेशानी और कुछ लोगों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। हालांकि, पुलिस का कहना है कि सुसाइड नोट की सत्यता और उसमें लिखी बातों की जांच की जा रही है।

पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर लिए हैं और मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, सुसाइड नोट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि जांच में किसी की भूमिका सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच और सुसाइड नोट में दर्ज तथ्यों के आधार पर पूरे मामले की गहन जांच की जाएगी।

जमानत पर घर लौटे युवक पर चाकुओं से हमला, पांच जगह किए वार

भारतेंदु संवाददाता, जींद

हरियाणा के जींद जिले में जमानत पर घर लौटे एक युवक पर अज्ञात हमलावरों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके शरीर पर चाकू के पांच गहरे घाव मिले हैं। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, युवक शनिवार रात खाना खाने के बाद घर से टहलने के लिए निकला था। इसी दौरान रास्ते में कुछ अज्ञात लोगों ने उसे घेर लिया और उस पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। आसपास के लोगों ने घायल युवक को लहूलुहान हालत में देखा और तुरंत परिजनों को सूचना दी। परिजन युवक को तत्काल नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के अनुसार युवक के शरीर पर पांच चाकू के घाव पाए गए हैं और उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया।

पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ साथ आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगालनी शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि हमलावरों की पहचान कर जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। हमले के पीछे की वजह का पता लगाने के लिए पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।

अलमारी में छिपे मिले नाबालिग, कोठी मालिक ने डंडों से की पिटाई

भारतेंदु संवाददाता ,सोनीपत। हरियाणा के सोनीपत में बंद पड़ी एक कोठी में घुसने के आरोप में दो नाबालिगों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, दोनों नाबालिग गेट फांदकर कोठी के अंदर घुस गए थे। इस दौरान कोठी में मौजूद लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और चोरी का आरोप लगाते हुए डंडों से बेरहमी से पीटा। एक नाबालिग को जमीन पर गिराकर उसके हाथ, पैर और सिर पर कई वार किए गए। मारपीट के दौरान वह दर्द से चीखता-चिल्लाता रहा। बताया जा रहा है कि दूसरा नाबालिग घर के अंदर एक अलमारी में छिपा हुआ था। उसे भी बाहर निकालकर पीटा गया। कोठी मालिक के भतीजे का दावा है कि पूछताछ में दोनों ने तीन अन्य साथियों के सुभाष चौक पर होने की बात बताई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों नाबालिगों को अपने साथ ले गई। मामले की जांच जारी है।

हरियाणा में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के नए नियम, रोज मिलेंगे सिर्फ 20 टोकन

रैंडम सिस्टम लागू होने से वीआईपी ट्रीटमेंट और एजेंटों की मनमानी पर रोक लगेगी, सभी को मिलेगा समान अवसर

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़

हरियाणा सरकार ने संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और समयबद्ध बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रदेशभर के तहसील और उप-मंडल स्तर के पंजीकरण कार्यालयों में अब प्रतिदिन अधिकतम 20 टोकन ही जारी किए जाएंगे।

सरकार का उद्देश्य रजिस्ट्री प्रक्रिया में होने वाली देरी को समाप्त करना, आम लोगों को समान अवसर उपलब्ध कराना और वीआईपी संस्कृति पर रोक लगाना है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने इस संबंध में सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश जारी करते हुए नई व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के लिए कहा है। विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यह नई टोकन-आधारित व्यवस्था प्रदेश की सभी तहसीलों और उप-मंडल स्तर के पंजीकरण कार्यालयों में तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। हालांकि, उपतहसीलों में पहले की तरह संपत्ति पंजीकरण का कार्य जारी रहेगा और वहां की मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक पंजीकरण कार्यालय में प्रतिदिन अधिकतम 20 अपॉइंटमेंट टोकन ही जारी किए जाएंगे। इन टोकनों का वितरण पूरी तरह रैंडम आधार पर होगा। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार के पक्षपात, सिफारिश या वीआईपी ट्रीटमेंट की संभावना को समाप्त करना है।

सरकार का मानना है कि इससे सभी आवेदकों को समान अवसर मिलेगा और संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बन सकेगी। नई व्यवस्था सेल डीड (बिक्री विलेख) के साथ-साथ अन्य संपत्ति संबंधी दस्तावेजों के पंजीकरण पर भी लागू होगी। विभाग ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रत्येक पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करना सुनिश्चित करें, ताकि लोगों को अनावश्यक इंतजार न करना पड़े और कार्यालयों में लंबित मामलों की संख्या भी कम हो।

सरकार का मानना है कि टोकन प्रणाली लागू होने से पंजीकरण कार्यालयों में लगने वाली भीड़ पर प्रभावी नियंत्रण होगा। अब लोगों को घंटों लाइन में खड़े रहने या पूरे दिन अपनी बारी का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे कार्यालयों में कामकाज भी अधिक व्यवस्थित ढंग से संचालित किया जा सकेगा और कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव भी कम होगा। नई व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य उन एजेंटों और बिचौलियों पर अंकुश लगाना भी है, जो जल्दी अपॉइंटमेंट या प्राथमिकता दिलाने का झांसा देकर लोगों से अतिरिक्त पैसे वसूलते हैं। रैंडम टोकन प्रणाली लागू होने के बाद इस प्रकार की अनियमितताओं पर रोक लगने की उम्मीद है। इससे आम नागरिकों को राहत मिलेगी और भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी कम होंगी।

राजस्व विभाग का कहना है कि नई व्यवस्था की नियमित निगरानी की जाएगी। यदि किसी कार्यालय में नियमों का उल्लंघन या पक्षपात की शिकायत मिलती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सरकार का विश्वास है कि इस सुधार से संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक हितैषी बनेगी तथा लोगों को समय पर और बिना किसी भेदभाव के बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नई व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न होने दी जाए।

नशीला पदार्थ सुंघाकर बहू से दुष्कर्म का आरोप, ससुर के खिलाफ कार्रवाई

भारतेंदु संवाददाता ,पानीपत

हरियाणा के पानीपत में एक नवविवाहिता ने अपने ससुर पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी ससुर के साथ-साथ पति, सास और ननद के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

शिकायत के अनुसार, शादी के कुछ ही दिन बाद आरोपी ससुर ने कथित तौर पर पीड़िता को नशीला पदार्थ सुंघाकर कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता का आरोप है कि घटना के बाद जब उसने विरोध किया और परिवार के अन्य सदस्यों को इसकी जानकारी दी, तो किसी ने उसकी मदद नहीं की। इसके बजाय उसे चुप रहने के लिए धमकाया गया और मामला बाहर न बताने का दबाव बनाया गया। पीड़िता का कहना है कि उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया और उसे कई दिनों तक एक कमरे में बंद रखकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया।

लगभग एक महीने बाद उसे कमरे से बाहर निकलने का मौका मिला। इसी दौरान उसे किसी तरह एक मोबाइल फोन मिला, जिससे उसने अपनी छोटी बहन को फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों की मदद से वह पुलिस तक पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर ससुर, पति, सास और ननद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है और मामले से जुड़े सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच जारी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है। आरोपितों से पूछताछ की जाएगी और पीड़िता के बयान सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

दिल्ली में अस्थायी जल संकट, लोगों को पानी स्टोर करने की सलाह

मुरादनगर इंटरकनेक्शन कार्य से दिल्ली में पानी की सप्लाई ठप,कई इलाकों में जल आपूर्ति बाधित

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी में पानी की आपूर्ति को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। गाजियाबाद के पास स्थित मुरादनगर क्षेत्र में पाइपलाइन इंटरकनेक्शन का आवश्यक कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में जल आपूर्ति प्रभावित रहने की संभावना जताई गई है। यह कार्य जल वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने और भविष्य में निर्बाध पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस तकनीकी कार्य के चलते कई क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति अस्थायी रूप से बाधित रहेगी।

जल बोर्ड ने बताया है कि यह कार्य 6 जुलाई की सुबह से शुरू होकर 7 जुलाई की शाम तक चल सकता है, जिसके दौरान लगभग 24 से 36 घंटे तक पानी की कमी महसूस की जा सकती है। इस अवधि में लोगों को पानी के उपयोग में सावधानी बरतने और पहले से पर्याप्त भंडारण करने की सलाह दी गई है। प्रभावित क्षेत्रों में दिल्ली के कई प्रमुख आवासीय और व्यावसायिक इलाके शामिल बताए जा रहे हैं। इनमें दक्षिण, पश्चिम और पूर्वी दिल्ली के कुछ हिस्सों के साथ-साथ एनसीआर के सीमावर्ती क्षेत्र भी शामिल हैं। इन इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों को अस्थायी जल संकट का सामना करना पड़ सकता है।

जल बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह कार्य आवश्यक रखरखाव और नई पाइपलाइन को जोड़ने के लिए किया जा रहा है, जिससे भविष्य में जल आपूर्ति और अधिक सुचारु हो सकेगी। अधिकारियों का कहना है कि कार्य पूरा होने के बाद पानी की सप्लाई सामान्य हो जाएगी और धीरे धीरे सभी प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य

जल आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। इस दौरान टैंकरों की सहायता से कुछ क्षेत्रों में वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा सकती है ताकि लोगों को गंभीर परेशानी का सामना न करना पड़े। दिल्ली जल बोर्ड ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि वे इस अवधि में पानी का संयमित उपयोग करें और अनावश्यक खर्च से बचें।

साथ ही, पहले से पानी संग्रहित कर लें ताकि असुविधा कम से कम हो सके। प्रशासन का कहना है कि यह अस्थायी असुविधा भविष्य में बेहतर जल आपूर्ति व्यवस्था के लिए आवश्यक है और इससे लंबे समय तक लाभ मिलेगा। जल आपूर्ति बाधित होने से लोगों को अस्थायी परेशानी हो। जल बोर्ड ने सलाह दी है कि नागरिक पहले से पानी संग्रह करें और इसका सीमित उपयोग करें ताकि समस्या कम हो सके।

सीएम योगी के हाथों होगा किसानों को प्लॉट का वितरण

एजेंसी ,नई दिल्ली

यमुना प्राधिकरण किसानों को देगा 5100 प्लॉट

यमुना प्राधिकरण ने जल्द ही कई गांवों के किसानों को सात प्रतिशत विकसित आबादी भूखंड देने की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों से 5100 किसानों को प्लॉट के आवंटन पत्र दिलाने की योजना है। इस योजना के तहत विभिन्न गांवों के पात्र किसानों को लंबे समय से प्रतीक्षित भूमि अधिकार प्रदान किए जाएंगे। प्राधिकरण का उद्देश्य किसानों को उनकी आबादी भूमि का नियमित और पारदर्शी आवंटन सुनिश्चित करना है। इस कदम से क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलेगी और किसानों की समस्याओं का समाधान होगा।

यमुना प्राधिकरण लगातार भूमि आवंटन प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने पर काम कर रहा है। इससे किसानों में संतोष और विश्वास बढ़ेगा तथा सरकारी योजनाओं पर भरोसा मजबूत होगा। प्राधिकरण ने आश्वासन दिया है कि सभी पात्र किसानों को समय पर भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना को लेकर गांवों में सकारात्मक माहौल है और लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। सरकार का मानना है कि यह पहल ग्रामीण विकास और भूमि सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। आने वाले समय में अन्य जिलों में भी इसी प्रकार की योजनाएं लागू किए जाने की संभावना है। इससे राज्य में भूमि वितरण प्रणाली और अधिक पारदर्शी और प्रभावी होने की उम्मीद है। किसानों को मिलने वाले इस लाभ से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने की संभावना जताई जा रही है। यमुना प्राधिकरण ने कहा है कि सभी प्रक्रियाएं निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी की जाएंगी। यह योजना किसानों के हित में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

गाजियाबाद पुलिस का बड़ा खुलासा,क्राइम पेट्रोल देखकर लिव-इन पार्टनर की हत्या

एजेंसी ,नई दिल्ली

दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां के रामपार्क कॉलोनी में एक महिला ने अपनी बहन के साथ मिलकर अपने लिव-इन पार्टनर की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस जांच में जो खुलासा हुआ, उसने सबको चौंका दिया है।

महिला पिछले कुछ समय से अपने इस पार्टनर के साथ लिव-इन में रह रही थी। महिला को काफी दिनों से शक था कि उसका प्रेमी उसकी नाबालिग बेटी पर बुरी नजर रखता है। बेटी की सुरक्षा को लेकर वह लगातार चिंतित थी। इसी शक और डर के चलते उसने अपने रास्ते से प्रेमी को हटाने का खौफनाक फैसला कर लिया। पुलिस के मुताबिक, इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए महिला ने टीवी शो 'क्राइम पेट्रोल' का सहारा लिया। उसने शो देखकर हत्या को आत्महत्या का रूप देने की पूरी साजिश रची, ताकि वह पुलिस की नजरों से बच सके। योजना के तहत महिला ने अपनी बहन को बुलाया और दोनों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद शव को इस तरह ठिकाने लगाने की कोशिश की जिससे मामला आत्महत्या का लगे। हालांकि, पुलिस की मुस्तैदी और बारीकी से की गई तफ्तीश के आगे यह साजिश टिक नहीं सकी।

न्यूज ब्रीफ

नोएडा एयरपोर्ट की नई उड़ान, अब श्रीनगर तक कनेक्टिविटी हुई आसान

एजेंसी ,नई दिल्ली नोएडा एयरपोर्ट से आज से श्रीनगर के लिए हवाई सेवाएं शुरू होने जा रही हैं जिससे यात्रियों को एक नई सुविधा का लाभ मिलेगा। हालांकि फिलहाल इस रूट पर कोई सीधी उड़ान उपलब्ध नहीं है। यात्रियों को यात्रा के दौरान बीच में विमान बदलना होगा यानी कनेक्टिंग फ्लाइट के माध्यम से श्रीनगर तक पहुंचना संभव होगा। इससे उन यात्रियों को राहत मिलेगी जो व्यापार, पर्यटन या निजी कारणों से कश्मीर की यात्रा करना चाहते हैं। इस नई सेवा के शुरू होने से नोएडा एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी धीरे धीरे देश के विभिन्न हिस्सों से मजबूत हो रही है। अधिकारियों के अनुसार आने वाले समय में सीधे उड़ानें शुरू करने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है जिससे यात्रा और आसान हो जाएगी। अभी यात्रियों को दिल्ली या अन्य बड़े हब एयरपोर्ट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और वे नोएडा एयरपोर्ट से ही अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एयरपोर्ट का उद्घाटन 28 मार्च को किया था और तभी से इसके संचालन और विस्तार की योजनाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं। सरकार का उद्देश्य इस एयरपोर्ट को एक प्रमुख एविएशन हब के रूप में विकसित करना है। इससे न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी बल्कि क्षेत्रीय आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि उड़ानों की संख्या और नए रूट्स को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा ताकि यात्रियों को अधिक विकल्प मिल सकें। श्रीनगर रूट की शुरुआत इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और आने वाले समय में इसमें और सुधार की उम्मीद है।

सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी शिक्षा व्यवस्था पर संकट

एजेंसी, नई दिल्ली सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी का संकट लगातार गहराता जा रहा है। हजारों पद खाली होने के कारण शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ रहा है। स्थिति यह है कि कई स्कूलों में एक ही शिक्षक पूरे स्कूल की जिम्मेदारी संभाल रहा है, जिससे पढ़ाई की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। एकल शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, जो चिंता का विषय है।रिपोर्ट के अनुसार हर चौथे वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षक का पद खाली पड़ा है, जिससे विषयवार पढ़ाई सही तरीके से नहीं हो पा रही है। विज्ञान, गणित और अंग्रेजी जैसे महत्वपूर्ण विषयों में सबसे ज्यादा कमी देखी जा रही है। इससे छात्रों की परीक्षा परिणाम और सीखने की क्षमता पर भी असर पड़ रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नई भर्ती प्रक्रिया पर काम चल रहा है, लेकिन प्रक्रिया धीमी होने के कारण समस्या बनी हुई है। कई स्थानों पर अस्थायी व्यवस्था के तहत अतिथि शिक्षकों से काम चलाया जा रहा है, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं माना जा रहा। अभिभावकों और शिक्षा विशेषज्ञों ने इस स्थिति पर चिंता जताई है और जल्द से जल्द स्थायी शिक्षकों की भर्ती की मांग की है।

रामचरितमानस गायब होने पर सियासी हलचल,जांच की मांग तेज

एजेंसी ,नई दिल्ली

अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि भगवान राम को चढ़ाई गए एक किलो सोने की रामचरितमानस भी गायब हो गई है उन्होंने इस मामले को महापाप करार दिया है यह बयान दिल्ली के राजनीतिक माहौल में चर्चा का विषय बन गया है अरविंद केजरीवाल के अनुसार यह घटना धार्मिक आस्था से जुड़ी बेहद गंभीर बात है और इसकी जांच होनी चाहिए उनके इस दावे के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है कुछ लोगों ने इसे चिंता जनक बताया है जबकि कुछ ने राजनीतिक बयान करार दिया है फिलहाल इस मामले में किसी आधिकारिक जांच की पुष्टि नहीं हुई है प्रशासन ने भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा होने के कारण संवेदनशील बना हुआ है विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे दावों की सत्यता की जांच जरूरी होती है

ताकि किसी प्रकार की गलत सूचना न फैले आने वाले समय में इस विषय पर और स्पष्टता आने की संभावना है सरकार से अपेक्षा की जा रही है। कि वह इस मामले पर स्थिति स्पष्ट करे और आवश्यक कदम उठाए इस घटना ने राजनीतिक और धार्मिक दोनों स्तरों पर चर्चा को जन्म दिया है और लोग लगातार अपडेट का इंतजार कर रहे हैं मीडिया में भी यह खबर प्रमुख रूप से चल रही है आगे की स्थिति जांच रिपोर्ट पर निर्भर करेगी प्रशासनिक सूत्र स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं ।

नोएडा में विकास की रफ्तार तेज सलारपुर में जल्द बनेंगे दो पुल

एजेंसी ,नई दिल्ली

नोएडा के सलारपुर क्षेत्र में नाले पर बन रहे दो पुलों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। प्राधिकरण की बैठक में यह बताया गया कि दोनों पुलों का तीस प्रतिशत काम पूरा हो गया है। इस साल नवंबर तक ये बनकर तैयार हो जाएंगे। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार निर्माण कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि लोगों को यातायात में सुविधा मिल सके। इन पुलों के बन जाने से सलारपुर और आसपास के क्षेत्रों में जाम की समस्या काफी हद तक कम होने की उम्मीद है।

प्राधिकरण ने बताया कि परियोजना पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और गुणवत्ता मानकों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि समय पर कार्य पूरा करना प्राथमिकता है ताकि नागरिकों को जल्द से जल्द लाभ मिल सके।

इसके अलावा स्थानीय लोगों ने भी निर्माण कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है और इसे उपयोगी परियोजना बताया है। आने वाले समय में इन पुलों के शुरू होने से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना जताई जा रही है। प्राधिकरण ने जनता से अपील की है कि निर्माण स्थल के आसपास सुरक्षा नियमों का पालन करें और सहयोग बनाए रखें।

पूरे प्रोजेक्ट को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि यह क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा और लंबे समय तक लोगों को लाभ देगा। प्राधिकरण ने कहा कि परियोजना निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरी की जाएगी। इन पुलों के बनने से सलारपुर क्षेत्र में यातायात व्यवस्था और अधिक सुगम होगी तथा आसपास के इलाकों में कनेक्टिविटी मजबूत होगी। स्थानीय लोगों को जाम से राहत मिलेगी और यात्रा का समय भी कम होगा जिससे रोजगार की आवाजाही आसान हो जाएगी।

नजारत घोटाला मामला,अगली सुनवाई 7 जुलाई को तय

एजेंसी, नई दिल्ली

गाजियाबाद में 6.50 करोड़ रुपये के नजारत घोटाला मामले में बीस से अधिक आरोपी अदालत में पेश हुए सुनवाई के दौरान राजू शर्मा का बयान दर्ज किया गया मामले की अगली सुनवाई सात जुलाई को होगी यह घोटाला वर्ष 2001 से 2007 के बीच हुआ था और इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई द्वारा की जा रही है जिसमें सत्तर लोगों पर आरोप पत्र दाखिल किया गया है अदालत में सभी आरोपियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और मामले की कार्यवाही आगे बढ़ी पुलिस और सीबीआई दोनों ने साक्ष्यों को मजबूत करने पर जोर दिया यह मामला लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन है और इसमें कई दस्तावेज प्रस्तुत किए जा चुके हैं अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि सात जुलाई निर्धारित की है आरोपियों से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच जारी है और सुनवाई नियमित रूप से चल रही है ।

वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था समाप्त, सरकारी दफ्तरों के समय में भी होगा बदलाव

एजेंसी ,नई दिल्ली

दिल्ली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू की गई वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था समाप्त करने का फैसला लिया है। मई महीने से लागू यह व्यवस्था अब खत्म कर दी गई है और कर्मचारियों को नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य करना होगा। सरकार ने यह निर्णय प्रशासनिक कार्यों की गति बढ़ाने, विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और कार्यालयों में सामान्य कार्यप्रणाली बहाल करने के उद्देश्य से लिया है।

इससे पहले सरकार ने हर सप्ताह दो दिन वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी थी। इसके साथ ही मेट्रो मंडे पहल भी शुरू की गई थी, जिसके तहत कर्मचारियों को सोमवार के दिन मेट्रो का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। इस पहल का उद्देश्य

सड़क यातायात का दबाव कम करना, प्रदूषण घटाना और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देना था। अब सरकार ने कार्यालयों के कामकाज के समय में भी बदलाव करने का निर्णय लिया है। नए आदेश के अनुसार विभिन्न विभागों के कार्यालय समय में संशोधन किया जाएगा ताकि कर्मचारियों की उपस्थिति बेहतर ढंग से सुनिश्चित की जा सके और कार्यों का निष्पादन अधिक प्रभावी तरीके से हो। इस संबंध में विस्तृत आदेश आज जारी किए जाने की संभावना है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, नए निर्देश लागू होने के बाद सभी विभागों को संशोधित व्यवस्था का पालन करना होगा। कर्मचारियों को भी नए कार्यालय समय और उपस्थिति संबंधी नियमों का पालन करने के निर्देश दिए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इस फैसले से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी, आम लोगों को सरकारी सेवाएं समय पर मिलेंगी और विभागों के बीच समन्वय पहले से अधिक मजबूत होगा।

दिल्ली में आज झमाझम बारिश के आसार,तापमान में आएगी गिरावट

एजेंसी ,नई दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। मौसम विभाग ने क्षेत्र में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत मिलने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज और आने वाले दिनों में आसमान में बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश के साथ बिजली गिरने और आंधी चलने की भी संभावना जताई गई है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में मौसम का यह बदलाव मानसून की सक्रियता के कारण देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि हवा की गति तीस से चालीस किलोमीटर प्रति

दिल्ली में बारिश और आंधी का मौसम अलर्ट

घंटा तक पहुंच सकती है जिससे पेड़ों के गिरने और यातायात प्रभावित होने की आशंका है। नागरिकों को सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने भी चेतावनी जारी की है कि बारिश के समय सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन सकती है और वाहन चालकों को सावधानी से ड्राइव करने की सलाह दी गई है। मौसम में आने वाले परिवर्तन को देखते हुए लोगों से अपील की गई है कि वे मौसम अपडेट पर नजर रखें और सुरक्षित स्थान पर रहें ध्यान रखें सुरक्षा जरूरी है

सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ डीडीए का बड़ा अभियान

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली में अवैध कब्जों के खिलाफ जल्द ही बड़ा बुलडोजर अभियान शुरू होने की तैयारी है। उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को निर्देश दिए हैं कि राजधानी में सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों की पहचान के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाए। इसके तहत ड्रोन सर्वे, रियल टाइम मॉनिटरिंग और डिजिटल मैपिंग जैसी तकनीकों की मदद से विस्तृत सर्वेक्षण कराया जाएगा। उद्देश्य यह है कि सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण की सटीक जानकारी जुटाकर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

डीडीए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सर्वे के दौरान प्रत्येक क्षेत्र का रिकॉर्ड तैयार किया जाए और जहां भी अवैध निर्माण या कब्जा पाया जाए, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाए। प्रशासन का कहना है कि तकनीक के इस्तेमाल से सर्वे अधिक पारदर्शी, तेज और सटीक होगा। इससे जमीन से जुड़े विवादों में भी कमी आने की उम्मीद है और सरकारी संपत्तियों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। सूत्रों के अनुसार, सर्वे की रिपोर्ट मिलने के बाद चिन्हित स्थानों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सभी कदम कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए उठाए जाएंगे और संबंधित पक्षों को नियमानुसार नोटिस भी जारी किए जाएंगे। अभियान का उद्देश्य केवल सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराना और भविष्य में नए अवैध कब्जों को रोकना है।

गृह विभाग को भेजी गई संदिग्धों की सूची,सुरक्षा जांच हुई तेज

रोहिंग्या अभियान के बीच पुलिस के हाथ लगी संदिग्धों की जानकारी

एजेंसी, नई दिल्ली

गुरुग्राम पुलिस को शहर में रह रहे बिहार के लगभग दो दर्जन संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। पुलिस ने इन सभी लोगों की पहचान से जुड़ी प्रारंभिक जानकारी जुटाकर उनकी एक सूची तैयार की है और आगे की जांच एवं सत्यापन के लिए गृह विभाग को भेज दी है। यह मामला उस समय सामने आया, जब पुलिस शहर के विभिन्न इलाकों में रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान और सत्यापन के लिए विशेष अभियान चला रही थी। इसी अभियान के दौरान कुछ ऐसे लोगों की जानकारी मिली, जिनकी पहचान, दस्तावेज और गतिविधियां जांच के दायरे में आ गईं।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इन सभी व्यक्तियों के पहचान पत्र, स्थायी पते, किरायेदारी से जुड़े रिकॉर्ड, मोबाइल नंबर और अन्य दस्तावेजों की बारीकी से सत्यापन किया जा रहा है। फिलहाल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई अंतिम

गुरुग्राम में दो दर्जन संदिग्धों की जांच तेज

निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि उनके दस्तावेज पूरी तरह वैध हैं या उनमें किसी प्रकार की अनियमितता है। पुलिस का कहना है कि सत्यापन प्रक्रिया पूरी तरह कानूनी प्रावधानों के तहत की जा रही है और किसी भी निर्दोष व्यक्ति को परेशान नहीं किया जाएगा। गृह विभाग को भेजी गई सूची के आधार पर संबंधित एजेंसियां अब विस्तृत जांच करेंगी। यदि किसी व्यक्ति के पास फर्जी दस्तावेज, गलत पहचान या कानून का उल्लंघन करने से जुड़े प्रमाण मिलते हैं, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और खुफिया एजेंसियां भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी संभावित सुरक्षा जोखिम को समय रहते रोका जा सके। गुरुग्राम पुलिस ने नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है। अधिकारियों ने मकान मालिकों से कहा है कि वे किरायेदारों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से कराएं और बिना पहचान की पुष्टि किए किसी को भी किराये पर कमरा या मकान न दें। साथ ही, यदि किसी इलाके में कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दें।

रेलवे स्टेशन पर परिवार से कथित मारपीट, किन्नरों पर लगे आरोप

एजेंसी ,नई दिल्ली

पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किन्नरों के एक समूह द्वारा कथित हंगामा किए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्टेशन परिसर में अफरा-तफरी का माहौल दिखाई दे रहा है। वीडियो के आधार पर दावा किया जा रहा है कि किन्नरों के समूह ने एक परिवार के साथ कथित तौर पर बदसलूकी की और उनके साथ मारपीट भी की। हालांकि, घटना के पीछे की पूरी परिस्थितियों और विवाद की वास्तविक वजह की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्टेशन पर किसी बात को लेकर पहले कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते विवाद में बदल गई। आरोप है कि बहस बढ़ने के बाद परिवार के सदस्यों के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की गई। घटना के दौरान आसपास मौजूद यात्रियों की भीड़ जमा हो गई और कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन से इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। यही वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

घटना की सूचना मिलने के बाद रेलवे सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तथा स्थिति को नियंत्रित किया। अधिकारियों ने संबंधित पक्षों से पूछताछ शुरू कर दी है और वायरल वीडियो की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जाएगी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वायरल वीडियो के आधार पर किसी निष्कर्ष पर न पहुंचें और अफवाहें फैलाने से बचें।

न्यूज ब्रीफ

आतंकियों की तलाश में शोपियां में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने के बाद सुरक्षाबलों ने कई गांवों में व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया है। सुरक्षा बलों ने संदिग्ध इलाकों की घेराबंदी कर घर-घर तलाशी शुरू की है और संभावित ठिकानों की गहन जांच की जा रही है। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

पीआईटी-एनडीपीएस के तहत अवंतिपोरा में दो बड़े अपराधी हिरासत में

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के अवंतिपोरा में पुलिस ने आतंकवाद और नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आतंकी मददगार को पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) तथा एक कुख्यात ड्रग तस्कर को पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी लंबे समय से गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल थे।

कठुआ में बढ़ा डेंगू का खतरा, स्वास्थ्य विभाग ने बताए बचाव के जरूरी उपाय

भारतेंदु संवाददाता, कठुआ। मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और बचाव के उपाय अपनाने की अपील की है। विभाग के अनुसार ये वेक्टर जनित रोग मच्छरों के जरिए तेजी से फैलते हैं लेकिन समय रहते सावधानी बरतकर इनसे बचाव संभव है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि घर और आसपास पानी जमा न होने देना सबसे अहम कदम है क्योंकि रुका हुआ पानी मच्छरों के पनपने का मुख्य कारण बनता है।

एसडीआरएफ ने तवी नदी में फंसे चार लड़कों को बचाया

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। शनिवार को पीर खो मंदिर के पास तवी नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने के कारण फंसे चार लड़कों को जम्मू-कश्मीर पुलिस और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) के जवानों की एक टीम ने बचाया। पुलिस ने बताया कि पुलिस नियंत्रण कक्ष के माध्यम से सूचना मिली थी कि पीर खो मंदिर के पास तवी नदी में स्नान कर रहे चार लड़के अचानक जलस्तर बढ़ने के कारण फंस गए थे।

मीरां साहिब में जमीन विवाद में व्यक्ति की हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू के मीरां साहेब क्षेत्र के गैयां गांव में जमीन के विवाद को लेकर एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार सतिंदर कुमार पर शुक्रवार शाम कथित तौर पर दो सगे भाइयों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल सतिंदर कुमार को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने रातभर छापेमारी कर दोनों आरोपियों अजय और विजय पुत्र दर्शन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच जारी है।

आतंकियों व अलगाववादियों के महिमामंडन वाली पुस्तक पर तत्काल रोक की मांग

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने शनिवार को सरकारी स्कूलों के पुस्तकालयों में वितरित एक विवादित पुस्तक पर तुरंत रोक लगाने की मांग की। उन्होंने शिक्षा विभाग पर राष्ट्र विरोधी सामग्री को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए संबंधित पुस्तक को मंजूरी दिए जाने और उसे वितरित करने की उच्चस्तरीय जांच की मांग की। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा नेता सुनील शर्मा ने आरोप लगाया कि पैराडाइज़ पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित किताब 'पर्सनैलिटीज़ एंड लेजेंड्स ऑफ़ जेएंडके' अलगाववादियों, आतंकवादियों और पत्थरबाज़ों का महिमामंडन कर भारत को नकारात्मक रूप में दर्शाती है।

अमरनाथ यात्रा ने पकड़ी रफ्तार, तीसरा जत्था जम्मू से रवाना

पहलगाम और बालटाल मार्ग पर बढ़ी रौनक, अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा 2026 पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ रही है। शनिवार को जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप से श्रद्धालुओं का तीसरा जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पवित्र गुफा की ओर रवाना हुआ। वहीं, दक्षिण कश्मीर के पहलगाम स्थित नुनवान बेस कैंप से दूसरे जत्थे ने भी अपनी पैदल यात्रा शुरू की। यात्रा के दोनों प्रमुख मार्गों—बालटाल और पहलगाम—पर श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों और स्वास्थ्य विभाग ने यात्रा को सुरक्षित, सुचारु और सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के कारण श्रद्धालु खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और प्रशासन की तैयारियों की सराहना कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बलों की तैनाती, नियमित गश्त, निगरानी उपकरणों का उपयोग तथा संवेदनशील स्थानों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके।

यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चिकित्सा सेवाओं को भी विशेष रूप से मजबूत किया गया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी,

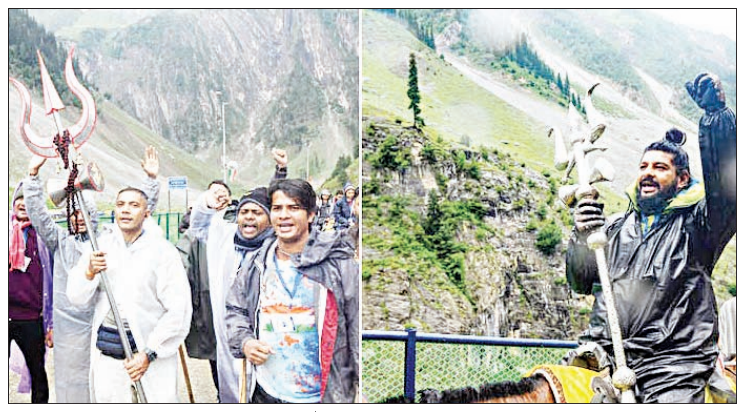

◆ **बारिश और कोहरे के बीच भी नहीं डिगी आस्था**

मौसम में अचानक बदलाव और स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों को देखते हुए उधमपुर स्वास्थ्य विभाग ने जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-44) पर व्यापक चिकित्सा व्यवस्था स्थापित की है। विशेष रूप से टिकरी काली माता मंदिर से चेनानी-नाशरी सुरंग तक के क्षेत्र में मेडिकल टीमें, एंबुलेंस, प्राथमिक उपचार केंद्र और आवश्यक जीवनरक्षक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मचारियों को चौबीसों घंटे तैनात रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर श्रद्धालुओं को तत्काल चिकित्सा सहायता मिल सके।

इसके अलावा यात्रा मार्ग पर स्वच्छ पेयजल, विश्राम स्थल, भोजन, संचार और परिवहन जैसी आवश्यक सुविधाओं का भी पर्याप्त प्रबंध किया गया है। शुक्रवार को बालटाल मार्ग से रवाना हुए पहले जत्थे के कई श्रद्धालु पवित्र अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन कर लौट आए। लौटने वाले श्रद्धालुओं के चेहरों पर गहरी आस्था, संतोष और आध्यात्मिक आनंद साफ दिखाई दे रहा था। श्रद्धालुओं ने बताया कि इस वर्ष पवित्र हिम शिवलिंग अपने पूर्ण स्वरूप में विराजमान है, जिसके दर्शन करना उनके जीवन का अत्यंत सौभाग्यपूर्ण क्षण रहा।

कई श्रद्धालुओं ने कहा कि उन्हें पहली आरती और प्रथम पूजा में शामिल होने का अवसर मिला, जो उनके लिए अविस्मरणीय अनुभव बन गया। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान तेज बारिश, घना कोहरा और कठिन चढ़ाई जैसी चुनौतियां जरूर सामने आईं, लेकिन भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास ने हर कठिनाई को आसान बना दिया।

श्रद्धालुओं में उमड़ा आस्था का सैलाब

श्रद्धालुओं का कहना था कि बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन के बाद सारी थकान पल भर में दूर हो गई और उन्हें अद्भुत मानसिक शांति तथा आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव हुआ। पहले जत्थे में शामिल श्रद्धालु पंकज सावंत ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि वे सुबह लगभग पांच बजे यात्रा के लिए निकले थे। खराब मौसम और फिसलन भरे रास्तों के बावजूद उन्होंने पूरे उत्साह के साथ यात्रा जारी रखी। सुबह करीब नौ बजे जब वे पवित्र गुफा पहुंचे तो वहां श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम थी।

राजौरी में माइन ब्लास्ट, भारतीय सेना का जवान घायल

भारतेंदु संवाददाता, राजौरी। राजौरी जिले के नौशहरा के झांगड़ सेक्टर में एलओसी के पास गश्त के दौरान माइन ब्लास्ट में भारतीय सेना की 14 असम यूनिट के नायब सूबेदार हितेश्वर गोगोई घायल हो गए। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद कमांड अस्पताल उधमपुर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार सेना की टीम झांगड़ के अग्रिम इलाके में नियमित पेट्रोलिंग और क्षेत्र की निगरानी कर रही थी। इसी दौरान अचानक जोरदार विस्फोट हुआ। इसमें नायब सूबेदार हितेश्वर घायल हो गए। विस्फोट के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई और सेना ने तत्काल पूरे क्षेत्र को घेरकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। सेना के अधिकारियों ने बताया कि घायल अधिकारी को पहले नजदीकी सैन्य चिकित्सा केंद्र पहुंचाया गया, जहां से कमांड अस्पताल उधमपुर भेजा गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक यह विस्फोट पुराने लैंडमाइन या गश्त मार्ग में मौजूद विस्फोटक सामग्री के कारण हो सकता है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे इलाके की जांच कर रही हैं ताकि किसी अन्य संभावित खतरे को समय रहते निष्क्रिय किया जा सके।

कश्मीर में बच्चे के वायरल वीडियो पर भड़के मीरवाइज उमर फारूक

12 साल के बच्चे के वायरल वीडियो ने छेड़ी बहस, शिष्टाचार पर उठे सवाल

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में शिक्षा मंत्री सकीना इटू की आलोचना करते हुए एक 12 वर्षीय बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो में बच्चा घाटी में लगातार बढ़ रही गर्मी और स्कूलों में छुट्टियां घोषित न किए जाने को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त करता दिखाई देता है। वह कहता है कि जब तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है, तब भी बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है।

इसी दौरान उसने शिक्षा मंत्री पर व्यक्तिगत टिप्पणी भी की, जिसके बाद यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर फैल गया और इस पर पक्ष-विपक्ष में बहस शुरू हो गई।

वीडियो सामने आने के बाद कश्मीर के प्रमुख धार्मिक नेता मीरवाइज उमर फारूक ने बच्चे द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा और टिप्पणी को अशिष्ट बताया। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के प्रति सम्मानजनक भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए।

वहीं, जम्मू-कश्मीर सरकार की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (सीडब्ल्यूसी) ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उस न्यूज पोर्टल को तलब किया जिसने सबसे पहले यह वीडियो प्रकाशित किया था।

लद्दाख में पर्यावरण सुरक्षा के लिए 100 पूर्व सैनिकों की तैनाती, ईपीएफ की शुरुआत

भारतेंदु संवाददाता, लेह। लद्दाख के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और उसकी रक्षा करने के उद्देश्य से शुरू की गई अपनी तरह की पहली पहल के तहत शनिवार को 100 पूर्व सैनिकों को लद्दाख पर्यावरण संरक्षण बल (ईपीएफ) में तैनात किया गया।

पूर्व सैनिकों को उनके गंतव्य तक ले जाने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाते हुए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि लद्दाख में दुनिया के सबसे नाजुक उच्च-ऊंचाई वाले पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद हैं और यह कई लुप्तप्राय वन्यजीव प्रजातियों का घर है जिन्हें उच्चतम स्तर की सुरक्षा की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बढ़ते पर्यटन के साथ-साथ पर्यावरणीय जिम्मेदारी भी होनी चाहिए और ईपीएफ मानव गतिविधियों और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लोगों का मार्गदर्शन भी करेगा।

उन्होंने कहा कि ईपीएफ हमारे पूर्व सैनिकों के अनुशासन, ईमानदारी और इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को एकजुट करता है। मुझे विश्वास है कि वे न केवल पर्यावरण और वन्यजीव कानूनों के उल्लंघन को रोकेंगे बल्कि लद्दाख भर में स्वच्छता जैव विविधता संरक्षण और जिम्मेदार पर्यटन के राजदूत भी बनेंगे।

उपराज्यपाल ने ईपीएफ सदस्यों को शपथ भी दिलाई जिसमें लद्दाख के पर्यावरण, जंगलों, वन्यजीवों और जैव विविधता की रक्षा में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने की उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई।

लद्दाख में पर्यावरण संरक्षण के लिए नई पहल

सेना, अर्धसैनिक बलों और लद्दाख स्काउट्स के पूर्व सैनिकों से युक्त ईपीएफ कर्मियों को केंद्र शासित प्रदेश के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा ताकि अवैध ऑफ-रोडिंग की बढ़ती घटनाओं पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। ईपीएफ को मजबूत करने के लिए इन पूर्व सैनिकों को अपने निर्धारित क्षेत्रों में किसी भी ऐसे उल्लंघन के लिए मौके पर ही चालान जारी करने का अधिकार दिया गया है।

सिल्क रूट पर सेना के सहनशक्ति और नेतृत्व की होगी परीक्षा

लद्दाख के ऐतिहासिक सिल्क रूट पर सेना का 12 दिवसीय अभियान शुरू

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

भारतीय सेना ने लद्दाख के ऐतिहासिक पुराने सिल्क रूट पर 12 दिवसीय ग्रीष्मकालीन साहसिक अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 264 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करेगा और 11,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई वाले दुर्गम हिमालयी क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। अत्यधिक ऊंचाई, कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, कम ऑक्सीजन और बदलते मौसम के बीच आयोजित यह अभियान सेना के जवानों की शारीरिक क्षमता, मानसिक दृढ़ता, टीम भावना और नेतृत्व कौशल की कड़ी परीक्षा माना जा रहा है।

अभियान का उद्देश्य केवल कठिन पर्वतीय मार्गों पर सैनिकों की दक्षता को परखना ही नहीं, बल्कि लद्दाख की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को भी नई पीढ़ी के सामने प्रस्तुत करना है। सेना का यह प्रयास दर्शाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ देश

◆ **12 दिन में तय होंगे 264 किलोमीटर**

की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और उनके महत्व को उजागर करने के प्रति भी उसकी गहरी प्रतिबद्धता है।

पुराना सिल्क रूट एशिया के सबसे प्राचीन व्यापारिक मार्गों में गिना जाता है। सदियों पहले इसी मार्ग के जरिए भारत, मध्य एशिया और अन्य क्षेत्रों के बीच व्यापार, संस्कृति, विचारों और सभ्यताओं का आदान-प्रदान होता था। लद्दाख इस ऐतिहासिक मार्ग का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, जहां से व्यापारी ऊन, नमक, मसाले, रेशम और अन्य मूल्यवान वस्तुओं का व्यापार करते थे। इसी कारण यह क्षेत्र केवल सामरिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

भारतीय सेना का यह अभियान उसी गौरवशाली विरासत को याद करते हुए उन प्राचीन रास्तों का अनुसरण कर रहा है, जिन्होंने सदियों तक विभिन्न सभ्यताओं को जोड़ने का कार्य किया। सेना के अधिकारियों के अनुसार इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य जवानों में कठिन परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता विकसित करना, उच्च हिमालयी इलाकों में समन्वय और आपसी सहयोग को मजबूत बनाना तथा लद्दाख की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

कश्मीर में मटन संकट खत्म, पंजाब सरकार ने पशुधन वाहनों से हटाया टैक्स

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से मटन की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण उपभोक्ताओं और कारोबारियों दोनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस संकट की मुख्य वजह पंजाब में जम्मू-कश्मीर जाने वाले पशुधन से लदे वाहनों पर लगाया गया विवादित टैक्स और कथित तौर पर कुछ समूहों द्वारा की जा रही अवैध वसूली थी। इसके चलते बड़ी संख्या में पशुधन से भरे वाहन रास्ते में ही रुक गए थे, जिससे घाटी में मटन की उपलब्धता कम होने लगी और बाजारों में कीमतों पर भी असर पड़ने लगा।

इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए ऑल कश्मीर होलसेल एंड रिटेल मटन डीलर्स एसोसिएशन ने एक समन्वय समिति का गठन किया, जिसने लगातार दस दिनों तक पंजाब में रहकर संबंधित अधिकारियों और सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात की तथा समस्या के समाधान की मांग उठाई। कारोबारियों ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी हस्तक्षेप की अपील की। मुख्यमंत्री ने मामले को प्राथमिकता देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से सीधे बातचीत की और स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर जाने वाले पशुधन वाहनों के

◆ **पंजाब सरकार ने वापस लिया विवादित टैक्स**

पास सभी आवश्यक परमिट और वैध दस्तावेज मौजूद हैं, इसलिए उन पर किसी भी प्रकार का अनधिकृत टैक्स या वसूली उचित नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा कि ये वाहन केवल राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग कर रहे हैं और उन्हें बिना किसी बाधा के अपने गंतव्य तक पहुंचने दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप और कारोबारियों के लगातार प्रयासों के बाद पंजाब सरकार ने विवादित टैक्स वापस लेने का फैसला किया। इस निर्णय के बाद कश्मीर में मटन संकट समाप्त होने का रास्ता साफ हो गया है और पशुधन से लदे वाहनों की आवाजाही फिर से सामान्य होने लगी है। ऑल कश्मीर होलसेल एंड रिटेल मटन डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष खजीर मोहम्मद रेगू ने पंजाब सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार ने यह समझा कि लगाया गया टैक्स उचित नहीं था, इसलिए उसे वापस ले लिया गया।

रनवे मरम्मत होगी रात में, दिन में सामान्य रहेगा श्रीनगर एयरपोर्ट संचालन

श्रीनगर एयरपोर्ट पर सामान्य रहेंगी उड़ानें

रनवे शटडाउन टला, श्रीनगर एयरपोर्ट से पूरे साल भरेंगी सामान्य उड़ानें

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जुड़े यात्रियों, पर्यटन उद्योग और स्थानीय कारोबारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। एयरपोर्ट प्रशासन ने वर्ष 2026 के दौरान प्रस्तावित पूर्ण रनवे बंदी की योजना वापस लेने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि पूरे साल दिन के समय उड़ानों का संचालन बिना किसी बड़े व्यवधान के सामान्य रूप से जारी रहेगा। पहले रनवे के रखरखाव और मरम्मत कार्य के कारण सप्ताह में कुछ दिनों तक उड़ानों को प्रभावित करने और अक्तूबर में लंबे समय तक रनवे बंद रखने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। हालांकि व्यापक विचार-विमर्श और विभिन्न पक्षों की चिंताओं को देखते हुए इस योजना में बदलाव किया गया है।

एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि श्रीनगर हवाई अड्डे पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक सभी निर्धारित उड़ानों का संचालन पहले की तरह नियमित रूप से होगा। इससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को किसी अतिरिक्त परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

हालांकि रनवे की मरम्मत और रखरखाव का कार्य पूरी तरह बंद नहीं किया गया है। यह कार्य रात के समय जारी रहेगा ताकि दिन के समय उड़ानों पर कोई असर न पड़े। अधिकारियों के अनुसार यह रात्रिकालीन रखरखाव कार्य अक्तूबर 2026 तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चलता रहेगा।

पर्यटन — अमरनाथ यात्रा के दौरान पर्यटकों को बाजार घूमने की अनुमति का सुझाव

यात्रियों को बसों तक सीमित न रखें: अब्दुल्ला

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अमरनाथ यात्रा को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए कहा है कि इस वार्षिक धार्मिक यात्रा के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को केवल बसों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें स्थानीय बाजारों और आसपास के क्षेत्रों में घूमने की अनुमति भी दी जानी चाहिए, ताकि वे कश्मीर की अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे सकें।

उन्होंने स्पष्ट किया कि अमरनाथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन ही नहीं है, बल्कि यह जम्मू-कश्मीर की आर्थिक गतिविधियों को गति देने का भी एक बड़ा माध्यम है, जिसमें स्थानीय व्यापारियों, दुकानदारों, परिवहन सेवाओं, होटल उद्योग और छोटे व्यवसायों को बड़ा लाभ मिलता है। उमर अब्दुल्ला का मानना है कि यदि यात्रियों को अधिक स्वतंत्र रूप से स्थानीय बाजारों में जाने, खरीदारी करने और क्षेत्रीय संस्कृति को देखने का अवसर मिलेगा तो इससे न केवल उनका अनुभव बेहतर होगा बल्कि स्थानीय लोगों की आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने अपने स्तर पर यात्रा से जुड़े सभी प्रशासनिक और व्यवस्थागत इंतज़ाम पूरे कर लिए हैं, जबकि सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ अमरनाथ श्राइन बोर्ड तथा संबंधित एजेंसियों द्वारा संभाली जा रही हैं, जिससे यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाया जा सके।

मुख्यमंत्री ने यात्रियों से अपील की कि वे अपनी यात्रा के दौरान जम्मू-कश्मीर में शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए प्रार्थना करें, ताकि यह क्षेत्र स्थायी रूप से विकास और स्थिरता की ओर बढ़ सके।

उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए उस सुझाव का भी स्वागत किया जिसमें कहा गया था कि यात्रियों को अपने यात्रा बजट का एक हिस्सा, लगभग दस प्रतिशत, स्थानीय अर्थव्यवस्था में खर्च करना चाहिए, जिससे छोटे व्यापारियों और स्थानीय बाजारों को सीधा लाभ मिल सके।

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यदि यात्री केवल बसों या निर्धारित मार्गों तक ही सीमित रहेंगे तो उनका आर्थिक योगदान सीमित रहेगा, लेकिन यदि उन्हें स्थानीय बाजारों, हस्तशिल्प की दुकानों, खाने-पीने की जगहों और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में जाने की अनुमति दी जाए तो इससे पूरी अर्थव्यवस्था को व्यापक फायदा होगा।

उमर अब्दुल्ला ने श्रद्धालुओं का किया नमन

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाना ही नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि स्थानीय लोग इस अवसर से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। उन्होंने विश्वास जताया कि यदि सभी संबंधित एजेंसियाँ और स्थानीय प्रशासन मिलकर काम करें तो अमरनाथ यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भी एक अत्यंत सफल आयोजन साबित होगी। इसके साथ ही उन्होंने पर्यटकों और श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि वे कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और लोगों के आतिथ्य का सम्मान करें।

◆ **कहा- यात्रियों का खर्च कश्मीर में ही हो सुनिश्चित**

◆ **कश्मीर की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की अपील**

उधमपुर पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान हेड कांस्टेबल की मौत

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। उधमपुर स्थित शेर-ए-कश्मीर पुलिस अकादमी में शनिवार को एक दुखद घटना सामने आई, जहां प्रशिक्षण के दौरान जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार, प्रशिक्षण सत्र के दौरान हेड कांस्टेबल बशीर अंजुम अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। वहां मौजूद प्रशिक्षकों और अन्य पुलिसकर्मियों ने तत्काल उन्हें प्राथमिक सहायता देने का प्रयास किया और बिना देरी किए अस्पताल पहुंचाया। हालांकि अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

◆ **ट्रेनिंग के दौरान गिरे हेड कांस्टेबल**

मृतक की पहचान पुंछ जिले के मेंढर क्षेत्र के गुरसाई निवासी हेड कांस्टेबल बशीर अंजुम के रूप में हुई है। वह वर्तमान में उधमपुर स्थित शेर-ए-कश्मीर पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। उनकी अचानक हुई मौत से पुलिस विभाग और उनके साथ प्रशिक्षण ले रहे जवानों में शोक की लहर दौड़ गई। घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली।

बारिश के बाद काउधा में दरका पहाड़, बढ़ी मुश्किलें

भारी बारिश के कारण रामनगर उधमपुर मार्ग पर यातायात ठप

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण उधमपुर जिले के काउधा क्षेत्र के पास रामनगर-उधमपुर सड़क पर भूस्खलन होने से यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा, मिट्टी और बड़े-बड़े पत्थर सड़क पर आ गिरने से दोनों ओर वाहनों की आवाजाही रुक गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, लोक निर्माण विभाग और संबंधित एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंचीं तथा स्थिति का जायजा लिया।

सड़क से मलबा हटाने और यातायात बहाल करने के लिए जेसीबी समेत अन्य भारी मशीनों की मदद से राहत एवं बहाली कार्य तेज़ी से शुरू कर दिया गया। सड़क ठेकेदार और रामनगर निवासी पुष्पिंदर सिंह ने बताया कि सुबह करीब सात बजे सड़क बंद होने की सूचना मिली, जिसके बाद तत्काल मशीनरी मंगवाकर मलबा हटाने का काम शुरू कराया गया।

प्रशासन का कहना है कि मौसम की स्थिति को देखते हुए सड़क को जल्द से जल्द यातायात के लिए खोलने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान पहाड़ी मार्गों पर यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि लगातार बारिश के चलते भूस्खलन का खतरा अभी भी बना हुआ है।

न्यूज ब्रीफ

नयना देवी मंदिर में सोने के कंगन स्नैचिंग का खुलासा

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिला बिलासपुर पुलिस ने माता श्री नयना देवी मंदिर परिसर में हुई सोने के कंगन स्नैचिंग की घटना का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए चोरी हुए आभूषणों की 100 प्रतिशत बरामदगी सुनिश्चित की है। 28 जून को मंदिर में दर्शन के लिए आई एक महिला के हाथों से दो सोने के कंगन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा छीन लिए गए थे। इस संबंध में थाना कोट में मामला दर्ज कर विशेष जांच टीम गठित की गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, वाहन सत्यापन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड सहित डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण किया। जांच में यह घटना एक संगठित गिरोह द्वारा अंजाम दी गई पाई गई। 2 जुलाई को मुख्य आरोपी हरिंद्र सिंह को पटियाला से गिरफ्तार किया गया और वारदात में इस्तेमाल वाहन भी बरामद हुआ। आरोपी की निशानदेही पर लगभग 6.50 लाख रुपए मूल्य के दोनों कंगन बरामद कर लिए गए। पुलिस ने आरोपी को चार दिन के रिमांड पर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

झंडूता कॉलेज में साइंस संकाय बहाल, क्षेत्र में खुशी की लहर

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। झंडूता कॉलेज में साइंस संकाय की बहाली को लेकर जारी विवाद के बीच सरकार ने अपने पहले के फैसले को वापस लेते हुए साइंस कक्षाएं बहाल करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस निर्णय के बाद क्षेत्र में खुशी का माहौल है। भाजपा ने इसे अपने जनसंघर्ष और क्षेत्र की जनता की एकजुटता की जीत बताया है। भाजपा नेताओं के अनुसार, साइंस संकाय बंद होने से पिछड़े क्षेत्र कोटधार सहित करीब 30 पंचायतों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 30-40 किलोमीटर दूर अन्य कॉलेजों का रुख करना पड़ता, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती। साइंस संकाय की बहाली के लिए विधायक जीतराम कटवाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। इसके बाद रैली, प्रदर्शन और पंचायत समिति व जिला परिषद में प्रस्ताव पारित कर सरकार से निर्णय वापस लेने की मांग की गई। भाजपा मंडल अध्यक्षों ने कहा कि अब विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र में ही विज्ञान विषय की पढ़ाई का अवसर मिलेगा।

28 को खोली जाएंगी खाद्यान्न परिवहन की ई-टेंडर निविदाएं

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के बिलासपुर स्थित थोक भंडार से हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के सदर थोक भंडार तक वर्ष 2026-27 और 2027-28 के लिए खाद्यान्न परिवहन एवं ढुलाई कार्य के लिए ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। जिला नियंत्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले बिजेंद्र पठानिया ने बताया कि इच्छुक एजेंसियां 27 जुलाई सायं 5 बजे तक केवल ई-टेंडरिंग पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। ऑफलाइन अथवा निर्धारित समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। प्राप्त निविदाएं 28 जुलाई 2026 को प्रातः 11 बजे उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर में खोली जाएंगी। निविदा की पात्रता एवं अन्य शर्तों की विस्तृत जानकारी ई-टेंडरिंग पोर्टल पर उपलब्ध है।

देवांशी ने राष्ट्रीय सम्मेलन में जीता स्वर्ण पदक

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय व अस्पताल (एसएलबीएसजीएमसी एंड एच), नेरचौक की एमबीबीएस अंतिम वर्ष की छात्रा देवांशी ने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतिष्ठित 'मेड-एसेंट 2026' सम्मेलन में स्वर्ण पदक जीतकर कॉलेज और हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। डॉ. आरपीजीएमसी एंड एच, टांडा में 20-21 जून को आयोजित सम्मेलन में उन्होंने क्लिनिकल केस प्रेजेंटेशन और रिसर्च पोस्टर प्रेजेंटेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। लगातार दूसरे वर्ष स्वर्ण पदक जीतने वाली देवांशी को कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रो. डॉ. राजेश कुमार ने सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि संस्थान और प्रदेश के लिए गर्व की बात है तथा अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणादायक है।

नशे के दुष्प्रभावों व पुनर्वास सेवाओं की दी जानकारी

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा शनिवार को किसान भवन, बिलासपुर में नशा मुक्त भारत अभियान व वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्ययोजना के अंतर्गत जिला स्तरीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लगाने, युवाओं को इससे दूर रखने तथा वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों, सम्मान और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। पुलिस, स्वास्थ्य व सामुदायिक विकास विशेषज्ञों ने नशे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभावों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नशा केवल व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है, इसलिए जनजागरूकता और पुनर्वास सेवाओं की भूमिका अहम है। विशेषज्ञों ने युवाओं को सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने तथा नशा मुक्ति के लिए उपलब्ध सरकारी सुविधाओं की जानकारी भी दी। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, अधिकारों और सुरक्षा पर चल रही योजनाओं की जानकारी साझा की गई। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों, संगठनों और स्वयंसेवकों ने भाग लिया।

खेलो इंडिया उत्कृष्टता केंद्र में चयन ट्रायल 16 से

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। युवा सेवा एवं खेल विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा खेलो इंडिया उत्कृष्टता केंद्र, बिलासपुर में सत्र 2025-26 के लिए खिलाड़ियों के चयन हेतु ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। विभाग ने पात्र खिलाड़ियों से निर्धारित तिथियों पर ट्रायल में भाग लेकर अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। जारी कार्यक्रम के अनुसार 16 जुलाई, 2026 को लड़कों के लिए एथलेटिक्स, बॉक्सिंग और जूडो तथा 17 जुलाई, 2026 को लड़कियों के लिए इन्हीं खेलों के ट्रायल होंगे। सभी ट्रायल प्रातः 8 बजे से खेलो इंडिया उत्कृष्टता केंद्र, बिलासपुर में शुरू होंगे। ट्रायल में 13 से 19 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले सकेंगे, जिनका जन्म 1 जनवरी 2007 से 1 जनवरी 2013 के बीच होना चाहिए। विभाग ने विभिन्न आयु वर्ग के लिए न्यूनतम शारीरिक मापदंड भी निर्धारित किए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता खिलाड़ियों को मापदंड में छूट दी जाएगी। चयनित खिलाड़ियों को निःशुल्क आवास, भोजन, चिकित्सा सुविधा, बीमा, खेल किट और आधुनिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही उनकी पढ़ाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।

रौड़ा अनुभाग में बाधित रहेगी बिजली आपूर्ति

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। सहायक अभियंता बिजली उपमंडल-।। ई. रविंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 जुलाई को रौड़ा अनुभाग में बिजली की लाईनों की आवश्यक मरम्मत, पेडों की कांट-छांट व जीओ स्वीच के पार्ट बदले के चलते कुछ क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने बताया कि रौड़ा अनुभाग के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र कोसरियां, कॉलेज चौक, कमेटी हॉल, कमेटी रैस्ट हाउस रौडा, धौलरा रोड, एनएच, पुरानी तहसील, मीट मार्किट, मेन मार्किट, दबदा मोहल्ला रौडा, ओयल, गांधी मार्किट तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में प्रातः 10 बजे से दोपहर 5 बजे तक बिजली आपूर्ति आंशिक रुप से बाधित रहेगी। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है।

प्रतिबंधित सीजन में अवैध मछली बिक्री पर जुर्माना

भारतेन्दु संवाददाता, ऊना। जिला ऊना में मत्स्य विभाग ने प्रतिबंधित (क्लोज) सीजन के दौरान अवैध रूप से मछली बेचने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए नियमों के उल्लंघन के पांच मामलों में कुल 8 हजार रुपए का जुर्माना वसूला है। मत्स्य विभाग के सहायक निदेशक विवेक शर्मा ने बताया कि विभाग के विशेष दस्ते ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सघन निरीक्षण अभियान चलाकर मछली विक्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। अभियान के दौरान अवैध रूप से मछली बिक्री के पांच मामले पाए गए, जिनमें नियमानुसार मौके पर ही कुल 8 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में मछलियों के प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए क्लोज सीजन लागू है। इस अवधि में मत्स्य संसाधनों के संरक्षण तथा प्राकृतिक प्रजनन प्रक्रिया को सुरक्षित बनाए रखने के लिए मछली पकड़ने और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा कि विभाग की इस कार्रवाई का उद्देश्य प्रजनन काल के दौरान मत्स्य संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना है। ऐसे में नियमों की अवहेलना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। विवेक शर्मा ने कहा कि मत्स्य संसाधनों के संरक्षण में सभी नागरिकों, व्यापारियों तथा मछली विक्रेताओं का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सभी संबंधित लोगों से क्लोज सीजन के दौरान निर्धारित नियमों का पूर्णतः पालन करने की अपील की।

सुक्खू मंत्रिमंडल में फेरबदल जल्द, बनेगा एक और मंत्री

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के मंत्रिमंडल में जल्द फेरबदल और विस्तार होगा। मंत्री की एक खाली कुर्सी को भरा जाएगा। इस संबंध में 16 और 17 जुलाई को धर्मशाला में कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे।

बैठक में मंत्रिमंडल के फेरबदल और विस्तार पर चर्चा होगी। इसके बाद इस विषय पर अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है। यह जानकारी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी की आम सभा में शामिल होने शिमला पहुंचीं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने आज मीडिया से बातचीत में दी। शिमला में दो दिवसीय प्रदेश कांग्रेस की आम सभा में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और आने वाले राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी चर्चा की जाएगी। रजनी पाटिल ने कहा कि

◆ 16-17 को धर्मशाला में केसी वेणुगोपाल के साथ कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक

कांग्रेस का लक्ष्य संगठन को हर बूथ तक मजबूत करना है। इसके साथ ही आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। रजनी पाटिल ने कहा कि राम मंदिर चंदा चोरी से जुड़े सामने आए आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि भाजपा ने राम मंदिर के नाम पर लोगों से वोट मांगे थे, इसलिए इस मामले की सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश से जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बैठक में इस मुद्दे के साथ-साथ नीट पेपर लीक सहित अन्य राजनीतिक विषयों पर भी चर्चा होगी। किन्नौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर चल रहे विवाद पर रजनी पाटिल ने कहा कि इस मामले में राजस्व मंत्री जगत सिंह

◆ 2027 चुनाव की तैयारी शुरू, ब्लॉक स्तर से रणनीति तय करने पर जोर

नेगी से बात की जाएगी और गलतफहमी दूर करने का प्रयास होगा। उन्होंने कहा कि जगत सिंह नेगी और निगम भंडारी को आमने-सामने बैठाकर विवाद सुलझाया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि संगठन विस्तार के उद्देश्य से होने वाली इस आम सभा में ब्लॉक अध्यक्षों से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी नेता भाग लेंगे। ब्लॉक स्तर पर संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारियां तय की जाएंगी और यहीं से अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की शुरुआत होगी। किन्नौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष के विवाद पर विनय कुमार ने कहा कि उनकी जगत सिंह नेगी से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि जगत सिंह नेगी और निगम भंडारी को साथ बैठाकर विवाद का समाधान किया जाएगा।

चूड़धार मंदिर में रील्स व वीडियो पर पूर्ण प्रतिबंध

भारतेन्दु संवाददाता, नाहन। उत्तर भारत के प्रमुख धार्मिक स्थल शिरगुल महाराज मंदिर चूड़धार में अब श्रद्धालु और पर्यटक रील्स व वीडियो नहीं बना सकेंगे। मंदिर परिसर और गर्भगृह की धार्मिक मर्यादा तथा पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रशासन ने यह कड़ा निर्णय लिया है। एसडीएम चौपाल एवं मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि मंदिर परिसर और गर्भगृह के भीतर सभी प्रकार की वीडियोग्राफी, रील्स और सोशल मीडिया गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह नियम पुजारियों, कर्मचारियों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों सभी पर समान रूप से लागू होगा। आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा मंदिर के भीतर रील्स बनाकर धार्मिक भावनाओं और मर्यादा को ठेस पहुंचाई जा रही थी, जिसके चलते यह कदम उठाया गया है।

भारतीय आभूषण, डिजाइन व प्रतिभा को वैश्विक मंचों तक पहुंचाने का लें संकल्प : अनुराग ठाकुर

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने राजस्थान के जयपुर में ज्वैलर्स एसोसिएशन के शताब्दी समारोह में बतौर मुख्यातिथि भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने ज्वैलरी एमीनेन्स अवाड्र्स 2026 के विजेताओं और प्रतिभागियों को सम्मानित किया तथा भारतीय आभूषण उद्योग की परंपरा और उसकी वैश्विक संभावनाओं पर विचार साझा किए।

अपने संबोधन में अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हमारे शास्त्रों में आभूषण निर्माण की शिल्प कला को केवल आजीविका नहीं, बल्कि धैर्य और एकाग्रता से सौंदर्य सृजन की साधना माना गया है। उन्होंने ज्वैलर्स एसोसिएशन जयपुर को 100 वर्ष पूर्ण करने पर बधाई देते हुए कहा कि किसी भी संस्था के लिए एक शताब्दी तक अपने मूल्यों, विश्वसनीयता और नेतृत्व को बनाए रखना बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि जयपुर केवल अपने ऐतिहासिक रणकौशल और वीर परंपरा के लिए ही नहीं, बल्कि अपने आभूषण कारीगरों के लिए भी विश्वभर में प्रसिद्ध है। यहां के जौहरियों ने तीन सौ वर्षों पुरानी परंपरा को न केवल जीवित रखा है, बल्कि उसे वैश्विक पहचान भी दिलाई है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ज्वैलरी एमीनेन्स अवार्ड्स 2026 केवल एक पुरस्कार समारोह नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। उन्होंने सुझाव दिया कि जैसे मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया ने वैश्विक स्तर पर पहचान बनाई है, वैसे ही डिजाइन इंडिया को भी एक वैश्विक ब्रांड के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।

उन्होंने बताया कि भारत का रत्न एवं आभूषण निर्यात चार दशमलव सत्ताईस अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। हाल के वैश्विक तनावों के कारण इस क्षेत्र पर कुछ दबाव जरूर आया है, लेकिन इसे नए अवसरों में बदलने की आवश्यकता है।

भाजपा की ताकत उसका अनुशासित संगठन व मजबूत बूथ स्तर : जम्वाल

भगत सिंह गुलेरिया, भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक राकेश जम्वाल ने जिला मंडी के प्रशिक्षण वर्ग में 'बूथ प्रबंधन' विषय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका अनुशासित संगठन और बूथ स्तर तक सक्रिय कार्यकर्ता हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का मार्ग बूथ से होकर ही निकलेगा, इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने बूथ को सबसे मजबूत बनाने का संकल्प लेना होगा।

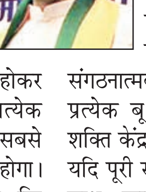

राकेश जम्वाल ने कहा कि भाजपा चुनाव केवल नारों या सभाओं के दम पर नहीं, बल्कि मजबूत संगठन, सूक्ष्म योजना और बूथ स्तर पर निरंतर किए गए कार्य के बल पर जीतती है। बूथ जितना मजबूत होगा, भाजपा की विजय उतनी ही सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता अपने बूथ के हर परिवार और हर मतदाता से व्यक्तिगत संपर्क बनाए तथा केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और संगठन की विचारधारा को घर-घर तक पहुंचाए। उन्होंने कहा कि आज भाजपा विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल इसलिए बनी है, क्योंकि उसने बूथ को अपनी संगठनात्मक शक्ति का केंद्र बनाया। प्रत्येक बूथ समिति, पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्र और मंडल स्तर की टीम यदि पूरी सक्रियता और समन्वय के साथ कार्य करे तो कोई भी राजनीतिक शक्ति भाजपा को रोक नहीं सकती। राकेश जम्वाल ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि हिमाचल के भविष्य का चुनाव होगा।

6 जुलाई को क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में दिव्यांगजनों का होगा चिकित्सा परीक्षण

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिला बिलासपुर में दिव्यांगजन को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कल यानी 6 जुलाई (सोमवार) को शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर आयोजन के दृष्टिगत मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिलासपुर डॉ. शशि दत्त शर्मा ने जिला मेडिकल डिसेबिलिटी बोर्ड का गठन किया है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि इस बोर्ड में विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टरों व अधिकारियों को नामित किया गया है, जिनमें ईएनटी विशेषज्ञ, जनरल सर्जन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ तथा मेडिसिन विशेषज्ञ शामिल हैं। उन्होंने बताया कि यह शिविर 06 जुलाई को प्रातः 10 बजे से अंतिम लाभार्थी के परीक्षण तक आयोजित किया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित लाभार्थियों से सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित निर्धारित तिथि व समयानुसार शिविर में शामिल होने का आह्वान किया है।

यूथ फेस्ट के तहत एड्स जागरूकता क्विज प्रतियोगिता का आयोजन

बालिका स्कूल बिलासपुर की पीहू-गौरी टीम प्रथम

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी) के अंतर्गत शनिवार को क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर के ट्रॉमा सेंटर स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में यूथ फेस्ट-2026 के तहत जिला स्तरीय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

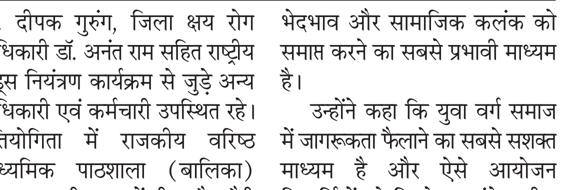

प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं में एचआईवी/एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाना, इससे जुड़े मिथकों एवं सामाजिक कलंक (स्टिग्मा) को दूर करना तथा वैज्ञानिक जानकारी एवं सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना था। प्रतियोगिता में जिला बिलासपुर के विभिन्न राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की 10 टीमों ने भाग लिया और एचआईवी/एड्स से संबंधित विषयों पर अपनी जानकारी एवं प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. शशि दत्त शर्मा ने की। इस अवसर पर जिला एड्स कार्यक्रम अधिकारी डॉ. दीपक गुरुंग, जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. अनंत राम सहित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम से जुड़े अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (बालिका) बिलासपुर की छात्राओं पीहू और गौरी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। विजेता टीम अब राज्य स्तरीय क्विज प्रतियोगिता में जिला बिलासपुर का प्रतिनिधित्व करेगी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला औहर ने द्वितीय, घागस ने तृतीय तथा डंगार ने चतुर्थ स्थान हासिल किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. शशि दत्त शर्मा ने विजेता प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि एड्स के प्रति सही और वैज्ञानिक जानकारी ही इस बीमारी से जुड़े भ्रम, भेदभाव और सामाजिक कलंक को समाप्त करने का सबसे प्रभावी माध्यम है।

उन्होंने कहा कि युवा वर्ग समाज में जागरूकता फैलाने का सबसे सशक्त माध्यम है और ऐसे आयोजन विद्यार्थियों को जिम्मेदार, संवेदनशील एवं जागरूक नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित टीम को शुभकामनाएं देते हुए सभी प्रतिभागियों के उत्साह और प्रदर्शन की सराहना की। इस अवसर पर अधिकारियों ने विद्यार्थियों से एचआईवी/एड्स की रोकथाम, समय पर जांच, उपचार की उपलब्धता तथा संक्रमित व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील एवं भेदभाव रहित व्यवहार अपनाने का आह्वान किया।

हर साल पांच किलोमीटर भी रेल लाइन बिछाते तो आज हमीरपुर पहुंच जानी थी रेल : कुलदीप

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि सांसद अनुराग ठाकुर मेडिकल कॉलेज की बड़ी-बड़ी बातें करके झूठी वाहवाही और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि पिछले 20 साल में हमीरपुर के लिए उन्होंने किया क्या है। इस पर कभी भी जवाब नहीं देते। वे सिर्फ राजनीति करते हैं, लोगों के विकास की उन्हें जरा भर भी फिक्र नहीं है।

◆ कुलदीप पठानिया ने अनुराग से पूछा कि 20 वर्षों में हमीरपुर को क्या दिया इसका जवाब दें

शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पठानिया ने कहा कि अनुराग ठाकुर की करनी और कथनी सब जानते हैं। अब उनकी बातों पर जरा भी कोई विश्वास करने की जहमत नहीं उठाने वाला। पठानिया ने कहा कि हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज किसकी देन है यहां अभी भी बताने की जरूरत है अनुराग ठाकुर जिस झूठ को लेकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं उससे उनका भला होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने जी बस स्टैंड की नींव रखी थी, इसका निर्माण तो भाजपा की सरकारों में नहीं हुआ, लेकिन हमीरपुर के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इसका निर्माण करवाया है, जो अब अंतिम चरण में है। उन्होंने अनुराग से कहा कि वे झूठ के साथ ना चले सच्चाई के साथ चलें यदि उन्होंने कोई काम करवाए हैं, तो उसका श्वेत पत्र जारी करें। हमीरपुर सैनिकों का जिला है और टौणी देवी में केंद्रीय विद्यालय खोले जाना चाहिए। ताकि उनके परिवारों को फायदा हो, यह केंद्र में बैठे हैं, इसलिए इसका फायदा हमीरपुर की जनता को मिलना चाहिए। लेकिन उन्हें तो सिर्फ राजनीतिक करनी है। पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि उनके समय में भाजपाई कहते थे कि काम नहीं हो रहे लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आई तो रुके हुए सारे काम शुरू हुए। फिर भी अनुराग ठाकुर और अन्य नेताओं को कुछ भी सूझता नहीं है। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर बताए कि हिमाचल से कितने खिलाड़ी देश के लिए खेले हैं। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री होते हुए भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट हिमाचल के लिए लेकर नहीं आए। पठानिया ने कहा कि 20 साल में यदि 5 किलोमीटर भी हर साल इसका निर्माण होता, तो आज तक रेलवे लाइन हमीरपुर तक निकल चुकी होती। लेकिन ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम पर लोगों को गुमराह किया था। ड्रीम वैसे भी रात को देखे जाते हैं। यही हाल अनुराग ठाकुर का है। जिन सपनों को ड्रीम बनाया, वे ड्रीम ही रहे, हकीकत में नहीं बदले।

पठानकोट में वकीलों की हड़ताल से 2200 केस प्रभावित अदालतों में कामकाज ठप

भारतेन्दु संवाददाता, पठानकोट। पठानकोट में एडवोकेट ज्योतिपाल भीम के खिलाफ दर्ज मामले के विरोध में जिला बार एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। शनिवार को लगातार तीसरे दिन भी वकीलों ने अदालतों में 'नो वर्क डे' रखा, जिससे जिला एवं सेशन डिवीजन की सभी 14 अदालतों का कामकाज पूरी तरह ठप रहा। बार एसोसिएशन ने सोमवार को भी हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष दर्शन सिंह ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बिना ठोस जांच के वकील पर मामला दर्ज किया है, जो अनुचित है। वकीलों ने चेतावनी दी है कि एफआईआर रद्द न होने पर राज्य स्तरीय आंदोलन किया जाएगा। हड़ताल के चलते तीन दिनों में करीब 2200 केस प्रभावित हुए और सैकड़ों वादी पक्ष को बिना सुनवाई लौटना पड़ा। बार एसोसिएशन ने नियम तोड़ने वाले वकीलों पर जुर्माना और अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी चेतावनी दी है।

बिलासपुर जिले में टीबी उन्मूलन अभियान तेज 183 गांवों की स्क्रीनिंग में मिले नौ नए मरीज

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जिला बिलासपुर में टीबी की समय रहते पहचान और संक्रमण की रोकथाम के लिए विशेष अभियान तेजी से चलाया जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिन्हित 244 हाई रिस्क गांवों में विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से लोगों की स्क्रीनिंग कर संभावित मरीजों की पहचान की जा रही है, ताकि समय पर उपचार शुरू कर संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. शशि दत्त शर्मा ने बताया कि अब तक 244 में से 183 हाई रिस्क गांवों में स्क्रीनिंग पूरी की जा चुकी है। इस दौरान 9 नए टीबी मरीजों की पहचान हुई है। सभी मरीजों का उपचार राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत तत्काल शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि शिविरों में 14 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की जांच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित हैंडहेल्ड डिजिटल एक्स-रे मशीन से की जा रही है। यदि एक्स-रे में टीबी की आशंका दिखाई देती है तो मौके पर ही बलगम सहित अन्य आवश्यक नमूने लेकर जांच की जाती है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर मरीज को तुरंत दवा और उपचार उपलब्ध कराया जाता है। डॉ. शर्मा ने बताया कि इन शिविरों में टीबी के साथ-साथ मधुमेह (डायबिटीज) और एनीमिया की जांच भी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 1 जनवरी से अब तक जिले में 481 टीबी मरीज सामने आ चुके हैं। टीबी पूरी तरह इलाज योग्य बीमारी है और समय पर जांच, नियमित दवा तथा चिकित्सकीय सलाह का पालन करने से मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो सकता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लोगों से अपील की कि यदि किसी व्यक्ति को दो सप्ताह से अधिक समय तक लगातार खांसी, बलगम में खून, वजन कम होना, भूख न लगना, रात में अधिक पसीना आना या टीबी से जुड़े अन्य लक्षण दिखाई दें तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग की टीम से संपर्क करें। उन्होंने लोगों से गांवों में लगाए जा रहे शिविरों में पहुंचकर छाती का एक्स-रे और आवश्यक जांच अवश्य करवाने का आग्रह किया।

खाद्य आपूर्ति विभाग ने तुगलकी फरमान वापस नहीं लिए, तो होगा आंदोलन : अशोक

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। प्रदेश सरकार जब से सत्ता में आई है, तब से डिपो धारकों की मांगों को पूरी तरह से नकार दिया है। प्रदेश के डिपो धारक सरकार के इस रवैये से परेशान व हताश हैं। वहीं, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने प्रदेश के डिपो धारकों को फेस ऑथेंटिकेशन ऐप डाउनलोड करने के तुगलकी फरमान जारी कर दिए हैं, जबकि संबंधित विभाग ने डिपो धारकों को न तो मोबाइल की सुविधा दी है और न ही इंटरनेट की।

प्रदेश डिपो संचालक समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कवि ने कहा कि विभाग तुगलकी फरमान जारी करने से पहले आंगनबाड़ी व आशा वर्करों की तर्ज पर डिपो धारकों को मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा प्रदान करे। कवि ने कहा कि सरकार व विभाग डिपो धारकों के आर्थिक हितों की अनदेखी करके डिपो धारकों को आर्थिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने का प्रयास कर कर रहे हैं, जो कि असहनीय है। राज्य अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा एनएफएसए के राशन पर 2015 व 2022 में कमीशन बढोतरी और पॉश मशीनों के माध्यम से राशन वितरित करने के एवज में प्रति क्विंटल 26 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की अधिसूचना जारी की गई है, लेकिन प्रदेश सरकार ने आज तक डिपो धारकों को फूटी कौड़ी भी नहीं दी। डिपो धारकों को अपना हक पाने के लिए उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।

अशोक कवि ने कहा कि विभाग द्वारा डिपुओं पर स्थापित की गई पॉश मशीनों में डाली गई सिमें पिछले पांच वर्षों से बंद पड़ी हैं वावजूद इसके डिपो धारकों ने प्रति माह 470 रुपए इंटरनेट पर खर्च करके उपभोक्ताओं को राशन वितरण का कार्य जारी रखा, ताकि उपभोक्ताओं को परेशानी न झेलनी पड़े, लेकिन अब प्रदेश के डिपो धारक बिना मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा के विभाग द्वारा दिए गए तुगलकी फरमानों की कड़ी निंदा करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विभाग या तो डिपो धारकों को मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा प्रदान करे या फिर तुगलकी फरमान वापिस ले अन्यथा सरकार व विभाग इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश सरकार या विभाग ने तुगलकी फरमान वापस नहीं लिए तो प्रदेश के सभी डिपो होल्डर एक बड़ा आंदोलन करेंगे।

शुभारंभ हिमाचल के स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था सुधार के लिए शिक्षा मंत्री ने शुरू किया 'वर्चुअल संवाद' कार्यक्रम

शिक्षा व्यवस्था की होगी ऑनलाइन निगरानी : रोहित ठाकुर

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शनिवार को 'वर्चुअल संवाद' कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

हिमाचल स्कूल स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा शनिवार को राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पोर्टमोर, शिमला में वर्ष 2025-26 के आईएसएफ वर्ल्ड स्कूल चैंपियनशिप, एशियन स्कूल चैंपियनशिप तथा 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पदक विजेता एवं प्रतिभागी खिलाड़ियों के सम्मान में भव्य पुरस्कार वितरण समारोह में शिक्षा मंत्री ने वर्चुअल संवाद का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत जिला चंबा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मेहला से की गई, जहां शिक्षा मंत्री ने विद्यालय के प्रधानाचार्य से वर्चुअल माध्यम से सीधा संवाद किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने विद्यालय में शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ की उपलब्धता, रिक्त पदों की स्थिति, विद्यार्थियों के शैक्षणिक परिणाम तथा विद्यालय में उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। प्रधानाचार्य ने वर्चुअल माध्यम से विद्यालय की कक्षाओं का भी अवलोकन करवाया। शिक्षा मंत्री ने आश्वस्त किया कि भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत रिक्त शिक्षकों के पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा, जिससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सके। रोहित ठाकुर ने कहा कि हाल ही में उनके जम्मू-कश्मीर के दौरे के दौरान उन्होंने वहां के शिक्षा विभाग में वर्चुअल निरीक्षण की प्रभावी व्यवस्था देखी। उसी से प्रेरणा लेकर हिमाचल प्रदेश में भी सरकारी विद्यालयों के लिए 'वर्चुअल संवाद' कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि इस पहल के माध्यम से शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं सरकार सीधे विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और विद्यार्थियों से संवाद स्थापित कर सकेंगे। इससे विद्यालयों की वास्तविक स्थिति की जानकारी समय पर प्राप्त होगी, विद्यार्थियों से सीधे फीडबैक लिया जा सकेगा तथा शिक्षण व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही, विद्यालयों के नियमित निरीक्षण की प्रक्रिया अधिक सरल, प्रभावी और पारदर्शी बनेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना तथा आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं जवाबदेह बनाना है। 'वर्चुअल संवाद' कार्यक्रम इस दिशा में एक महत्वपूर्ण और अभिनव कदम साबित होगा। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए निदेशक स्कूल शिक्षा ने कहा कि अब शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव और निदेशक सहित निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी सभी सरकारी स्कूलों में वर्चुअल संवाद पर बल देंगे। उन्होंने कहा कि इससे तुरंत फीडबैक मिलेगा और कभी भी स्कूल प्रधानाचार्य से वर्चुअल संवाद किया जा सकेगा।

हॉट क्वीन 'शकीरा'

शकीरा कोलंबिया की प्रसिद्ध गायिका, गीतकार, नर्तकी और फुटबॉल लीग से सबंधित हैं, जो कि फुटबॉल की शुरुआत से लगातार थीम गाने बनाती आई हैं। उनका जन्म 2 फरवरी 1977 को बारांक्विला शहर में हुआ था। है एक महान संगीत व्यक्तित्व की पहचान है

जर्मनी-नीदरलैंड को हराकर गरजा भारत प्रो लीग ने बढ़ाया विश्व कप का भरोसा

एफआईएच प्रो लीग में भारत का दमदार अंत, विश्व कप से पहले दिखाई चैंपियन वाली लय

एजेंसी, नई दिल्ली

एफआईएच प्रो लीग 2025-26 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यह संकेत दिया कि वह विश्व कप और एशियाई खेलों जैसे बड़े टूर्नामेंटों से पहले सही समय पर अपनी सर्वश्रेष्ठ लय में पहुंच रही है। यूरोपीय चरण में भारत ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीदरलैंड को हराया, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ दोनों मुकाबलों में कड़ी टक्कर दी।

भारत का अभियान तीन चरणों में आगे बढ़ा। राउरकेला में घरेलू चरण के दौरान टीम को बेल्जियम और अर्जेंटीना के खिलाफ हार झेलनी पड़ी। इसके बाद होबार्ट में भारतीय टीम ने अपने खेल में उल्लेखनीय सुधार दिखाया। स्पेन के खिलाफ शुरुआती हार के बाद ऑस्ट्रेलिया और स्पेन के खिलाफ ड्रॉ खेला, हालांकि दोनों शूटआउट हार गई। अंतिम मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शूटआउट जीतकर टीम ने आत्मविश्वास हासिल किया। इस चरण में भारतीय रक्षा पंक्ति प्रभावी रही और चार मैचों में केवल छह गोल खाए। यूरोपीय दौरे में भारतीय टीम ने अपने प्रदर्शन को नई ऊंचाई दी।

रॉटरडैम में जर्मनी को 3-1 और नीदरलैंड को 3-2 से हराकर भारत ने यादगार जीत दर्ज की। मजबूत रक्षात्मक टीमों के खिलाफ चार मैचों में नौ गोल करना इस बात का प्रमाण रहा कि भारत अब केवल पेनल्टी कॉर्नर पर निर्भर नहीं है, बल्कि खुले खेल में भी लगातार गोल करने में सक्षम है।

लंदन चरण में भी भारत निर्धारित समय में अपराजित रहा। पाकिस्तान के खिलाफ दोनों मुकाबले जीतने के साथ एक मैच में 7-1 की बड़ी जीत दर्ज की। इंग्लैंड के खिलाफ दोनों मैच ड्रॉ रहे, जिनमें एक शूटआउट भारत ने अपने नाम किया। इस चरण में टीम ने चार मैचों में 13 गोल किए, जबकि विपक्षी टीमों को केवल छह गोल करने दिए।

यूरोपीय चरण में दिलप्रीत सिंह और जुगराज सिंह ने चार-चार गोल किए, जबकि अभिषेक, सुखजीत सिंह और नीलकांत शर्मा ने तीन-तीन गोल दागे। कई खिलाड़ियों का योगदान भारतीय आक्रमण की बढ़ती मजबूती और संतुलन का संकेत रहा। मुख्य कोच क्रेग फुल्टन ने कहा कि जर्मनी और नीदरलैंड जैसी टीमों पर जीत से खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ा है और टीम ने साबित किया है कि सही रणनीति के साथ वह किसी भी प्रतिद्वंद्वी को चुनौती दे सकती है। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने भी कहा कि मजबूत रक्षा, नियंत्रित मिडफील्ड और प्रभावी फॉरवर्ड लाइन ने टीम को संतुलित बनाया है, हालांकि अभी भी सुधार की गुंजाइश बनी हुई है।

अंकतालिका भले ही पूरे अभियान की तस्वीर न दिखाए, लेकिन भारतीय टीम का लगातार बेहतर होता प्रदर्शन स्पष्ट करता है कि वह बड़े टूर्नामेंटों के लिए सही दिशा में आगे बढ़ रही है।

विश्व कप में मेस्सी का 20वां गोल गोल्डन बूट की दौड़ में सबसे आगे

एजेंसी, मियामी गार्डन्स

अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेस्सी ने फीफा विश्व कप में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। केप वर्दे के खिलाफ प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबले में गोल दागकर उन्होंने विश्व कप करियर के 20 गोल पूरे कर लिए। इसके साथ ही अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय में 3-2 से जीत दर्ज कर अंतिम-16 में जगह पक्की कर ली। मेस्सी इस विश्व कप में अब तक सात गोल कर चुके हैं और गोल्डन बूट की दौड़ में सबसे आगे हैं।

मेस्सी ने मैच के 29वें मिनट में शानदार फिनिश के साथ गोल किया। हालांकि मुकाबले के दौरान उन्हें सिर पर चोट भी लगी, लेकिन मैच के बाद उन्होंने कहा कि दर्द जरूर है, लेकिन वह पूरी तरह ठीक हैं। पिछले आठ विश्व कप मुकाबलों में मेस्सी 12 गोल कर चुके हैं और उनका शानदार फॉर्म 2022 विश्व कप से लगातार जारी है। गोल्डन बूट की दौड़ में फ्रांस के काइलियान एमबाप्पे छह गोल के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि इंग्लैंड के हैरी केन और नॉर्वे के एर्लिंग हालैंड ने पांच-पांच गोल किए हैं। फ्रांस के उस्मान डेम्बेले, स्पेन के मिकेल ओयारजाबाल और ब्राजील के विनीसियस जूनियर चार-चार गोल के साथ पीछे चल रहे हैं।

मेस्सी ने अब तक अपने करियर में कभी विश्व कप का गोल्डन बूट नहीं जीता है। 2022 विश्व कप में वह सात गोल के साथ एमबाप्पे से एक गोल पीछे रहे थे। यदि इस बार गोलों की संख्या बराबर रहती है तो फीफा पहले गोल असिस्ट और फिर मैदान पर बिताए गए कम समय के आधार पर विजेता तय करेगा। फिलहाल असिस्ट के मामले में एमबाप्पे को बढ़त हासिल है, लेकिन गोलों की दौड़ में मेस्सी सबसे आगे बने हुए हैं।

स्पोर्ट्स विंडो

दीक्षा खिताब की दौड़ में चारों भारतीयों ने किया कट में प्रवेश

एजेंसी, हुलेनकोर्ट (बेल्जियम)। दीक्षा डागर खिताब की दौड़ में बनी हुई है और भारत की चारों गोल्फर ने हुलेनकोर्ट महिला ओपन के कट में प्रवेश कर लिया। दीक्षा कल रात बढत पर थी लेकिन इवन पार 72 का स्कोर करके संयुक्त तीसरे स्थान पर खिसक गई। उन्होंने तीन बर्डी लगाये लेकिन तीन बोगी भी किये। भारत की अदिति अशोक ने भी लेडीज यूरोपीय टूर पर प्रभावी वापसी करके संयुक्त आठवां स्थान हासिल कर लिया। अवनि प्रशांत संयुक्त 18वें स्थान पर है जबकि प्रणवी उर्स संयुक्त 56वें स्थान पर है। स्पेन की कैरोलिना चाकारा ने सात अंडर 65 और कुल नौ अंडर स्कोर करके बढत बना ली है।

हैरी केन रहे विश्व कप के सबसे प्रभावी खिलाड़ी: बाईचुंग भूटिया

एजेंसी, नई दिल्ली। भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान बाईचुंग भूटिया ने इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन को मौजूदा फीफा विश्व कप का अब तक का सबसे प्रभावी खिलाड़ी बताया है। उनका मानना है कि केन ने अपनी टीम की सफलता में अर्जेंटीना के लियोनेल मेस्सी और फ्रांस

के काइलियान एमबाप्पे से भी अधिक योगदान दिया है। इंग्लैंड ने ग्रुप चरण में दो जीत और एक ड्रॉ के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया और अंतिम-16 में जगह बनाई। केन ने टीम के आठ में से पांच गोल किए हैं और गोल करने वालों की सूची में मेस्सी (आठ) और एमबाप्पे (सात) के बाद तीसरे स्थान पर हैं। भूटिया ने कहा कि केन ने कठिन मुकाबलों में टीम की जिम्मेदारी उठाई और निर्णायक मौकों पर गोल किए। उनके अनुसार यदि इंग्लैंड फाइनल तक पहुंचता है तो केन गोल्डन बॉल और गोल्डन बूट दोनों पुरस्कारों के प्रबल दावेदार होंगे। उन्होंने फ्रांस, स्पेन, अर्जेंटीना और इंग्लैंड को अब तक की चार सबसे प्रभावशाली टीमें बताया तथा फ्रांस को खिताब का सबसे मजबूत दावेदार माना। सर्वकालिक महान खिलाड़ी की बहस पर भूटिया ने कहा कि उनके लिए ब्राजील के महान स्ट्राइकर रोनाल्डो, मेस्सी, रोनाल्डो, माराडोना और पेले से भी आगे हैं।

धोखाधड़ी के आरोपों पर ब्लादीमिर क्रामनिक एक साल के लिए निलंबित

एजेंसी, बिलिंग्स। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ (फिडे) ने पूर्व विश्व चैंपियन ब्लादीमिर क्रामनिक को कम से कम एक वर्ष के लिए निलंबित कर दिया है। फिडे का कहना है कि क्रामनिक ने अमेरिकी ग्रैंडमास्टर डेनियल नारोदित्स्की सहित कुछ खिलाड़ियों पर बिना पर्याप्त सबूत के सार्वजनिक रूप से धोखाधड़ी के आरोप लगाए, जो महासंघ के साइबर बुलिंग संबंधी नियमों का उल्लंघन

है। महासंघ ने स्पष्ट किया कि शतरंज में धोखाधड़ी रोकना उसकी प्राथमिकता है, लेकिन किसी भी शिकायत की जांच तय प्रक्रिया और ठोस साक्ष्यों के आधार पर ही की जानी चाहिए। क्रामनिक ने इस फैसले को अवैध बताते हुए कहा है कि वह इसके खिलाफ कानूनी चुनौती देंगे। उनका दावा है कि वह अपनी प्रतिष्ठा बहाल करने के लिए सभी उपलब्ध कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी ओर, नारोदित्स्की पहले ही इन आरोपों को खारिज कर चुके हैं। उनका कहना था कि इन आरोपों का उनके मानसिक स्वास्थ्य और खेल पर गहरा असर पड़ा। फिडे का यह फैसला खिलाड़ियों के खिलाफ बिना प्रमाण सार्वजनिक आरोप लगाने पर सख्त संदेश माना जा रहा है।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

एजेंसी, मुंबई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तबीयत अचानक बिगड़ जाने से उन्हें शुक्रवार रात ठाणे के जुपिटर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उपमुख्यमंत्री का शनिवार की सुबह से हर

तरह की वैद्यकीय जांच की जा रहा है और उनकी तबीयत स्थिर बताई जा रही है। शिवसेना शिंदे समूह के एक नेता ने बताया कि एकनाथ शिंदे की तबीयत शुक्रवार को ही थोड़ी खराब थी। कल दोपहर को जब विधानसभा का सेशन चल रहा था तभी उन्हें कमजोरी महसूस हो रही थी। 'वायरल फीवर' और कमजोरी होने की वजह से डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें औषधि दी गई थी। रात के समय आराम न होने पर शिंदे को ठाणे के जुपिटर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फिलहाल, एक्सपर्ट डॉक्टरों की एक टीम उनकी हालत पर नजर रख रही है और कहा जा रहा है कि उनकी हालत स्थिर है।

एरियास के गोल की बदौलत घाना को 1-0 से हराकर कोलंबिया अंतिम 16 मे

एजेंसी, कंसास सिटी

जोन एरियास ने शुरूआती मिनटों में लुई सुआरेस के क्रॉस पर गोल किया और इसी एक गोल के दम पर कोलंबिया ने भीषण गर्मी के बीच घाना को हराकर विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बना ली। कोलंबिया का सामना अब मंगलवार को वैंकूवर में स्विटजरलैंड से होगा। मैच शुरू होने के कुछ मिनट के भीतर ही कोलंबिया के फॉरवर्ड जोन कोरडोबा को जांघ के पीछे की मांसपेशी में चोट लग गई जिसके बाद कोच नेस्टर लोरेंजो को सुआरेज को बुलाना पड़ा। यह इंटर मियामी के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी सुआरेज नहीं बल्कि स्पोर्टिंग सीपी के लिये खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। उन्होंने आते ही अपने प्रदर्शन की छाप छोड़ी और 14वें मिनट में डेनियल मुनोज से गेंद लेकर एरियास को जबर्दस्त क्रॉस दिया जिन्होंने घाना के गोलकीपर लारेंस एटि जिगि को छकाकर गोल कर दिया।

करीब 32 डिग्री सेल्सियस तापमान में खेले गए इस मैच की शुरूआत स्थानीय समयानुसार 8.30 पर हुई। कई मैचों में विवादित रहे 'हाइड्रेशन ब्रेक' इस मैच में खिलाड़ियों के लिए वरदान साबित हुई क्योंकि पानी की कमी व थकान हो रही थी। कोलंबिया ने ग्रुप चरण में सिर्फ एक गोल गंवाया था जिसमें उसने उजबेकिस्तान और कांगो को हराने के अलावा पुर्तगाल से ड्रॉ खेला था। दो दशक में पहली बार पिछले साल अफ्रीका नेशंस कप के लिए क्वालीफाई करने में नाकाम रही घाना की टीम ने इंग्लैंड और क्रोएशिया जैसे दिग्गजों से भरे ग्रुप में रहने के बावजूद नॉकआउट में जगह बनाकर अपने आलोचकों को गलत साबित कर दिया था। कोलंबिया के खिलाफ घाना ने 8 शॉट लिए, लेकिन एक भी गोल पर नहीं था।

फीफा विश्व कप से बाहर होकर भी हीरो बना केप वर्दे

अर्जेंटीना को अतिरिक्त समय तक दी कड़ी टक्कर, संघर्ष और साहस की लिखी अविस्मरणीय गाथा

एजेंसी, मियामी

फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में हार के बावजूद केप वर्दे ने दुनिया को यह संदेश दिया कि जज्बा और आत्मविश्वास के दम पर छोटे देश भी फुटबॉल की सबसे बड़ी ताकतों को चुनौती दे सकते हैं।

महज पांच लाख से कुछ अधिक आबादी वाले अफ्रीका के पश्चिमी तट के छोटे द्वीपीय देश केप वर्दे ने विश्व चैंपियन अर्जेंटीना को अतिरिक्त समय तक कड़ी टक्कर दी। आखिरकार 111वें मिनट में डिने बोर्गेस के आत्मघाती गोल की बदौलत अर्जेंटीना ने 3-2 से जीत दर्ज की।

मैच के बाद केप वर्दे के डिफेंडर पिको लोप्स ने कहा कि उनकी टीम ने दुनिया को दिखा दिया है कि छोटे देशों के लिए भी कुछ असंभव नहीं है। उन्होंने पत्रकारों से कहा, 'हम यह दिखाना चाहते थे कि छोटे देश भी बड़े सपने देख सकते हैं। अगर दिल बड़ा हो और विश्वास मजबूत हो, तो कुछ भी संभव है। उम्मीद है कि हमारी टीम ने केप वर्दे के युवा खिलाड़ियों को प्रेरित किया होगा। हमने साबित किया है कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों के खिलाफ भी मुकाबला किया जा सकता है।

अब वर्दे को जानती है दुनिया

आयरलैंड के क्लब शैमरॉक रोवर्स से खेलने वाले पिको लोप्स ने कहा कि इस विश्व कप ने केप वर्दे को वैश्विक पहचान दिलाई है। अब किसी को यह पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि केप वर्दे कहां है। दुनिया अब हमारे देश और हमारी टीम को जानती है। हमने आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता दिखाया है।

वोजिन्हा बने विश्व कप के स्टार

40 वर्षीय गोलकीपर वोजिन्हा विश्व कप के सबसे चर्चित खिलाड़ियों में शामिल रहे। स्पेन के खिलाफ पहले मैच में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स की संख्या करीब 50 हजार से बढ़कर 1.9 करोड़ से अधिक हो गई। उन्होंने कहा, 'विश्व कप में खेलना हमारे पूरे देश का सपना था। हम अगले दौर में पहुंचना चाहते थे, लेकिन हमें अपने प्रदर्शन पर गर्व है। हमने विश्व चैंपियन के खिलाफ पूरी ताकत से मुकाबला किया और सिर ऊंचा रखकर मैदान से लौट रहे हैं।

दो बार की बराबरी, अंत तक लड़ाई

लियोनेल मेसी के शानदार गोल से पिछड़ने के बाद भी केप वर्दे ने हार नहीं मानी। डेरॉय डुआर्टे ने दूसरे हाफ में बराबरी का गोल कर मैच को अतिरिक्त समय तक पहुंचाया। इसके बाद अर्जेंटीना के लिए लिसांद्रो मार्टिनेज ने फिर बढ़त दिलाई, लेकिन सिडनी लोप्स कैब्रल के शानदार गोल ने एक बार फिर मुकाबला बराबरी पर ला दिया। आखिरकार डिने बोर्गेस का आत्मघाती गोल केप वर्दे के सपनों को तोड़ गया।

ममता को एक और झटका, बंगाल टीएमसी अध्यक्ष चंद्रिमा ने सभी पदों से दिया इस्तीफा

एजेंसी, कोलकाता

अब तृणमूल कांग्रेस की दिग्गज नेता और ममता बनर्जी की बेहद करीबी मानी जाने वालीं चंद्रिमा भट्टाचार्य ने भी शनिवार को पार्टी के राज्य अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तीन जून को ही उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन मात्र एक महीने के भीतर ही उन्होंने पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को पत्र लिखकर इस पद के साथ-साथ सभी सांगठनिक जिम्मेदारियों से खुद को मुक्त कर लिया है।

चंद्रिमा ने न केवल अध्यक्ष पद छोड़ा है, बल्कि पार्टी के बैंक खातों से जुड़े अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की भूमिका और चुनाव आयोग के समक्ष पार्टी का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी से भी अपना नाम वापस ले लिया है।

इस इस्तीफे के पीछे की मुख्य वजह उनके पुत्र सौरव बसु का हाल ही में ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले 'बागी' गुट में शामिल होना माना जा रहा है। इस्तीफे के बाद पत्रकारों से बात करते हुए चंद्रिमा ने स्पष्ट किया कि उन्हें किसी से कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनके कार्यों और निष्ठा पर सवाल उठाए गए, उसके बाद उनका बने रहना मुश्किल था।

उन्होंने कहा कि जब विश्वसनीयता ही सवालों के घेरे में हो, तो उस स्थिति में वापसी का कोई प्रश्न नहीं उठता। वहीं, ऋतब्रत बनर्जी ने इस घटनाक्रम पर कटाक्ष करते हुए तृणमूल को 'प्राइवेट लिमिटेड कंपनी' करार दिया है। ममता खेमे के लिए यह इस्तीफा एक बड़े संकट के रूप में देखा जा रहा है।

दिल्ली दंगा मामला: खालिद व शरजील इमाम की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगा मामले में आरोपित उमर खालिद और शरजील इमाम की नई जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत आज ही इस पर आदेश सुना सकती है। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व आदेशों और हाल के फैसलों का हवाला देते हुए अपने-अपने तर्क रखे। उमर खालिद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पेस ने कहा कि हालिया सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने पहले की जमानत अस्वीकृति पर सवाल उठाए हैं और अब एक वर्ष बाद नई जमानत याचिका दाखिल करने की शर्त लागू नहीं होती। वहीं शरजील इमाम के वकील तालिब मुस्तफा ने दलील दी कि समान मामलों में कई सह-आरोपितों को जमानत मिल चुकी है, जबकि मुकदमे की सुनवाई में भी कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ कोई नया निर्देश नहीं देती, तब तक पूर्व आदेश प्रभावी रहेगा और ट्रायल कोर्ट उसमें बदलाव नहीं कर सकती। मामले में यूएपीए के तहत 18 आरोपितों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है।

उपराष्ट्रपति ने जमा किया मतदाता सूची पुनरीक्षण का गणना फॉर्म, नागरिकों से सहयोग की अपील

एजेंसी, नई दिल्ली

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने शनिवार को उपराष्ट्रपति भवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन-एसआईआर) अभियान के तहत विधिवत भरा हुआ गणना फॉर्म जमा किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हुए चुनाव आयोग का सहयोग करने की अपील की।

उपराष्ट्रपति सचिवालय के अनुसार, दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के नेतृत्व में जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) तथा बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) की टीम ने उपराष्ट्रपति भवन पहुंचकर गणना प्रक्रिया पूरी कराई। यह अभियान दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का हिस्सा है। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने भी सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर

जारी वीडियो संदेश में कहा कि चुनाव आयोग की यह पहल लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य लोकतंत्र को कमजोर करना नहीं, बल्कि मतदाता सूची को अधिक सटीक, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना है।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक वास्तविक और पात्र मतदाता का मतदाता सूची में पंजीकरण होना चाहिए। साथ ही, एक ही व्यक्ति के नाम का एक से अधिक स्थानों पर दर्ज होना (डबल एंट्री) समाप्त किया जाना आवश्यक है। जिन मतदाताओं का निधन हो चुका है, उनके नाम भी मतदाता सूची से हटाए जाने चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत जैसे सशक्त लोकतंत्र में निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनावों के लिए सटीक मतदाता सूची अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी नागरिकों से चुनाव आयोग के साथ समन्वय और सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रत्येक पात्र नागरिक को अपना पंजीकरण सुनिश्चित करने का अधिकार है। इसके लिए आवश्यक प्रपत्रों को सही ढंग से भरकर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ हो सके।

फिल्मों व ओटीटी कंटेंट की पायरेसी पर तुरंत रोक लगाए टेलीग्राम, केंद्र सरकार ने 15 दिन में मांगी एक्शन रिपोर्ट

एजेंसी, नई दिल्ली

सरकार ने बड़े पैमाने पर हो रही पायरेसी को लेकर टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीग्राम को निर्देश दिया है कि वह पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तुरंत कदम उठाए और 15 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपे। सूत्रों के मुताबिक, सरकार का यह कदम भारत की क्रिएटर इकॉनमी, फिल्म इंडस्ट्री, ब्रॉडकास्टर्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म, प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की सुरक्षा के लिए है। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार का नजरिया अब पायरेटेड कंटेंट को एक-एक करके हटाने के बजाय प्लेटफॉर्म की जवाबदेही तय करने की ओर बढ़ रहा है।

पता चला है कि मंत्रालय ने टेलीग्राम से कहा है कि कॉपीराइट का उल्लंघन सिर्फ एक सिविल उल्लंघन नहीं है, बल्कि कॉपीराइट एक्ट, 1957 और सिनेमैटोग्राफ एक्ट, 1952 के तहत एक आपराधिक अपराध भी है। टेलीग्राम को नीट की दोबारा परीक्षा के दौरान पेपर लीक को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर जून में भारत में कुछ समय के लिए ब्लॉक किया गया था।

अधिकारियों ने कहा, 'मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि टेलीग्राम सिर्फ इस बात का इंतजार नहीं कर सकता कि सरकार एक-एक करके हर पायरेसी चैनल की पहचान करे। सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला और एक-एक करके चैनल हटाने का तरीका आईटी एक्ट, 2000 और आईटी नियम, 2021 के तहत जरूरी सावधानी बरतने (ड्यू डिलिजेंस) को साबित करने के लिए काफी नहीं हो सकता है।' एक अधिकारी ने आगे कहा कि सरकार ने साफ कर दिया है कि पायरेटेड कंटेंट का लगातार उपलब्ध रहना, नियमों का ठीक से पालन न करना या अधूरा जवाब देने पर लागू कानूनी ढांचे के तहत और जांच और कार्रवाई हो सकती है। यह कार्रवाई भारत की क्रिएटर इकोनॉमी, फिल्म इंडस्ट्री, ब्रॉडकास्टर्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म, प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की सुरक्षा के लिए की गई है।

केंद्र सरकार ने मेटा को भी जारी किया था नोटिस

टेलीग्राम को यह नोटिस केंद्र सरकार द्वारा मेटा के खिलाफ हाल ही में की गई रेगुलेटरी कार्रवाई के बाद भेजा गया है। बुधवार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने मेटा को नोटिस जारी करके व्हाट्सऐप पर आने वाले यूजरनेम फीचर के बारे में सवाल पूछा और बाद में उसी हफ्ते बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों को लेकर कंपनी को तलब करने का फैसला किया।

शिकायत निवारण तंत्र के बारे में मांगी जानकारी

सूत्रों ने बताया कि इस बीच, मंत्रालय ने प्रोड्यूसर्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए टेलीग्राम के शिकायत निवारण तंत्र के बारे में भी जानकारी मांगी है। उन्होंने आगे कहा कि टेलीग्राम को याद दिलाया गया है कि एक मध्यस्थ के तौर पर उसे आईटी एक्ट और आईटी नियमों के तहत जरूरी सावधानी बरतनी होगी।

परिसीमन और 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' पर संसद में घेराव की तैयारी

मानसून सत्र में विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरेगा इंडिया गठबंधन : कांग्रेस

एजेंसी, नई दिल्ली

कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर जनविरोधी कदम उठा रही है लेकिन विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन संसद के मानसून सत्र में जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगा तथा उससे जवाब मांगेगा। कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने शनिवार को यहां एक बयान में कहा कि इंडिया गठबंधन संसद में सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस तथा गठबंधन को केवल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से ही नहीं, बल्कि भाजपा और चुनाव आयोग के गठजोड़ से भी

मुकाबला करना पड़ रहा है।

उनका कहना था कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर द्रमुक (द्रमुक), आम आदमी पार्टी सहित 24 विपक्षी दलों तथा निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को संयुक्त पत्र लिखा है। उनका आरोप था कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं, जिससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि चुनाव परिणाम पहले से तय होने की धारणा बन जाए तो लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया का महत्व ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि उच्चतम न्यायालय चुनाव आयोग को निष्पक्ष ढंग से काम करने का निर्देश देगा।

श्री रमेश ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव में दो-तिहाई बहुमत नहीं मिलने के बाद भाजपा बदले की राजनीति कर रही है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी भविष्य में दो-तिहाई बहुमत हासिल कर संविधान में बदलाव करना चाहती है तथा सामाजिक न्याय और आरक्षण व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास कर रही है।